सुविचार

जो व्यक्ति शांत और प्रसन्न स्वभाव का होता है, उसे उम्र का दबाव शायद ही महसूस होता है।

-प्लेटो

Daily

THE PHOTON NEWS

सच के हक में...

द फोटोन न्यूज़ Published from Ranchi

12

Shraddha Kapoor Spills The Beans...

Ranchi • Thursday, 12 December 2024 • Year : 02 • Issue : 319 • Ranchi Edition • Page : 12 • Price : ₹3 • www.thephotonnews.com

E-Paper : epaper.thephotonnews.com

SHARE

सेंसेक्स	:	81,526.14
निफ्टी	:	24,641.80

SARAFA

सोना	:	7,455
चांदी	:	103.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

संजय मल्होत्रा बने आरबीआई के नए गवर्नर

MUMBAI : बुधवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के 26 में गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा ने जिम्मेदारी संभाल ली। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक नीतिगत मोर्चे पर स्थिरता को बनाए रखेगा। मौजूदा वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक माहौल को देखते हुए हमें सतर्क और सजग रहने की जरूरत है।

बांग्लादेश की सीमा पर भारत ने बढ़ाई सुरक्षा

NEW DELHI : बुधवार को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने भारत के त्रिपुरा बॉर्डर तक लॉन्ग मार्च निकाला। इस लॉन्ग मार्च को त्रिपुरा चली अभियान नया दिया गया है। बुधवार को सुबह 9 बजे ढाका के नयापल्टन से इसकी शुरूआत की गई। भारत ने हालात देखते हुए सुबह से ही क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। पश्चिमी त्रिपुरा जिले के एसपी किरण कुमार ने सुबह बॉर्डर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों को जीरो पॉइंट से पहले ही रोक दिया गया।

वायुसेना के जवान ने ड्यूटी के दौरान किया सुसाइड

NAGPUR : वायुसेना के एक सार्जेंट ने ड्यूटी के दौरान कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। गिट्टिखदान थाने के एक अधिकारी ने बताया कि हरियाणा में भिवानी के रहने वाले जयवीर सिंह (36) ने मंगलवार देर रात करीब दो बजे अपनी सर्विस बंदूक से खुद को गोली मार ली।

सुखी, समृद्ध एवं उन्नत झारखंड बनाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे विधायक

गवर्नर ने हेमंत सरकार का बताया रोड मैप

केंद्र सरकार से 1 लाख 36 हजार करोड़ लेने की कानूनी लड़ाई लड़ेगी सरकार

PHOTON NEWS RANCHI : बुधवार को विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण में हेमंत सोरेन सरकार का रोडमैप प्रदेश के लोगों के सामने रखा। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य के सभी नवनिर्वाचित विधायक सुखी, समृद्ध एवं उन्नत झारखंड के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। बता दें कि झामुमो ने विधानसभा चुनाव में जारी किए गए घोषणा पत्र में वादा किया था कि जब वह सत्ता में आएगी तो महिलाओं को राज्य सरकार की हर नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण देगी। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि केंद्र और उनकी कंपनियों के बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये हासिल करने के लिए झारखंड सरकार कानूनी रास्ता देखेगी। राज्यपाल ने कहा कि इसमें 95000 सरकारी पदों पर जल्द बहाली की बात कही गई। अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि 60 हजार शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। 15 हजार प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। 10 हजार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति का भी एलान किया। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को सुदृढ़ करने के लिए 10 हजार भाषा शिक्षकों को नौकरी देगी।

राज्य के सभी पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन का अधिकार किया जाएगा सुनिश्चित

सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, 95000 खाली सरकारी पदों को शीघ्र भरेगी सरकार

- सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों की लड़ाई लड़ेगी झारखंड सरकार
- किसानों को बिना ब्याज कृषि ऋण मुहैया करने का किया जाएगा इंतजाम
- नदियों एवं डैम के पानी के सदुपयोग के लिए शुरू होंगी 10 हजार करोड़ की योजनाएं
- राज्य में खोले जाएंगे 4500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय, हर प्रखंड में खुलेगा डिग्री कॉलेज
- केजी से पीजी तक नि:शुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करेगी सरकार

विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन अभिभाषण पढ़ते राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार।

- जेएसएलपीएस के सभी कर्मियों के मानदेय में किया जाएगा इजाफा
- आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन बच्चों को दिया जाएगा अंडा या फल
- शहरी क्षेत्रों में वर्षों पुराने बने घरों के नक्शे का किया जाएगा नियमितीकरण
- नई पेंशन योजना के तहत जमा पैसे को केंद्र सरकार से वापस लेकर कर्मियों के पेंशन खाते में करवाया जाएगा जमा
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों की सरकारी पदों पर की जाएगी नियुक्ति
- जिला मुख्यालयों में कराया जाएगा बहूद्देशीय स्टेडियम का निर्माण

अभिभाषण की अन्य प्रमुख बातें

- सभी महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के तहत हर महीने मिलेंगे ₹2500
- अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से लोगों को तेजी से जोड़ने का होगा काम
- गरीबों को हर माह 7 किलो चावल और 2 किलो दाल सरकार की ओर से दिया जाएगा
- झारखंड में मदरसा बोर्ड का किया जाएगा गठन
- स्वयंसहायता समूह से जुड़ीं महिलाओं के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे स्वरोजगार के अवसर
- ग्राम संगठन को बिना ब्याज उपलब्ध कराया जाएगा 15 लाख का क्रेडिट लिंकेज
- चरणबद्ध तरीके से अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा 3 कमरों का सुंदर आवास
- राज्यकर्मियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को सुरक्षित रखेगी सरकार

आदिवासियों को 28, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 व अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत आरक्षण, सरना धर्मकोड का प्रस्ताव पास

राज्यपाल ने कहा कि पंचम विधानसभा में सरकार ने आदिवासियों को 28 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत आरक्षण देने के अलावा सरना धर्मकोड का प्रस्ताव पास किया था। ये सभी प्रस्ताव अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित हैं। सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन प्रस्तावों को जल्द मंजूरी दिलाने का प्रयास करेगी। राज्यपाल ने कहा कि सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों की लड़ाई झारखंड सरकार लड़ेगी। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सड़क से लेकर संसद तक। जब तक सभी निवेशकों को उनका पैसा नहीं मिल जाएगा, सरकार उनकी लड़ाई लड़ती रहेगी।

किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण

राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों को केंद्र की ओर से बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है। उनकी सरकार अपनी तरफ से मनरेगा मजदूरों के लिए पैसे की व्यवस्था करेगी, ताकि उन्हें न्यूनतम 350 रुपये मजदूरी मिल सके। नदियों एवं डैम के पानी के सदुपयोग के लिए 10 हजार करोड़ की योजनाएं झारखंड में शुरू की जाएगी।

खुलेंगे 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस

राज्यपाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में झारखंड में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इन स्कूलों में स्वास्थ्य और संगीत के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय भी खोले जाएंगे। इतना ही नहीं, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। अनुमंडल स्तर पर पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर लाइब्रेरी की भी स्थापना का ऐलान राज्यपाल ने किया। उन्होंने कहा कि केजी से पीजी तक नि:शुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था सरकार करेगी। अपने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने झारखंड सरकार द्वारा पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों की भी चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने आदिवासियों को 28 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण और अल्पसंख्यकों को 12 प्रतिशत आरक्षण दिया है।

नियुक्ति संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

जेपीएससी अध्यक्ष की शीघ्र नियुक्ति का निर्देश

PHOTON NEWS RANCHI : बुधवार को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस एसएन पाठक की बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि 22 अगस्त के बाद से ही आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा हुआ है। इससे कई परीक्षाओं का परिणाम और प्रक्रिया बाधित है। इस मामले को लेकर एक अभ्यर्थी की ओर से एक रिट याचिका दाखिल की गई थी। पहली ही सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।

पॉलिसी से जुड़ा मामला : कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, फिर भी एक अध्यक्ष की नियुक्ति में इतनी देर आखिर क्यों हो रही है। डीजीपी और अन्य पद तुरंत भर लिए जा रहे हैं।

- जस्टिस एसएन पाठक की बेंच में हुई सुनवाई
- 22 अगस्त के बाद से ही आयोग के अध्यक्ष का पद है खाली
- कई परीक्षाओं का परिणाम और प्रक्रिया बाधित

2035 तक भारत स्थापित कर लेगा अपना स्पेस स्टेशन

NEW DELHI : केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर लेगा। इसे भारत अंतरिक्ष स्टेशन नाम दिया जाएगा। इसके साथ ही, 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजने की योजना है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉ. सिंह ने बताया कि 2025 के अंत तक या 2026 की शुरूआत में, गगनयान मिशन के तहत पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएगा। साथ ही भारत अपने गहरे समुद्र मिशन के तहत 6,000 मीटर की गहराई में मानव को भेजने की योजना बना रहा है।

झामुमो केंद्रीय समिति की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने की शिरकत

हमने लड़कर जीत हासिल की कभी हार नहीं मानी : हेमंत सोरेन

PHOTON NEWS RANCHI : बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झामुमो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में शामिल हुए। बैठक का आयोजन विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा करने के उद्देश्य से हुई। मौके पर झामुमो के सभी विधायक समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। पार्टी को दूसरे राज्यों में कैसे मजबूत बनाना है, इसे लेकर मंथन हुआ। सीएम हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनका आभार जताते हुए आगे के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष से उपजी पार्टी है। इसी वजह से हमने हमेशा हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है। हमने लड़कर जीत हासिल की, कभी भी हार नहीं मानी।

कार्यकर्ताओं को दिया टास्क, झामुमो परिवार की जड़ों को राज्य के कोने-कोने तक पहुंचाने का किया आह्वान

- पार्टी को दूसरे राज्यों में मजबूत बनाने को लेकर हुआ मंथन
- सीएम बोले- झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष से उपजी पार्टी
- राज्यवासियों के आशीर्वाद से मजबूत अबुआ सरकार का हुआ गठन

हक-अधिकार देने का करना है काम

सीएम ने कहा कि विगत विधानसभा चुनाव में आप सभी कर्मठ नेताओं और जुझारू कार्यकताओं की कड़ी मेहनत और करोड़ों राज्यवासियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप झारखंड में मजबूत अबुआ सरकार का गठन हुआ। आप सभी को इसके लिए हार्दिक बधाई और जोहार। झवंचित, शोषित समेत समाज के सभी वर्ग को हक-अधिकार देने का काम करना है। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मीडिया से कहा कि यह बैठक कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए बुलाई गई थी। इसमें जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के कार्यकर्ता शामिल हुए।

राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला- हम नहीं छोड़ेंगे गौतम अडानी पर चर्चा

AGENCY NEW DELHI : बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 12वां दिन था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम गौतम अडानी मुद्दे पर चर्चा नहीं छोड़ेंगे। राहुल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की और कार्यवाही से अपमानजनक बातें हटाने का अनुरोध किया। राहुल ने कहा- हमारा मकसद है कि संसद चले, सदन में चर्चा हो। वे (सत्ता पक्ष) मुझे क्या कहते हैं, ये मायने नहीं रखता। हम चाहते हैं कि 13 दिसंबर को संविधान पर चर्चा हो। इधर, राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा हुआ। राज्यसभा पहले 12 बजे तक, फिर 12 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई।

- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात
- कार्यवाही से उनके खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने का किया अनुरोध
- भाजपा अध्यक्ष नड्डा बोले- कांग्रेस बताए सोनिया-सोरोस का रिश्ता

मुद्दे को भटकाने की कोशिश करती है कांग्रेस

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि दो दिन से हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी का क्या संबंध है। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है। यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नचिह्न है। हम सोरोस पर इसलिए बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम आम आदमी के लिए प्रतिबद्ध हैं। चेयर पर आरोप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। यह मुद्दे को भटकाने के लिए कुत्सित प्रयास है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 72 साल बाद किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना। ऐसा सभापति मिलना मुश्किल है। विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई है। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के बीच रिश्ता क्या है, उन्हें ये बताना चाहिए। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी

प्रियंका बोलीं- रोज सदन स्थगित करा रही सरकार

प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बाहर कर रहे हैं। हम रोज कोशिश करते हैं, लेकिन वे (सरकार) चर्चा नहीं चाहते। रोज किसी न किसी बहाने सदन को स्थगित करा रहे हैं।

भविष्य की सुरक्षा पानी की बर्बादी के प्रति जागरूकता ही एकमात्र उपाय

जल को कल के लिए भी बचाकर रखने का काम अहम

AGENCY NEW DELHI : जल जीवन के लिए प्रकृति का अनमोल उपहार है। जीवन का मतलब सिर्फ मानव जीवन ही नहीं, बल्कि सभी जीवों का जीवन। यदि शरीर की जैविक आवश्यकता के अनुसार, जलीय जीवों को भी पानी न मिले तो वे अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। जो जीव जालीय नहीं है, उन्हें तो हर हाल में जैविक क्रियाओं के लिए जल पर ही आधारित रहना पड़ता है। मानव जीवन के लिए भी यह स्थिति समान है। जल बनने की प्राकृतिक प्रक्रिया यदि मानव गतिविधियों से प्रभावित होती है, तो उसका असर समग्र जैव संतुलन पर नकारात्मक रूप में पड़ता है। जल की आवश्यकता आज जितनी है, कल उसकी आवश्यकता बढ़ेगी। अत: कल के लिए अगर हमने जल को बचाने के काम को अहमियत नहीं दी, तो आज के साथ-साथ कल भी प्रभावित होगा। कल यानी भविष्य की पीढ़ी। आज के समय में यह देश के लिए सुखद स्थिति कहीं जा सकती है कि हमारे प्रमुख जलाशयों में वर्तमान जल संग्रहण 145.416 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है।

गुजरे 10 सालों के औसत से लगभग 117 फीसद अधिक है अभी का संग्रहण

केंद्रीय जल आयोग की अपडेट रिपोर्ट में 155 जलाशयों की दी गई है जानकारी

यह सुखद है कि देश के प्रमुख जलाशयों में बीते साल की अपेक्षा अधिक पानी मौजूद

वर्तमान में 145.416 बिलियन क्यूबिक मीटर है जल संग्रहण	उत्तर क्षेत्र के जलाशयों में पिछले साल की तुलना में कम है पानी	कृषि, औद्योगिक व पेयजल जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये जलाशय

अभी लबालब हैं पश्चिम के जलाशय

रिपोर्ट बताती है कि देश के पश्चिमी क्षेत्र (गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र) में जलस्तर सबसे ज्यादा है, जो कुल क्षमता का 91 फीसद है। यह पिछले साल के 79 फीसद और 10 साल के औसत 71 फीसद के स्तर से काफी बेहतर है। मध्य क्षेत्र के हालात भी सुधरे हैं। दक्षिण में राहत स्थित है। मध्य क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र में जलस्तर 83 फीसद है। उत्तरी क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान) में जल स्तर केवल 56 फीसद है। यह पिछले साल के 69 फीसद और 10 साल के औसत से कम है।

80 प्रतिशत है जल संग्रहण क्षमता

देश के 155 प्रमुख जलाशयों के जल संग्रहण की कुल क्षमता 180.852 बीसीएम है, जो भारत के कुल जल भंडारण का 70.15 फीसदी है। मौजूदा समय में ये जलाशय अपनी कुल जल संग्रहण क्षमता के 80 फीसद पर हैं। यह बीते साल और 10 साल के औसत दोनों के मुकाबले अहम सुधार है। सीडब्ल्यूसी के अनुसार, ये जलाशय देश में कृषि, औद्योगिक और पेयजल जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के नवीनतम बुलेटिन में यह खुलासा हुआ है।

सीरिया में फंसे 75 भारतीय नागरिकों को सरकार ने निकाला

NEW DELHI : भारत सरकार ने सीरिया में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद 75 भारतीय नागरिकों को वहां से निकाला। इनमें जम्मू और कश्मीर के 44 'जायरीन' शामिल थे, जो सैदा जैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं और वे उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से भारत लौटेंगे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि सीरिया में सुरक्षा स्थिति के हमारे आकलन और भारतीय नागरिकों के अनुरोध के बाद दमिश्क और बेरूत स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा समन्वित निकासी की प्रक्रिया शुरू की गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली

नमिता देवी हत्याकांड में शामिल रहा है घायल सद्दाम कुरैशी

AGENCY PALAMU : जिला मुख्यालय मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के कोयल नदी किनारे कसाब मोहल्ला में बाइक सवार अपराधियों ने बुधवार को सद्दाम कुरैशी (30) को गोली मार दी। युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसे बांह में गोली लगी है। गोली मारने वाले अपराधियों की संख्या दो बताया जा रहा है। दोनों बाइक से पहुंचे थे। जख्मी युवक मेदिनीनगर की शास्त्री नगर निवासी नमिता देवी मर्डर केस में जेल जा चुका है। सद्दीक चौक से सटे एक दुकान में दिनदहाड़े नमिता देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस हर एक एंगल पर जांच में जुटी हुई है। अपराधियों की

अस्पताल में इलाजरत सद्दाम कुरैशी व बाहर बैठे परिजन • फोटोन न्यूज

पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। जख्मी युवक की पत्नी नजराना बीवी ने निजी अस्पताल में बताया कि उसके सोहर सद्दाम कुरेशी नौ माह के बच्चे की देखभाल कर रहे थे। घर के बाहर धूप में खड़े थे। मैं कमरे में अंदर मोजा लेने अंदर गयी थी। इसी क्रम में मोटरसाइकिल से दो युवक पहुंचे और गोली चलाकर भाग निकले। महिला ने बताया कि घटना को मिंटू रंगसाज और साबिर रंगसाज ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। दोनों गढ़वा के रहने वाले हैं। दोनों छोटू रंगसाज मर्डर केस में शामिल थे। छोटू की हत्या रांची में दिनदहाड़े कर दी गई थी। नजराना ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करके आरोपियों की पहचान करने और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इधर, गोली लगने के बाद जख्मी हालत में सद्दाम को इलाज के लिए एमआरएमसीएच में भर्ती कराया गया।

कोडरमा में अवैध माइका खनन रोकने के लिए छापेमारी

KODERMA : वन विभाग की टीम और कोडरमा पुलिस ने छापेमारी कर तीन शक्तिमान, एक जेसीबी जब्त किया है। जंगल के इंदरवा चितरपुर स्थित लोमचाची जंगल मे अवैध माइका खनन को लेकर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने अवैध खनन में लगे एक जेसीबी मशीन, तीन शक्तिमान जब्त किया है। रेंजर रामबाबू ने बुधवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर लोमचाची जंगल में छापेमारी की गयी। अंधेरे का लाभ देखकर चालक फरार हो गये। इस मामले में अवैध उत्खनन में लगे लोगों को चिन्हित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि उनलोगों के ऊपर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। जब्त वाहनों को कोडरमा वन विभाग परिसर में जब्त कर रखा गया है। मौके पर वनपाल प्रभारी उस्मान अंसारी, छत्रपति शिवाजी, दुर्गा माहतो गोपाल यादव के अलावे पुलिस बल के जवान मौजूद थे।

स्कूल से घर जा रही छात्रा का करकट से कटा गला, रेफर

AGENCY PALAMU : राजकीय मध्य विद्यालय तरहसी से छुट्टी के बाद घर लौट रही वर्ग छह की छात्रा सौम्या कुमारी का करकट से गला कट गया। गंभीर अवस्था में उसे उपस्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए एमआरएमसीएच मेदिनीनगर रेफर कर दिया है। छात्रा सौम्या अपने मामा के घर तरहसी में रहकर पढ़ाई करती थी। छात्रा के पिता का कृष्णा तिवारी है।

मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को स्कूल से छुट्टी होने पर छात्रा सौम्या अपनी सहपाठियों के साथ घर जा रही थी। रास्ते में पड़ने वाले शिव शक्ति इंटरप्राइजेज में दुकानदार शिवकुमार साव सड़क पर करकट लोड कर रहा था। बिना किसी सुरक्षा उपाय के खुले में करकट लोड किया जा रहा था। दुकानदार की लापरवाही के कारण एक साथ कई करकट

एंबुलेंस में घायल को ले जाते परिजन • फोटोन न्यूज

गाड़ी से गिरने लगे। इसी क्रम में छात्रा की दिशा में लुढकते हुए एक करकट से अचानक उसका गला कट गया। इस दृश्य को देखकर आसपास के लोग हैरान हो गए और तुरंत स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित किया। छात्रा को गंभीर अवस्था में उपस्वास्थ्य केंद्र तरहसी भेजा गया। इस घटना को लेकर परिजन एवं स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। तरहसी भाजपा मंडल महामंत्री अनिल सिंह ने इस लापरवाही पर दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दुर्घटना के बाद से लोग सड़क पर दुकानदारों के जरिये सामान लोड करते वक्त सुरक्षा उपायों की कमी पर चिंता जता रहे हैं।

यह हादसा इस बात की ओर इशारा करता है कि सड़क पर व्यापारियों और दुकानदारों को सामान लोड करते समय अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि घटना की पुनरावृति ना हो सके।

BRIEF NEWS

नहीं रहे भाजपा नेता मुनीनाथ मिश्रा

KHUNTI : जनसंघ काल के वयोवृद्ध भाजपा नेता और पद्मभूषण कड़िया मुंडा के निकटतम सहयोगी मुनीनाथ मिश्रा (82) का मंगलवार की देर

रात निधन हो गया। वे पिछले कुछ माह से बीमार थे। रात को लगभग एक बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मुनीनाथ मिश्रा बाबा आम्रेश्वर धाम प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष भी थे। मुनीनाथ मिश्रा लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा के राजनीतिज्ञ सलाहकार के रूप में जाने जाते थे। कुछ महीनों पूर्व उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। कुछ दिनों के बाद वे खूंटी आ गये थे, लेकिन घर पर ही रहते थे। मुनीनाथ मिश्रा के निधन पर पद्मभूषण कड़िया मुंडा, सांसद कालीचरण मुंडा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, पूर्व विधायक कोचे मुंडा सहित कई नेताओं और सामजिक कार्यकताओं ने मुनीलनाथ मिश्रा के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की।

नगरपालिका चुनाव की सरगर्मी तेज

DHANBAD : धनबाद में नगरपालिका चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसके निमित्त पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने की पात्रता निर्धारण के लिए बुधवार को उपायुक्त माधवी मिश्रा ने प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारियों को वार्डवार प्रगणक का गठन कर सर्वे शुरू करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि धनबाद नगर निगम एवं चिरकुंडा नगर परिषद में अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के संबंध में वार्डवार सूचना अद्यतन मतदाता सूची के आधार पर निर्धारित प्रपत्र-1 से 3 में एवं पिछड़े वर्गों की राजनीतिक स्थिति की जानकारी के लिए अनारक्षित वर्ग के विरुद्ध चुने गए अत्यंत पिछड़ा वर्ग-पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों की सूचना पिछले दो निर्वाचन के आधार पर निर्धारित प्रपत्र-4 व 5 से प्राप्त कर 31 दिसंबर से पहले पूरा करें। बैठक में नगर आयुक्त रवि राज शर्मा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुकेश कुमार बाउरी, चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी तथा सभी बीडीओ-सीओ मौजूद थे।

बिना परमिशन होर्डिंग लगाने पर कार्रवाई : डीसी

RAMGARH : रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र और छावनी परिषद क्षेत्र का विलय होना लगभग तय हो गया है। इन दोनों क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य भी हो रहे हैं। लेकिन ऑरेंज मीडिया इन क्षेत्रों में बिना अनुमति के अपना प्रचार होर्डिंग और बैनर लगाकर कर रही है। इन क्षेत्रों में बिना अनुमति के प्रचार करने वालों पर कार्रवाई होगी। यह निर्देश बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान डीसी चंदन कुमार ने दिया। नगर परिषद क्षेत्र में बिना अनुमति के होर्डिंग लगाए जाने संबंधित मामले में ऑरेंज मीडिया एजेंसी के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज की गई है। डीसी चंदन कुमार ने बैठक में पूर्व में दिए गए निदेशों के आलोक में हुए कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मनीष कुमार के जरिये अन्य विकास कार्यों के संबंध में डीसी, डीडीसी सहित बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारियों को जानकारी दी गई। शहरी जलापूर्ति योजना के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में पतरातू डैम परिसर में सम्प हाउस निर्माण, चैंगड्डा तथा बंजारी में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करने के लिए तत्काल रूप से भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया।

पतरातू में सभी गिरोह पर कसी जाएगी नकेल, एसपी ने थानेदारों को दिए निर्देश

क्राइम मीटिंग में अपराधों की समीक्षा में कहा-हवाई फायरिंग भी गंभीर

AGENCY RAMGARH : त्योहार और चुनाव के बाद रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बुधवार को क्राइम मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एसपी के तल्ख तेवर देख सभी थाना प्रभारी भी अलर्ट मोड में आ गए हैं। एसपी ने थाना प्रभारियों को आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हर हाल में आपराधिक गिरोह पर नकेल कसना होगा। किसी भी सूरत में वैसे अपराधी बचने नहीं चाहिए जो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हवाई फायरिंग कर रहे हैं। संगठित अपराध के खिलाफ

पुलिस पदाधिकारियों की बैठक करते एसपी अजय कुमार • फोटोन न्यूज

अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सभी इलाकों में सघन छापेमारी होगी। एसपी अजय कुमार ने बताया कि चुनाव के बावजूद कई मामलों का निष्पादन हुआ है, जो कि सक्रिय पुलिसिंग का संकेत है। कई अपराधी जेल से छूटने के बाद किन गतिविधियों में शामिल हैं इस पर नजर रखना भी बेहद जरूरी है। इसलिए थाना प्रभारी को अलर्ट रहने और लगातार छापेमारी करते रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि रामगढ़ जिले में कई घाटी हैं जिसमें अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। चुटूपालू घाटी के अलावा पतरातु वैली और गोला क्षेत्र में भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं। वाहन दुर्घटनाएं कैसे काम हो इसके लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। क्राइम मीटिंग में रजरप्पा थाना सबसे अधिक पासपोर्ट वेरीफिकेशन पेंडिंग रखने के मामले में चर्चित रहा। एसपी अजय कुमार ने बताया कि उन्हें तत्काल सारे पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा पोस्को एक्ट और महिलाओं के साथ हुए हादसों का निष्पादन 2 महीने के अंदर करने का निर्देश भी जारी किया गया है। एसपी अजय कुमार ने बताया कि नए साल की शुरूआत होने वाली है और पिकनिक का माहौल अभी से ही बन गया है। पतरातु डैम और रजरप्पा क्षेत्र में लोगों का जमावड़ा भी लग रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में हुड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मध्याह्न भोजन लेते उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता • फोटोन न्यूज

डीसी ने किया मनिका के स्कूलों का निरीक्षण, चखा मिड डे मील

LATEHAR : उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने बुधवार को मनिका प्रखंड का दौरा किया, जिसमें उन्होंने डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने पठन-पाठन व छात्रों को मिल रही मूलभूत सुविधाओं एवं विधि-व्यवस्था का जायजा लिया। इसी क्रम में वे आदिम जनजाति आवासीय बालक प्राथमिक विद्यालय, औराटांड़ भी गए, जहां बच्चों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं व व्यवस्था का अवलोकन किया। यहां उन्होंने मिड डे मील भी चखा, जिससे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का पता चल सके। इसके अलावा उपायुक्त सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, राजकीय मध्य विद्यालय,शिंजो, कस्तूरबा गांधी मनिका आदि भी गए। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्य कर रहे चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों व सफाई कर्मियों की स्थिति की जानकारी ली। डिस्पेंसरी का निरीक्षण कर दवा की उपलब्धता की वस्तुस्थिति से अवगत हुए।

लोस में उठाया गया मंडल डैम निर्माण का मामला

PALAMU : सांसद विष्णु दयाल राम ने बुधवार को लोकसभा में शून्य काल के दौरान उत्तरी कोयल जलाशय (मंडल डैम) निर्माण कार्य से संबंधित मामले को उठाया। सांसद ने कहा कि लातेहार जिला में उत्तरी कोयल जलाशय (मंडल डैम) परियोजना स्थित है। इस परियोजना में पलामू प्रमंडल के तीनों जिले पलामू, गढ़वा एवं लातेहार और बिहार राज्य के गया एवं औरंगाबाद जिलों के लगभग 1,11,521 हेक्टेयर सूखाग्रस्त भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराने, लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उद्योग धंधों की जरूरत की परिकल्पना है।

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार बनने पर 1622.27 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना के

सांसद बीडी राम

पुनर्निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

परियोजना का कार्य वाप्कोस लिमिटेड कंपनी को मिला। प्रधानमंत्री ने पांच जनवरी 2019 को इस परियोजना के निर्माण की अधारशिला पलामू में आकर रखी। प्रधानमंत्री के जरिये शिलान्यास करने के बाद पलामू प्रमण्डल के साथ-साथ बिहार के औरंगाबाद एवं गया जिले की जनता के मन में मंडल डैम परियोजना के निर्माण कार्य फिर से शुरू होने की आशा जगी।

नहाने गया युवक तालाब मे डूबा, तलाश जारी

GIRIDIH : जिले के सरिया थाना क्षेत्र के बलीडीह गांव में नहाने के दौरान एक युवक तालाब में डूबने का मामला बुधवार को प्रकाश में आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक को तालाब से निकालने की कोशिश की गई लेकिन उसका पता नहीं चला है तालाब में डूबे युवक का नाम मोहित राणा बताया जा रहा है। मोहित सुभाष राणा का पुत्र है और कोडरमा जिले का रहने वाला है। इन दिनों वह अपने मामा के घर बलीडीह आया हुआ था। मंगलवार शाम में गांव के तालाब में नहाने गया था। घटना के बाद काफी संख्या में स्थानीय लोग जुटे। जानकारी मिलने के बाद एसडीएम संतोष गुप्ता, एसडीपीओ धनंजय राम के साथ सरिया थाना प्रभारी और बीडीओ भी तालाब पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने युवक को काफी ढूंढने की कोशिश की लेकिन युवक का कुछ नहीं पता चल सका।

बस ने बाइक में मारी टक्कर युवक की हुई मौत, एक घायल

AGENCY KHUNTI : खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर तोरपा थाना क्षेत्र के ओरमेंजा गांव के पास बुधवार को यात्री बस और बाइक की हुई सीधी टक्कर में ज्योतिष होरो (22) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि आलोक टोपनो नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक रनिया थाना क्षेत्र के गरई डिगरी गांव का रहनेवाला था, जबकि घायल आलोक मरचा मिशन का रहनेवाला है। जानकारी के अनुसार ज्योतिष होरो की पत्नी सदर अस्पताल खूंटी में भर्ती है। ज्योतिष अपने दोस्त आलोक टोपनो के साथ अपनी पल्सर बाइक से कंबल पहुंचाने अस्पताल जा रहा था। इसी क्रम में ओरमेंजा गांव के पास बाइक चालक ने विपरीत

एंबुलेंस में घायल • फोटोन न्यूज

दिशा से आ रही यात्री बस को सीधी ठोकर मार दी। इससे ज्योतिष हीरो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त आलोक गंभीर रूप से घायल हो गया। 108 एंबुलेंस की मदद से उसे रेफरल अस्पताल ले जाया गया, पर उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल खूंटी भेज दिया। घटना की सूचना मिलते ही ज्योतिष होरो की मां एंजलीना होरो और कई परिजन रेफरल अस्पताल पहुंचे। बेटे का शव देखते ही उसकी मां बार-बार बेहोश हो रही थी। परिजन उसे ढाढ़स दे रहे थे। तोरपा थाना की पुलिस ने सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों का सौंप दिया।

वर्षांत में ही पिकनिक स्थलों पर बढ़ी चहल-पहल, बंगाल से भी पहुंचने लगे पर्यटक

सैलानियों को खूब लुभा रहा खूंटी का विशाल लतरातू जलाशय

AGENCY KHUNTI

भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती खूंटी को प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में कई सौगातें दी हैं, जो शायद ही झारखंड के किसी अन्य जिले में नजर आती हो। पेरवांघाघ, पंचघाघ, रानी फॉल, सप्तधारा, उलूंग, पांडूपुड़िंग, रिमिक्स फॉल सहित कई प्राकृतिक पर्यटन स्थल खूंटी जिले में आकर्षण का केंद्र हैं जबकि लतरातू जलाशय, रेमता जलाशय, बिरसा मृग विहार जैसे मानव निर्मित पर्यटन केंद्र हमेशा सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। साथ ही बाबा आम्रेश्वर धाम, नकटी देवी, माता सोनमेर मदिर सहित कई धार्मिक स्थल भी युगों से लोगों के लिए आस्था के केंद्र रहे हैं।

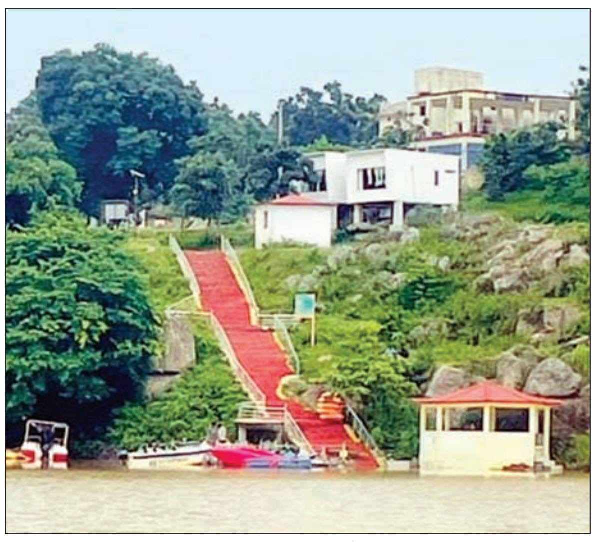

डैम के किनारे का दृश्य व बोटिंग के लिए लगीं नौकाएं • फोटोन न्यूज

पक्षियों की चहचहाहट देती सुकून

खूंटी जिले के लतरातू डैम हाल के दिनों में सैलानियों के लिए बड़े आकर्षण केंद्र के रूप में उभरा है। लतरातू डैम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और मनोरम दृश्य के लिए लोकप्रिय है। समय के साथ इसे पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए और भी आकर्षक बनाया जा रहा है। लतरातू डैम के चारों ओर हरे-भरे जंगल, साफ-सुथरी झील और पक्षियों की चहचहाहट इसे एक आदर्श पिकनिक स्थल बनाते हैं। यहां आकर आप बोटिंग समेत अन्य मनोरंजक चीजों का भी आनंद ले सकते हैं। यह स्थान परिवार और दोस्तों के साथ बहुमूल्य समय बिताने कर लिए बढ़िया विकल्प है। साथ ही प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीन के लिए भी एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है।

प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा लतरातू डैम : उपायुक्त

लतरातू जलाश के संबंध में खूंटी के उपायुक्त लोकश मिश्रा कहते हैं कि यह काफी आकर्षक है। यहां वर्षभर प्रकृति प्रेमियों और सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। विशेषकर नवंबर से लेकर फरवरी तक तो यहा सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से लतरातू डैम को एक प्रमुख पर्यटन और पिकनिक स्थल के रूप में विकसित करने की पहल की गई है। लतरातू जलाशय के विकास के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। उपायुक्त ने कहा कि हमारा प्रयास है कि लतरातू डैम घूमने के लिए आने वाले पर्यटक एक अद्भुत अनुभव प्राप्त करें और इस क्षेत्र की सुंदरता और संस्कृति का आनंद लें। साथ ही उन्होंने पर्यटकों से अपील की कि डैम क्षेत्र में सुरक्षा निदेशों का पालन करें। प्रकृति की सुंदरता को संरक्षित करने के लिए कचरा न फैलाएं और पिकनिक के दौरान डैम के निकट सतर्कता बरतें।

नई कमेटी ने संभाला श्री दिगंबर जैन समाज का प्रभार

नवगठित कमेटी के पदाधिकारी • फोटोन न्यूज

RAMGARH : श्री दिगंबर जैन समाज का चुनाव संपन्न होने के बाद सत्र 2024-26 के पदाधिकारी ने प्रभार ग्रहण कर लिया। अध्यक्ष पद पर प्रभार ग्रहण करने वाले राजेंद्र चूड़ीवाल ने बुधवार को नई कमेटी के पदाधिकारियों को नई ऊर्जा के साथ समाज का काम करने की बात कही। जैन भवन में आयोजित पदस्थापना समारोह में पुराने सत्र 2022-24 की कमेटी द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया,जिसमें पूर्व सचिव नरेंद्र छाबड़ा के जरिये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जंबू पाटनी की ओर से विगत दो वर्षों का आय ब्यय का लेखा-जोखा समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

राजेंद्र को अध्यक्ष व योगेश को सचिव का मिला प्रभार

बैठक के दौरान राजेंद्र चूड़ीवाल को अध्यक्ष और योगेश सेठी को सचिव पद का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा राजेंद्र पाटनी को उपाध्यक्ष, विकास रपरिया को सहसचिव, सौरभ अजमेर को कोषाध्यक्ष, देवेंद्र गंगवाल को मंदिर मंत्री, मीडिया प्रभारी श्रवण जैन, सुनील छाबड़ा को भवन एवं भंडार मंत्री की जिम्मेवारी प्रदान की गई।

सच के हक में...
Daily THE PHOTON NEWS
www.thephotonnews.com
Thursday, 12 December 2024

लावारिस हालत में छोड़े गए शिशुओं की सुरक्षा का लिया संकल्प

BRIEF NEWS

छात्रों पर लाठीचार्ज कर सरकार ने स्पष्ट कर दी अपनी मंशा : चम्पाई

RANCHI : पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक चम्पाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इसी तर्ज पर अपने कार्यकाल की शुरूआत में ही न्याय की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करके सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। चम्पाई सोरेन ने लिखा है कि हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि यदि नियुक्ति सहित किसी भी सरकारी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हों, तो सीबीआई जांच के जरिये सरकार इस विवाद का सर्वमान्य हल निकाल सकती है लेकिन जिस प्रकार लाठी के दम पर युवाओं के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है।

सदर एसडीओ ने फुटपाथ पर सोने वाले बेघर लोगों को शेल्टर हाउस पहुंचाया

RANCHI : रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के आदेश के बाद में मंगलवार देर रात अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ), सदर उत्कर्ष कुमार ने रांची के मुख्य चौराहों पर फुटपाथ पर सोने वालें बेघर लोगों को रेस्क्यू कर शेल्टर हाउस पहुंचाया। जो नहीं गए उनके लिए कंबल और अलाव की व्यवस्था की गई ताकि ठंड से उनका बचाव किया जा सकें। कुमार ने अपर बाजार स्थित और खादगड़ा स्थित शेल्टर होम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य रूप से शेल्टर होम के बाथरूम की साफ-सफाई और रिपेयर कार्य कराने का संबंधित पदाधिकारी को दिशा-निर्देश दिया। साथ ही शहर अंचल अधिकारी को मुख्य इलाकों में अलाव जलाने के लिए कहा। उल्लेखनीय है कि उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री बेहद संजीदगी से लोगों की समस्या को जमीनी स्तर पर दूर करने के लिए प्रयासरत हैं।

किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे : बाबूलाल

RANCHI : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किसानों से धान की खरीद के मामले में राज्य सरकार को अपना वादा निभाने को कहा है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी बात रखते कहा है कि झामुमो-कांग्रेस गठबंधन ने किसानों से वादा किया था कि धान की खरीदी 3200 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर की जाएगी। लेकिन चुनावी वादों पर अमल न होने से किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बाबूलाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध करते कहा है कि चुनावी वादों के अनुरूप किसानों से 3200 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान की खरीदी करें। साथ ही, किसानों के लिए पारदर्शी व्यवस्था और समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।

PHOTON NEWS RANCHI : हर स्तर पर शिशुओं के जीवन की रक्षा होनी चाहिए। यह दुखद है कि देश में हर दिन कई नवजात शिशु लावारिस अवस्था में छोड़ दिए जाने के कारण असुरक्षा और लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। इन शिशुओं के जीवन और अस्मिता की रक्षा के उद्देश्य से पालोना अभियान, जो आश्रयणी फाउंडेशन द्वारा समर्थित है, नवजात सुरक्षा अधिनियम की मांग को लेकर निरंतर काम कर रहा है। इसी कड़ी में अभियान की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्यों ने छठी वर्चुअल मीटिंग की। बैठक में लावारिस हालत में छोड़े गए शिशुओं की हर तरह से सुरक्षा का संकल्प लिया गया। मीटिंग में 12 सदस्यों ने भाग लिया। इनमें डॉ. कृपा शंकर चौबे (भोपाल), एडवोकेट केडी शर्मा (पटना), डॉ. वैशाली निगम (देवास), एडवोकेट नवीन शेलर (दिल्ली), दीप सिंह (विदिशा), त्रिभुवन शर्मा (गुमला), एडवोकेट प्रीति प्रसाद (बोकारो), अविनाश आथल्ये (जबलपुर), नवीन कुमार (दिल्ली), मोहन कुमार (श्योहर), ज्योति पांडे (बेंगलुरु) तथा मोनिका आर्य (रांची) सम्मिलित हुईं।

नवजात सुरक्षा अधिनियम की मांग को लेकर निरंतर काम कर रहा पालोना अभियान

राष्ट्रीय कोर कमेटी की मीटिंग में 12 सदस्यों ने की शिरकत, रांची की मोनिका व गुमला के त्रिभुवन ने भी रखे विचार

एक सेट फॉर्मेट की आवश्यकता

डॉ. वैशाली एनआईसीयू की इंचार्ज और शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ड्राफ्ट तैयार करके दिया कि जब भी शिशु अस्पताल में लाया जाए तो क्या आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। कहा कि शिशुओं की जानकारी देने के लिए एक सेट फॉर्मेट की आवश्यकता है। वर्तमान में लगभग 18 पन्नों का फॉर्मेट है, जिसको भरना डॉक्टरों के लिए मुश्किल होता है।

न हो अधिक पूछताछ

एडवोकेट केडी मिश्रा ने कहा कि शिशु को सुरक्षित या घायल अवस्था में लाने वाले से अधिक पूछताछ न हो। इसके लिए कॉलम बना दिए जाएं जैसे – अजनबी, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, रिश्तेदार इत्यादि।

इलाज के बाद शिशु का डिस्चार्ज

मीटिंग में शिशु के डिस्चार्ज को लेकर चर्चा की गई। डॉ. वैशाली ने बताया कि डिस्चार्ज के समय शिशु के ट्रीटमेंट और टीकाकरण संबंधी जानकारी शिशु के साथ संलग्न रहती है। मोहन कुमार ने सुझाव दिया कि अस्पताल में किसी एक स्टाफ को बच्चे की स्थिति अपडेट व अन्य कार्य के लिए समन्वय का उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए।

होनी चाहिए जीवन रक्षक की जानकारी

मोनिका आर्या का मत था कि शिशु को लाने वाले का नाम अवश्य पूछा जाए, क्योंकि शिशु को बचाने वाले उसके जीवन रक्षक हैं और यह एक उत्तम कार्य है। मीटिंग के अंत में सभी लोग इस बात पर एकमत थे कि शिशु को लाने वाले की जानकारी को लेना मेंडेटरी न बनाया जाए, क्योंकि पुलिस के डर से बहुत से लोग अपनी जानकारी नहीं देना चाहते हैं।

सरेंडर किए गए शिशु का हो इलाज

डॉ. कृपा शंकर चौबे ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सरेंडर फॉर्म जैसा फॉर्मेट एबेंडन केस में भी रखा जा सकता है। इसके बाद शिशु के ट्रीटमेंट पर चर्चा हुई कि कैसे सरेंडर किए गए शिशु का इलाज किया जाना चाहिए। इस पर डॉ. वैशाली निगम ने डीएनए सैंपलिंग के विषय में जानकारी दी। डॉ. चौबे ने भी अपना मत दिया कि डीएनए संबंधी ऑर्डर करने का अधिकार सीडब्ल्यूसी के पास होना चाहिए।

गलत जानकारी से शिशुओं का बचाव जरूरी

मोनिका आर्य ने कहा कि कई बार शिशुओं के विषय में मीडिया में गलत जानकारी चली जाती है। इससे पॉलिसी बनाने में दिक्कत आती है। एडवोकेट नवीन शेलर ने डेटा और फॉर्मेट के डिजिटलीकरण पर जोर दिया। त्रिभुवन शर्मा ने सुझाव दिया कि मिशन वात्सल्य में बदलाव करके गाइडलाइन बनाई जा सकती है, ताकि शिशुओं का डाटा तैयार किया जा सके।

वित्त मंत्री राधाकृष्ण ने पेश किया 11697 करोड़ का अनुपूरक बजट

महिला बाल विकास के लिए सबसे अधिक 6390.55 करोड़ का प्रावधान

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 11697.45 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें सबसे अधिक महिला बाल विकास विभाग के लिए 6390.55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके बाद ऊर्जा विभाग के लिए 2577.92 करोड़, गृहकारा विभाग के लिए 445.96 करोड़, माध्यमिक शिक्षा के लिए 301.89 करोड़ और प्राथमिक शिक्षा के लिए 272.80 करोड़ का प्रावधान है। महिला बाल विकास के लिए 6,39,055.83 लाख रुपये, प्राथमिक शिक्षा के लिए 27280.18 लाख रुपये, माध्यमिक शिक्षा के लिए 30189.57 लाख रुपये, आवास प्रभाग के लिए 1.00 लाख रुपये, पंचायती राज के लिए 2516.35 लाख रुपये, ग्रामीण कार्य के लिए 2.66 लाख रुपये, डेयरी प्रभाग के लिए 29.34 लाख रुपये, कला संस्कृति के लिए 1924.25 लाख रुपये, एसटी-एससी पिछड़ा वर्ग के लिए 5238.13 लाख रुपये, जल संसाधन के लिए 6869.30 लाख रुपये, नगर विकास के लिए 143.25 लाख रुपये, परिवहन के लिए 0.01 लाख रुपये, पर्यटन के लिए 114.95 लाख रुपये, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 36.76 लाख रुपये, कृषि प्रभाग के लिए 44.54 लाख रुपये, पशुपालन प्रभाग के लिए 509.10 लाख रुपये, मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए 6137.14 लाख रुपये, राज्यपाल सचिवालय के लिए 13.00 लाख रुपये, मंत्रिमंडल निर्वाचन के लिए 12311.00 लाख रुपये, मंत्रिमंडल निगरानी के लिए 32.90 लाख रुपये, नागर विमानन के लिए 2.00 लाख रुपये, सहकारिता के लिए 25006.41 लाख रुपये, ऊर्जा के लिए 257792.21 लाख रुपये, उत्पाद के लिए 66.70 लाख रुपये, वित्त विभाग के लिए 5865.42 लाख रुपये, ब्याज संदाय के लिए 11260.27 लाख रुपये, ऋण वापसी के लिए 1700.00 लाख रुपये, वित्त अंकेक्षण के लिए 4.13 लाख रुपये, वाणिज्यकर के लिए 391.00 लाख रुपये, खाद्य आपूर्ति के लिए 24.65 लाख रुपये, वन विभाग के लिए 168.15 लाख रुपये, स्वास्थ्य के लिए 14443.13 लाख रुपये, गृह कारा के लिए 44596.40 लाख रुपये, उद्योग के लिए 1482.69 लाख रुपये, सूचना जनसंपर्क के लिए 8027.06 लाख रुपये, सांस्थिक वित्त के लिए 11.16 लाख रुपये, श्रम विभाग के लिए 158.93 लाख रुपये, विधि के लिए 56.95 लाख रुपये, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 44.02 लाख रुपये, हाईकोर्ट के लिए 3739.00 लाख रुपये, खान विभाग के लिए 1.02 लाख रुपये, संसदीय कार्य प्रभाग के लिए 12.00 लाख रुपये, विधानसभा के लिए 1.00 लाख रुपये, जेपीएससी के लिए 3540.10 लाख रुपये, योजना विकास के लिए 55.00 लाख रुपये, पेयजल के लिए 3445.50 लाख रुपये, निबंधन के लिए 26.00 लाख रुपये, आपदा प्रबंधन के लिए 16640.30 लाख रुपये, राजस्व भूमि सुधार के लिए 315.47 लाख रुपये, पथ विभाग के लिए 17015.00 लाख रुपये, ग्रामीण विकास के लिए 19428.99 लाख रुपये, तकनीकी शिक्षा के लिए 1952 लाख रुपये, स्कूली शिक्षा के लिए 22.20 लाख रुपये का प्रावधान है।

विस में सीएम हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर व अन्य। ● फोटोन न्यूज

इन विभागों के लिए बजट पर दिया जोर

चुनाव में किए गए वायदे को पूरा करने के लिए सरकार ने उन विभागों पर विशेष जोर दिया है, जिससे जनता सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। सरकार ने मंईयां सम्मान योजना के लिए 6390.55 करोड़ आवंटित की है। इसके अतिरिक्त स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 272 करोड़, पथ निर्माण विभाग के लिए 170.15 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 194.28 करोड़, गृह कारा विभाग के लिए 445.96 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए 2577.92 करोड़ और पशुपालन विभाग के लिए 250.06 करोड़ दिए गए हैं।

विस के बाहर धरना पर बैठे मांडू विधायक

सड़क से सदन तक बढ़ी परीक्षा रद्द करने की मांग

PHOTON NEWS RANCHI : जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आहूत हजारीबाग बंद के दौरान मंगलवार को जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की गूंज विधानसभा तक पहुंच गई है। बुधवार को आजसू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो सदन के बाहर हाथ में तख्ती लेकर धरने पर बैठे नजर आए। तिवारी महतो इस परीक्षा को रद्द करने के साथ ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। इस बीच आजसू विधायक के बाद भाजपा विधायक पूर्णिमा दास ने भी इस परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर आपत्ति जताई है और मुख्यमंत्री से इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस परीक्षा में अनियमितता की शिकायतें आई हैं, उससे साफ है कि इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। छात्र आंदोलन के जरिए विधानसभा पहुंचने में सफल रहे जयराम महतो ने कहा कि सरकार को अभ्यर्थियों से बात करनी चाहिए थी। मैंने सरकार को चेताया था और हजारीबाग में सड़क पर बैठे अभ्यर्थियों से बात करने को कहा था, लेकिन सरकार ने एक न सुनी और लाठीचार्ज में छात्र घायल हो गए। अभी भी समय है, सरकार छात्र हित में फैसला ले, नहीं तो आंदोलन तेज होगा। इस मामले में बीजेपी विधायक नीरा यादव ने कहा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे।

नए विधायकों की सुरक्षा पर जोर, 24 जगहों पर विशेष चौकसी की जरूरत

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद 9 दिसंबर से सदन का विशेष सत्र चल रहा है। इस बार 20 नये चेहरे पहली बार चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं। सभी विधायक सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों से आना-जाना कर रहे हैं। लिहाजा, उन नये विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्पेशल ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक 23-24 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां विशेष चौकसी की जरुरत है। स्पेशल ब्रांच ने संबंधित जिलों के एसपी को इससे अवगत करा दिया है। इस बाबत राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि यह एक रूटीन प्रक्रिया है। चुनाव होने के बाद नये विधायकों के विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होती है। इसी लिहाज से स्पेशल ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर संबंधित जिलों के एसपी को अवगत करा दिया है। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था किसी थ्रेट इनपुट के आधार पर नहीं की गई है। यह एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि तैमारा घाटी, चुट्टूपालू घाटी, तिलैया घाटी, टाटीझरिया, कोलेबिरा जंगल, बंदगाव घाटी, अमझरिया घाटी, मनिका घाटी, चतरा के जंगली क्षेत्र, गारु घाटी, हुसैनाबाद रोड पर पहाड़ी घाटी समेत रामगढ़-गोला रोड, बोकारो-बनासो रोड, गढ़वा-नगर उंटारी रोड, चतरा-पेलावल रोड, चौपारण-बरही रोड, बगोदर-सरिया रोड, चान्हो-खलारी रोड, हजारीबाग-सिमरिया रोड, कांड्रा चौका रोड को चिन्हित किया गया है। विधायकों के सदन आने और जाने के दौरान इन जगहों पर विशेष चौकसी बरतना है।

डीजीपी अनुराग गुप्ता।

चेक बाउंस के मामले में सजायाफ्ता की सजा यथावत

RANCHI : न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने बुधवार को चेक बाउंस मामले में सजायाफ्ता सोनी देवी की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा है। इससे सजायाफ्ता को झटका लगा है। सोनी देवी को न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडे की अदालत ने शिकायतवाद संख्या 1702/23 मामले में दोषी पाकर 21 जुलाई को एक साल की सजा और 12 लाख रुपए का जुमार्ना लगाया था। कोर्ट से सुनाई गई सजा को चुनौती देते हुए सजायाफ्ता ने न्यायायुक्त की अदालत में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। इस पर सुनवाई पश्चात अदालत ने सजा को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दी।

होल्डिंग टैक्स को लेकर न्यूक्लियस मॉल 2 और अन्य को नोटिस जारी

PHOTON NEWS RANCHI : नगर निगम ने रेवेन्यू कलेक्शन के कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त के निर्देश पर 11 दिसंबर को सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार के नेतृत्व में निगम की संयुक्त टीम ने निगम क्षेत्र के विभिन्न आवासीय भवनों और प्रतिष्ठानों में होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और वाटर टैक्स की जांच की। इस अभियान के तहत कांके स्थित कैंब्रियन स्कूल, न्यूक्लियस मॉल 2, अंतु चौक स्थित जानकी भवन, यशोदा टावर स्थित कोटक महिंद्रा बैंक, परिवार कलेक्शन समेत कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई। कैब्रियन स्कूल में पूरे परिसर का रिअसेसमेंट करने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया गया। न्यूक्लियस मॉल 2 में बकाया कर का भुगतान शीघ्र करने के लिए नोटिस जारी किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि जानकी भवन को कई वर्षों से बकाया होल्डिंग टैक्स के भुगतान हेतु नोटिस जारी किया गया था। लेकिन, टैक्स नहीं भरा गया। इसके बाद पूरे भवन की मापी की गई। कोटक महिंद्रा बैंक यशोदा टावर में ट्रेड लाइसेंस न पाए जाने पर 15 दिनों के भीतर लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई। सहायक प्रशासक ने सभी भवन मालिकों और व्यवसायियों से अपील की कि वे जल्द से जल्द बकाया कर का भुगतान करें और ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करें। ऐसा नहीं करने पर निगम द्वारा झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जांच को पहुंची निगम की टीम।

सर्दी का सितम : पांच दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की आएगी कमी

झारखंड में अभी नहीं होगी बारिश, मगर तेवर दिखाती रहेगी ठंड

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड में हुई बारिश के बाद ठंड तेवर में आ गई है। ठंडी हवाओं के साथ तापमान गिर रहा है। इसमें अभी और गिरावट की संभावना है। अगले पांच दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अधिकतम तापमान अभी 27.6 डिग्री सेल्सियस है। अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री की गिरावट आएगी। इस वजह से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में अगले पांच दिनों तक बारिश के आसार नहीं हैं। सुबह में कोहरा रहेगा, लेकिन बाद में मौसम साफ हो जाएगा। गुरुवार को सुबह में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा रहेगा। बाद में आसमान साफ हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान बुधवार को 9.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर के अधिकतम तापमान में छह डिग्री की वृद्धि हुई है। राजधानी रांची के अधिकतम तापमान में 2.4 डिग्री, डाल्टेनगंज में 1.4 डिग्री और बोकारो में 3.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है।

गढ़वा में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा

- ठंडी हवाओं के साथ तापमान में आने लगी है गिरावट
- रांची समेत कई जिलों का तापमान सामान्य से कम

चाईबासा में सबसे अधिक उच्चतम तापमान

रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड का उच्चतम तापमान 27.6 डिग्री पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री रहा, जो गढ़वा जिले में दर्ज किया गया। इस दौरान कहीं भी बारिश नहीं हुई। रांची, जमशेदपुर, डाल्टेनगंज और बोकारो थर्मल का उच्चतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम हो गया। रांची का उच्चतम तापमान 22.4 डिग्री है, जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री है, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है। जमशेदपुर का उच्चतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम है। यहां का न्यूनमत तापमान 11.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस कम है। डाल्टेनगंज का उच्चतम पारा 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड कम है।

विधायक सरयू राय के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक 10 तक बढ़ी

RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट ने जदयू विधायक सरयू राय को मिली राहत बरकरार रखी है। अदालत ने बुधवार को उनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव की ओर से दर्ज करवाए गए मामले में पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को 10 जनवरी तक विस्तार दिया है। इसके साथ अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दोबारा समय दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सरयू राय की याचिका पर सुनवाई हुई। उनकी ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने बहस की। चुनाव के समय पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को विस्तार मिलने से सरयू राय को बड़ी राहत मिली है।

'बायोमीट्रिक उपस्थिति नहीं, तो अनुपस्थित माने जाएंगे कर्मी'

PHOTON NEWS RANCHI : रांची डीसी मंजूनाथ भजन्त्री लगातार प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में डीसी ने बुधवार को नामकुम प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीसी ने बायोमेट्रिक सेसभी पदाधिकारियों व कर्मियों की उपस्थिति की जांच की। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के बिना सभी अनुपस्थित माने जायेंगे, ससमय कार्यालय आयें और अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करें। अनाधिकृत रुप से अनुपस्थिति पर डीसी ने बीडीओ विजय कुमार एवं सीओ कमल किशोर सिंह को कार्रवाई करने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान प्रखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सविता कुमारी वर्मा अनुपस्थित पायी गयीं, जिस पर डीसी ने उनकी अनुपस्थिति अधिकृत है या नहीं इसे सत्यापित करने का निर्देश दिया। डीसी ने प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय में निष्पादित किये जाने वाले सभी कार्यों की जांच की। उन्होंने लॉग बुक, आगत-निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, संचिका, जनशिकायत, पेंशन तथा अन्य की जांच करते हुए कहा कि सभी आवेदनों का त्वरित गति से निष्पादन करें।

समाचार सार

मछुआ गागराई को दी गई श्रद्धांजलि

BANDGAON : पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के नकटी बाजार परिसर में बुधवार को झारखंड आंदोलनकारी शहीद मछुआ गागराई का 35वां शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समाजसेवी डॉ. विजय सिंह गागराई, 20 सूत्री अध्यक्ष दोड़ाय जोंकों, शहीद मछुआ गागराई की पत्नी रंधाई कुई, पुत्र सिकंदर गागराई, झारखंड आंदोलनकारी श्याम गागराई, बागुन गागराई, विजय दोंगो, रामराय सामाड, कुशल गागराई, दीपक मुंडा, एतवा टुटी समेत अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि विजय सिंह गागराई ने कहा कि शहीद मछुआ गागराई झारखंड अलग राज्य व जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे। शहीद परिवार को मान-सम्मान व सरकारी सहायता मिलनी चाहिए।

शिक्षा व पर्यावरण पर कल से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

JAMSHEDPUR : कदमा स्थित डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 13-14 दिसंबर को दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका विषय 'हार्नेसिंग द पावर ऑफ एजुकेशन टू एम्ब्रेस एंड एडॉप्ट ग्रीन इनिशिएटिव्स' है। बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में बी. चंद्रशेखर, ललिता चंद्रशेखर, सतीश कुमार सिंह, श्रीप्रिया धर्मराजन, डॉ. जूही समरपिता व डॉ. मोनिका उप्पल ने बताया कि टाटा स्टील के सहयोग से होने वाले सम्मेलन में 7 गैर सरकारी संस्था कोरू फाउंडेशन, एम्प्लीफाइंग कम्युनिटी वॉयस प्रोजेक्ट, हाउस ऑफ ग्रोनेस्ट, विनिशा, बिपोनी, सुरदीब प्राकृतिक प्रोडक्ट्स आदि भाग ले रहे हैं।

कस्तूरबा की छात्राओं ने चलाए तीर, भेदे लक्ष्य

GHATSILA : एचसीएल-ईसीसी सीएसआर के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कार्यकारी संस्था विद्यानिकेतन के साथ विभिन्न प्रकार के समाज कल्याण कार्य के साथ सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके के बालिकाओं की प्रतिभा के अनुरूप उनकी प्रतिभा को तैयार करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के लिए मल्टी फैसिलेटेड विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) मुसाबनी की 37 एवं घाटशिला (केजीबीवी) की 52 लड़कियों को तीरंदाजी का प्रशिक्षण टाटा स्टील के कोच जितेन महतो व तिलक महतो की देखरेख में दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि झारखंड के ग्रामीण इलाके की प्रतिभा को निखारकर उचित प्लेटफार्म तक पहुंचाया जा सके, जिससे ये लड़कियां अपने क्षेत्र प्रखंड, राज्य व परिवार का नाम रोशन कर सकें।

मधुसूदन महतो जयंती पर छात्रों ने भरे सांस्कृतिक रंग

CHAKRADHARPUR : आसनतलिया स्थित मधुसूदन महतो उच्च विद्यालय में बुधवार को मधुसूदन महतो जन्मोत्सव सह वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं ने गीत, संगीत व नृत्य से सांस्कृतिक रंग भर दिया। आसनतलिया के पूर्व मुखिया मधुसूदन महतो का जन्म 11 दिसंबर 1911 को ग्राम आसनतलिया में हुआ था। उनकी स्मृति में उनके पुत्रों श्यामसुंदर महतो, लक्ष्मण महतो, प्रभात कुमार महतो व कमलेश कुमार महतो ने 26 जनवरी 1992 को मधुसूदन महतो उच्च विद्यालय की स्थापना की थी। आज यहां सीबीएससी माध्यम से केजी से 12वीं तक करीब 3000 छात्र अध्यनरत हैं।

मानगो के बेताकोचा में कचरा प्लांट लगाने का विरोध

JAMSHEDPUR : पलासबनी व देवघर पंचायत के मुखिया व बेताकोचा के ग्राम प्रधान ने उपायुक्त को ज्ञापन दिया है, जिसमें बेताकोचा में कचरा प्लांट लगाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यहां आदिवासियों का धार्मिक स्थल जाहिराथान है। यही नहीं, कचरा प्लांट लगाने से यहां के आसपास की खेती पर असर पड़ेगा ही, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होगा। इन्होंने कहा कि यदि कचरा प्लांट को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया गया, तो जोरदार आंदोलन होगा।

सहायक लोको पायलट के लिए होगी परीक्षा

JAMSHEDPUR : दक्षिण पूर्व जोन के 700 से ज्यादा ग्रुप सी व डी श्रेणी के रेल कर्मचारी जल्द सहायक लोको पायलट बनेंगे। इनमें चक्रधरपुर मंडल के करीब 150 रेलकर्मी शामिल हैं, जिन्हें सहायक लोको पायलट बनाया जा सकता है। एएलपी पद पर प्रमोशन के लिए जोन स्थित चार मंडल के रेलकर्मियों से आवेदन मांगा गया था। इधर, विभागीय परीक्षा से रेलकर्मियों का ग्रेड बदलने की प्रक्रिया गार्डेनरीच में शुरू है।

चौकीदार के लिए 22 को दोबारा होगी परीक्षा

JAMSHEDPUR : पूर्वी सिंहभूम जिले में 1 दिसंबर को चौकीदार के 305 पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा रद्द कर दी गई है। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब यह परीक्षा 22 दिसंबर को दोबारा ली जाएगी।

प्रवचन देते पं. पवन कृष्ण गौतम • फोटोन न्यूज

भगवान के गुणों का श्रवण करें, यही भक्ति है : पं. गौतम

JAMSHEDPUR : गोलमुरी स्थित जॉगर्स पार्क मैदान में बुधवार को संध्या 4 बजे से भागवत कथा प्रारंभ हुई। कथा के दूसरे दिन वृंदावन से पधारे पं. पवन कृष्ण गौतम ने कहा कि वैसे सत्य को बारंबार प्रणाम करते हैं, जो समस्त ब्रह्मांड में अधर्म का नाश किया हो, कुरीति-कुमति का सर्वनाश किया हो। श्री कुसुम मधुबन बिहारी गौ सेवा संस्थान द्वारा आयोजित भागवत कथा में पं. गौतम ने कहा कि यक्ष ने पहला प्रश्न किया कि आखिर मानव का धर्म क्या है और दूसरा प्रश्न भगवान के कितने अवतार हुए, साथ ही यह बताइए कि भगवान कौन से अवतार में कौन सी लीला की। सूत महाराज ने जवाब देते हुए बताया कि भागवत कथा में अमृत का रस है और भागवत सुनने के लिए नहीं, बल्कि भागवत तो पीने के लिए है, इसलिए इसका रसपान कीजिए, आनंदित रहिए, सूत महाराज ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते हैं, बल्कि भागवत कथा में रसपान करने से पाप धुलते हैं।

अब 10 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे सभी विभागाध्यक्ष, एमजीएम को मिले 90 लाख

पहली बार शुरू हुई यह व्यवस्था, 18 विभाग प्रमुखों के खाते में भेजे पांच-पांच लाख रुपये

मरीजों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश, विभागों के पास अब नहीं होगा कोई बहाना

PHOTON NEWS JSR: स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज-अस्पताल के सभी विभागाध्यक्षों को प्रति वर्ष 10-10 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार दिया गया है। बुधवार को एमजीएम के विभिन्न विभागों के कुल 18 विभागाध्यक्षों के खाते में 5-5 लाख रुपये भेज दिए गए। यह राशि विभागाध्यक्षों के नाम से खुले खाते में भेजी गई है। एमजीएम कॉलेज के प्रिंसिपल डा. दिवाकर हांसदा ने बताया कि बदलते दौर में कार्य करने की शैली तेजी से बदली है। पहले विभागों में कुछ भी खामियां सामने आती थीं या मरीजों को परेशानी होने पर विभागाध्यक्ष अधीक्षक को पत्र लिखते थे। इसके बाद अधीक्षक और प्रिंसिपल स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखते थे। इस प्रक्रिया को पूरा होने में महीनों लग जाता था, लेकिन अब वह दौर खत्म हो चुका है। पहली बार सभी विभागाध्यक्षों को कम से कम पांच लाख और अधिक से अधिक 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने का अधिकार दिया गया है। इसे लेकर बुधवार को प्रिंसिपल ने सभी विभागाध्यक्षों के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। प्रिंसिपल ने कहा कि एमजीएम की सूरत बदलनी है और इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। अब सभी विभागाध्यक्षों को प्रति वर्ष 10-10 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार दिया गया है। ऐसे में विभाग को उनसे काफी उम्मीदें हैं। अब समस्या का समाधान तत्काल ढूंढना होगा। विभागाध्यक्षों के पास किसी तरह की बहाना नहीं होगा। इसमें दवा से लेकर सर्जिकल आइटम सहित विभाग से जुड़ी सभी तरह की सामग्री की खरीदारी वे कर सकते हैं।

एमजीएम में ये विभाग संचालित

मेडिसिन, सर्जरी, आर्थो, नेत्र, ईएनटी, महिला एवं प्रसूति रोग, बर्न, एनेस्थीसिया, माइक्रोबायोलाजी, फार्माकोलाजी, पैथोलाजी, रेडियोलाजी, बायोकेमेस्ट्री, एफएमटी, पीएसएम, मनोरोग विभाग, दंत रोग विभाग।

डिपार्टमेंट हेड को प्रस्ताव तैयार कर काम करने का निर्देश

एमजीएम प्रिंसिपल डॉ. दिवाकर हांसदा ने कहा कि सभी विभागाध्यक्षों को अपने-अपने विभाग से संबंधित एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा है, ताकि उसके अनुसार मरीजों के हित में सभी बड़े कदम उठाए जा सकें। प्रिंसिपल ने कहा कि आवश्यकतानुसार यह राशि समय पर खर्च करनी होगी, अन्यथा लैप्स करने की संभावना बनी रहेगी। इधर, विभागाध्यक्षों ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे व्यवस्था में सुधार जरूर देखने को मिलेगा। अभी तक विभागाध्यक्ष के पास कोई अधिकार नहीं होता था। वह चाहकर भी विभाग की खामियां दूर नहीं कर सकता था, लेकिन अब सभी छोटे-बड़े कार्य बेहतर ढंग से किए जा सकेंगे।

जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज में मना भारतीय भाषा उत्सव दिवस

कार्यक्रम को संबोधित करते प्राचार्य डॉ. अमर सिंह • फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS JSR: जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज के हिंदी विभाग ने बुधवार को भारतीय भाषा उत्सव दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अमर सिंह ने की। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉ. अमर सिंह ने भाषायी एकता की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि हमें एक-दूसरे की भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। भाषा विविधता में एकता की प्रतीक होती है, और इसे हमें संजोकर रखना चाहिए। अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉ. संजय यादव ने क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि पर कहा कि भारतीय भाषाओं का संरक्षण आवश्यक है। डॉ. स्वाति सोरेन ने संथाली गीत प्रस्तुत करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व बताया। डॉ. अंतरा कुमारी ने भोजपुरी भाषा के बारे में बताया, जबकि डॉ. अशोक कुमार रवानी ने खोरठा भाषा में गीत सुनाया। प्रो. ईश्वर राव ने तेलुगु भाषा में एक गीत प्रस्तुत किया, जो कार्यक्रम में विविधता और समृद्धि का प्रतीक बना।

एलबीएसएम में याद किए गए महाकवि सुब्रमण्यम भारती

JAMSHEDPUR : एलबीएसएम कॉलेज में महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाकवि भारती के योगदान को याद करते हुए भाषायी एकता और समाज सुधार के लिए उनकी भूमिका को सराहा गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और साहित्यकार डॉ. अशोक कुमार झा 'अविचल' ने महाकवि भारती के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डाला।

ग्रेजुएट कॉलेज में दी गई भारतीय भाषाओं की जानकारी

JAMSHEDPUR : साकची स्थित ग्रेजुएट कॉलेज में बुधवार को भारतीय भाषा दिवस पर संगोष्ठी हुई, जिसमें एक भारत-श्रेष्ठ भारत का संकल्प लिया गया। तमिल के सुप्रसिद्ध साहित्यकार चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर हुए कार्यक्रम में छात्रों को भारतीय भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया, एकता, सद्भाव और अखंडता का अनुभव कराया गया और राष्ट्र के विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करने की दिशा में पहल करने की बात बताई गई। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. वीणा सिंह प्रियदर्शी ने भारतीय भाषाओं के महत्व और उसकी प्रासंगिकता के बारे में प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत में 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें 22 भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हैं। भारतीय भाषा भारतीय संस्कृति और सभ्यता को प्रदर्शित करने में सहायक हैं।

आपराधिक प्रवृत्ति वालों पर पैनी नजर रखने का निर्देश

घाटशिला में पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते एसडीपीओ अजित कुजूर

GHATSILA : पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल अंतर्गत एसडीपीओ कार्यालय में बुधवार को पुलिस पदाधिकारियों की क्राइम मीटिंग हुई। इसमें एसडीपीओ अजित कुजूर ने अधीनस्थ थाना प्रभारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। इसके साथ ही लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने, क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाने, पुराने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने समेत अन्य कई बिंदुओं पर गहनता से चर्चा की गई। अपराध उन्मूलन पर हुई बैठक में घाटशिला थाना प्रभारी मधुसूदन दे, कुमार इंद्रेश सहित अन्य थानेदार उपस्थित थे।

बहरागोड़ा में मिले 2 नए कुष्ठ रोगी, दी गई दवा

चर्मरोग के शिविर में मरीजों की जांच करते चिकित्सक • फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बहरागोड़ा में बुधवार को चर्मरोग जांच शिविर लगा था, जिसमें जिला कुष्ठ परामर्शी डॉ. राजीव लोचन महतो ने 23 संदेहास्पद मरीजों की जांच की। इसमें 2 नए कुष्ठ मरीजों की सम्पुष्टि कर निःशुल्क एमडीटी वितरण किया गया। जिला कुष्ठ परामर्शी ने बताया कि शरीर में किसी भी प्रकार का दाग तथा दाग में सूनापन हो तो वह कुष्ठ रोग हो सकता है, तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें। यह एक बैक्टीरिया जनित रोग है और इसका इलाज सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क उपलब्ध है। उन्होंने कुष्ठ रोग के लक्षण, उपचार तथा कुष्ठ रोग से होने वाली दिव्यांगता के बारे में बताया। शिविर में कुष्ठ के मरीजों को सेल्फ केयर के महत्व के बारे में बताया गया। उन्हें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जानकारी देते हुए बताया कि सर्जरी से दिव्यांगता को ठीक किया जा सकता है।

एसडीओ ने बीडीओ सीओ को दिया समन्वय बनाने का निर्देश

GHATSILA : अनुमंडल कार्यालय, घाटशिला के सभागार में बुधवार को एसडीओ सुनील चंद्र की उपस्थिति में सभी बीडीओ-सीओ की बैठक हुई। इसमें प्रखंड और अंचल कार्यालय से संचालित कार्यों के निष्पादन में आने वाली अड़चन को दूर करने का निर्देश दिया। कहा गया कि प्रखंड के अधिकांश कार्य जमीन संबंधित अड़चन रहने पर समन्य के अभाव में नहीं उतर पाते हैं। विभागों के कार्यों का निपटारा करने के लिए अंचल और प्रखंड के बीच समन्वय बनाकर कार्यों का निष्पादन करने पर जोर दिया जाए। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लंबित मामले समेत अन्य पर गंभीरता से चर्चा की गई।

अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा, बंद कराई दुकान

शराब दुकान के बाहर हंगामा करतीं महिलाएं • फोटोन न्यूज

CHAKRADHARPUR : अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन कर शराब दुकान को बंद कर दिया है। इसके साथ ही दुकान में रखे अवैध शराब को जमीन पर गिरा कर विरोध जताया। घटना के बाद गांव में बुधवार को अलग माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार, चक्रधरपुर थाना अंतर्गत पंसुवा गांव में अवैध शराब के खिलाफ आजीविका वैष्णो देवी के महिला समूह महिला समिति ने अवैध शराब दुकान पहुंचकर भट्ठी बंद करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही देसी शराब को महिलाओं ने जमीन में बहा कर जमाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने गांव में शराब बिक्री करने पर रोक लगाने की मांग की। महिलाओं ने कहा कि गांव में शराब बिक्री करने से माहौल बिगड़ रहा है। घर के पुरुष अपनी कमाई शराब पीने में लगा रहे हैं, जिस कारण घर में रोजाना झगड़े होते हैं।

चाकुलिया के चियाबांधी पहुंची बाघिन 'जीनत', रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

JAMSHEDPUR : ओडिशा के मयूरभंज जिले के सिमिलिपाल बाघ अभयारण्य (एसटीआर) से छोड़ी गई तीन वर्षीय बाघिन 'जीनत' ने बुधवार को झारखंड के चाकुलिया के मौरबेड़ा जंगल में कदम रखा। रेलवे ट्रैक को पार करते हुए यह बाघिन भातकुंडा पंचायत के चियाबांधी स्थित जंगल में पहुंच गई है, जहां पर ओडिशा और झारखंड के वन विभाग की टीमें उसे रेस्क्यू करने के लिए पूरी तैयारी में जुटी हैं।

रेस्क्यू ऑपरेशन और ग्रामीणों का उत्साह : बाघिन के जंगल में होने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीणों की भीड़ जंगल के पास जमा हो गई है, जबकि रेस्क्यू टीम बाघिन की गतिविधियों पर निगरानी रख रही है। बाघिन को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिकअप वैन से तीन भैंसों को जंगल के पास भेजा है, जिनके सहारे बाघिन को रेस्क्यू करने की योजना है। इसके अलावा, बाघिन को पकड़ने के लिए पिंजरे की भी व्यवस्था की गई है।

बाघिन का सफर : बताया जा रहा है कि बाघिन 'जीनत' को 15 नवंबर को महाराष्ट्र के ताडोबा-अंधारी बाघ अभयारण्य से ओडिशा लाया गया था। उसे सिमिलिपाल अभयारण्य में 24 नवंबर को जंगल में छोड़ा गया था। वहां से बाघिन ने अब झारखंड के जंगलों में कदम रखा है। एसटीआर के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक प्रकाश चंद गोगिनेनी ने बताया कि बाघिन का स्वास्थ्य अच्छा है और वह अब झारखंड में प्रवेश कर चुकी है। वन विभाग उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है।

झारखंड और ओडिशा वन विभाग की साझा निगरानी : बाघिन 'जीनत' के जंगल में प्रवेश करने के बाद से दोनों राज्यों के वन विभाग अलर्ट मोड पर हैं। उनकी गतिविधियों की निगरानी के लिए जीपीएस ट्रैकर का उपयोग किया जा रहा है। ओडिशा और झारखंड के वन अधिकारी बाघिन की दिशा और गति पर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं।

एकदिवसीय कार्यशाला से हुई ग्रामीण प्रशासन को मजबूत बनाने की कवायद

मानकी-मुंडा व दिऊरी पर परंपरा बचाने की जिम्मेदारी : आयुक्त

PHOTON NEWS CHAIBASA: पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत कोल्हान यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में मानकी-मुंडा, डाकुवा व दिऊरी की एकदिवसीय कार्यशाला में हुई। इस दौरान कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त हरिकुमार केसरी, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष कुमार शेखर, उपविकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, वन प्रमंडल पदाधिकारी चाईबासा,सारंडा, अपर उपायुक्त व सभी अनुमंडल पदाधिकारी उपस्थित थे।

कार्यशाला में उपस्थित ग्रामसभा के प्रतिनिधि • फोटोन न्यूज

कार्यशाला को संबोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि झारखंड राज्य की संस्कृति और परंपरा ही यहां के समाज की पहचान है। इस संस्कृति के संवाहक व संरक्षक हैं, यहां के विभिन्न परंपरागत पदाधिकारी मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा व ग्रामीण दिउरी (पुजारी)।

झारखंड के ग्रामीण समाज में आपका महत्वपूर्ण स्थान है और स्थानीय शासन, न्याय एवं सामाजिक समरसता में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे ग्रामीण प्रशासन कहा जाता है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से हो रहे सामाजिक और आर्थिक बदलावों ने मानकी-मुंडा की जिम्मेदारी को और भी बढ़ा दिया है। वर्तमान परिदृश्य में आपके द्वारा किए जा रहे कार्य यथा जनता के साथ सरकार से सीधे संबंध रखना, विवादों का निपटारा ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्रामों में करना, अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखना एवं लगान वसूली सहित अन्य कार्य काफी सराहनीय हैं।

सन 1834-35 में ब्रिटिश सरकार ने इकरारनामा के आधार पर कोल्हान क्षेत्र के लिए मानकी तथा मुंडा को अलग-अलग सनद पट्टा निर्गत किया, जिसे हकूकनामा कहा जाता है। मुंडा को ग्राम का प्रधान तथा मानकी को पीड़ का प्रधान ठहराया गया है। मुंडा-मानकी अपने ग्राम तथा पीड़ के प्रति उत्तरदायी बनाए गए। यही रिवाज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कोल्हान क्षेत्र में प्रचलित है।

उपायुक्त ने कहा कि इस कार्यशाला उद्देश्य क्षेत्र की सामाजिक संरचना और मानकी-मुंडा में संवाद स्थापित करना है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कार्यशाला के माध्यम से स्थानीय स्तर की समस्याओं से अवगत होना है।

BRIEF NEWS

अररिया में पुलिस ने चोरी की बाइक व कट्टा के साथ दो को किया गिरफ्तार

ARARIYA : अररिया के बरदाहा में पुलिस ने आज चोरी के बाइक के साथ दो व्यक्ति को कट्टा के साथ गिरफ्तार किया। बरदाहा थानाध्यक्ष विकास कुमार मौर्या ने बताया कि चोरी की बाइक किशनगंज जिला के टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र के नोमा टोला मसजिद के पास से बरामद कर ली गयी है। उन्होंने बताया कि बरदाहा थाना क्षेत्र के बरदाहा वार्ड दस निवासी श्याम शर्मा पिता राजू शर्मा ने बरदाहा थाना में कांड 78/24 के तहत मामला दर्ज किया था। गत तीन दिसंबर की रात में बरदाहा पेट्रोल पंप के आगे ऋषुराज के दुकान के आगे बाइक नंबर बीआर 38 एक्स 4502 लगाकर बगल में चाय पीने चला गया। वापस आने पर बाइक नहीं थी। जब पेट्रोल पंप के आगे बाइक लगाया था तो बाइक के पास बरदाहा वार्ड आठ निवासी सूरज शर्मा पिता बालेश्वर शर्मा, अनिल मंडल पिता मोहन मंडल था। सूचक ने जब दोनों को फोन लगाया तो दोनों व्यक्ति ने कहा कि हमलोग सिकटी थाना क्षेत्र के भपटिया में है।

लालू यादव के बयान से आधी आबादी आहत : श्रवण

PATNA : ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने महिला संवाद यात्रा को लेकर लालू प्रसाद यादव के दिए गए बयान को अशोभनीय और निंदनीय करार दिया। मंत्री ने जदयू कार्यालय में बुधवार को आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लालू प्रसाद यादव की ओछी टिप्पणी से प्रदेश सहित पूरे देशभर की आधी आबादी का अपमान हुआ है और महिलायें कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसलिए विपक्षी गठबंधन में दबाव की राजनीति चल रही है। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने कहा कि महागठबंधन में शह-मात का खेल चल रहा है। सत्ता की महत्वाकांक्षा में सभी घटक दल एक-दूसरे की पैर खींच रहे हैं और प्रदेश की जनता भी उनके इस खेल को बखूबी समझ रही है। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में सफाया होना तय है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बयान पर भी कड़ी भर्त्सना की और कहा कि उन्हें महिलाओं से माफी माँगनी चाहिए।

बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी

PATNA : बिहार में पछुआ हवा चलने से ठंड बढ़ गई है। राजधानी पटना समेत कई शहरों में तापमान धड़ाम से गिरा है। उत्तर बिहार की तरह दक्षिण बिहार में भी कोहरा बढ़ रहा है। तराई इलाकों में बुधवार को घना कोहरा छाया रहा। डेहरी सबसे ठंडा रहा, जबकि सिवान सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को भी बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार कोसी-पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। बारिश होने पर ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को भी बिहार के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। कोहरे से ट्रेन और हवाई सेवा प्रभावित हो सकती है।

झारखंड के गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम से भेजा गया पत्र

लेटर भेज गया के महाबोधि मंदिर को उड़ाने की धमकी

AGENCY GAYA : गया के महाबोधि मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी मंदिर समिति को पत्र भेजकर दी गई है। धमकी मिलते ही मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस की जांच में पता चला है कि धमकी भरा लेटर झारखंड के गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर भेजा गया है। प्रिंस पर झारखंड सरकार ने 30 लाख का इनाम रखा है। उसके खिलाफ रेड और ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी है, लेकिन वह अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। अब तक की जांच में उसका मोबाइल लोकेशन दुबई में मिला है। इधर धमकी मिलने के बाद गया पुलिस मंगलवार को धनबाद के वासेपुर स्थित गैंगस्टर के घर भी पहुंची, लेकिन वहां प्रिंस खान नहीं मिला।

कुख्यात के घर धनबाद पहुंची पुलिस, जांच शुरू

धनबाद पुलिस ने पहले ही प्रिंस का पासपोर्ट रद्द करवा चुकी है। उसके खिलाफ प्रिंस खान साल 2021 में जमीन कारोबारी नन्हे खान की हत्या के बाद से फरार है। बोधगया को दोबारा दहलाने की साजिश 19 जनवरी 2019 को की गई थी। आतंकियों ने महाबोधि मंदिर परिसर के आसपास तीन जगहों पर विस्फोटक रखे थे। उस समय दलाई लामा बोधगया में ही प्रवास पर थे। हालांकि, गया पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर तीनों विस्फोटक बरामद कर किया था। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया था।

एजेंसियां हर पहलू पर कर रहीं जांच

धमकी मिलने के बाद महाबोधि मंदिर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियां हर पहलू पर काम कर रही हैं। बुधवार को गया के सिटी एसपी प्रेरणा कुमार ने कहा कि 'लेटर भेजकर धमकी दी गई है, जिसकी सत्यता की जांच की जा रही है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मामले में गोपनीयता बरती जा रही है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि धमकी असली है या किसी ने प्रिंस खान का नाम इस्तेमाल कर साजिश रची है।' 7 जुलाई, 2013 को आतंकवादियों ने महाबोधि मंदिर और बोधगया के आसपास के तीर्थस्थलों पर विस्फोट किए थे। 30 मिनट में 9 विस्फोट किए गए थे। इस हमले में दो भिक्षु सहित 5 लोग घायल हुए थे।

तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग, पुलिस ने खिलाई हवालात की हवा

ROHTASH : बिहार में बात-बात पर हथियार लहराना आज कल लोगों का शौक बन गया है। वहीं स्टेटस सिंबल को लेकर भी शादी समारोह, जन्म दिन की पार्टी या खास आयोजन सहित सार्वजनिक जगहों पर भी हथियार का प्रदर्शन करने से लोग बाज नहीं आते। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर रोहतास पुलिस ने अब कड़ाई से निपटने का मूड बना लिया है। दअरसल, जिले के करगहर थाना क्षेत्र के कौवाखोच में एक तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से पुलिस ने दो लाइसेंसी रायफल भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक हत्थे चढ़ा आरोपी चंद्रशेखर प्रधान कौवाखोज गांव का ही निवासी है। जबकि धनु कुमार सोनी सासाराम के तकिया का निवासी है। पुलिस की मानें तो चंद्रशेखर प्रधान का लाइसेंसी राइफल है। जबकि धनु कुमार सोनी दूसरे का लाइसेंसी राइफल लेकर हर्ष फायरिंग कर रहा था।

तीन लोगों ने तैरकर बचाई जान, एक किशोर लापता

शिवहर में बागमती की तेजधार में पलटी नाव

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस व लोगों की भीड़।

AGENCY SHEOHAR : बिहार के शिवहर में नाव पलट गयी। घटना पुरनहिया थाना क्षेत्र के दोस्तिया बागमती नदी घाट की बतायी जा रही है। बागमती नदी की उपधारा में छोटी नाव पलटी है। नाव पर 4 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचायी। एक किशोर अभी भी लापता हैं। एसडीएम अविनाश कुणाल, ट्रैफिक डीएसपी भारत, बीडीओ, सीओ, पुरनहिया थानाध्यक्ष प्रेमजीत सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है नाव पर चार लोग सवार थे। सभी नाव से अपने घर के लिए दूसरी तरफ पार कर रहे थे। इसी दौरान नाव डगमगाते हुए पलट गयी। घटना के दौरान अफरा-तफरी मच गयी। तीन लोग नदी तैरकर अपनी जान बचा लिए, लेकिन एक लापता है। खोताखोरों की टीम शव निकालने के लिए खोजबीन कर रही है। एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गयी है। लापता होने वालों में एक किशोर है जिसकी पहचान दोस्तीया वार्ड 12 निवासी कैलाश शाह के 15 वर्षीय पुत्र कार्तिक कुमार शामिल है।

वंदे भारत रद्द, राजधानी व विवेक एक्सप्रेस ट्रेन के रूट में बदलाव

AGENCY PATNA : ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन द्वारा जोराई रेलवे स्टेशन पर रेल नाकाबंदी के कारण बुधवार को कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। यह नाकेबंदी लीपुरद्वार डिवीजन द्वारा किया जा रहा है। बुधवार को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने जोराई स्टेशन पर पहुंच कर प्रदर्शन किया। देखते ही देखते काफी भीड़ जमा हो गई और उन्होंने पटरी पर चढ़ कर सभी लाइनों को जाम कर दिया। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस के 500 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स

एसोसिएशन पिछले कई वर्षों से अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा है। इस एसोसिएशन की मांग पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है इसलिए बुधवार को हजारों की संख्या में लोगों ने रेल रोक कर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और कई ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से डायवर्ट किया गया है। रेलवे अधिकारियों ने डायवर्जन से प्रभावित यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में बसों और टाटा सूमो की व्यवस्था की है।

इन ट्रेनों का मार्ग बदला : जिन ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया हैं उनमें ट्रेन संख्या-15657 ब्रह्मपुत्र मेल और ट्रेन संख्या- 15959 कामरूप एक्सप्रेस शामिल है। इसके अलावा ट्रेन संख्या- 22503 विवेक एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या- 13247 कामाख्या राजेंद्र नगर कैपिटल एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या- 12423 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट बदला गया है। वहीं, रेल नाकाबंदी के कारण ट्रेन नं। 22227/22228 न्यू जलपाईगुड़ी-गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 15704/15703 बोंगाईगांव-न्यू जलपाईगुड़ी- बोंगाईगांव एक्सप्रेस को रद्द किया गया है।

अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत परिवार में मचा कोहराम

NAWADA : राष्ट्रीय उच्चपदस्थ संख्या 20 पर नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर मोड़ के समीप फोर लेन पर बुधवार को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़ फरार हो गया। दुर्घटना के बाद आस-पास के लोगों ने ट्रैक्टर के नीचे दबे व्यक्ति को निकालना लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी अकबरपुर थाना को दी गई। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को जब्त कर ली। पुलिस ने शव को कागजी कार्रवाई करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल नवादा भेज दी। मृतक फतेहपुर गांव निवासी बुन्दी चौधरी के 45 वर्षीय पुत्र इंद्रदेव चौधरी बताए गए हैं।

बहन को स्कूल छोड़ने जा रहा था भाई ट्रक से कुचलकर दोनों की गई जान

AGENCY SASARAM : बिहार के रोहतास में सड़क हादसे में भाई बहन की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमोर्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है। साथ ही आगे की कारवाई में जुट गई है। घटना चेनारी इलाके की है। मिली जानकारी के मुताबिक चेनारी थाना क्षेत्र के टेकारी में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार भाई-बहन को कुचल दिया। जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही बाइक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि राजा हसन अपनी बहन को बाइक से स्कूल छोड़ने जा रहा था। इसी

क्षतिग्रस्त बाइक।

दौरान एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक खुरमाबाद के रहने वाले इजहार हुसैन के बच्चे थे। मृतक की पहचान राजा हसन (18 साल) और उसकी बहन कनिष जहरा (16 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों भाई-बहन की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। वहीं, घटना की सूचना मिलते ही चेनारी थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेजा है। इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने बताया कि ट्रक चालक की पहचान के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सीएम पर कमेंट करने पर भड़कीं लवली आनंद, बोलीं- सठिया गए हैं लालू यादव

AGENCY PATNA : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सीएम नीतीश कुमार की होने वाली 'महिला संवाद यात्रा' को लेकर दिए गए बयान पर शुरू हुई बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को जदयू सांसद सांसद लवली आनंद ने राजद नेता लालू यादव को जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव बुढापे में 'सठिया' गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका यह बयान महिलाओं का अपमान है। पटना में लवली आनंद ने कहा कि लालू यादव बहुत गलत बात बोल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव बुढ़ापा में सठिया गए हैं। उनका बयान महिलाओं का अपमान है। इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। लालू यादव मुख्यमंत्री के पद रहे और महिला जाति और मुख्यमंत्री के लिए इस तरह बोलना कहीं से भी ठीक नहीं है। उनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। इधर, इंडिया गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर पूछे गए सवाल

पर जेडीयू सांसद लवली आनंद ने कहा कि यह उनका मामला है। इंडिया गठबंधन में बिखराव है। पूरे देश में विपक्षी दल कहीं भी एकजुट नहीं है। उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ अपनी बात करते हैं। एनडीए एकजुट है और एनडीए के नेतृत्व में देश और राज्य में विकास के लगातार काम हो रहे हैं। तिरहुत स्नातक चुनाव में जदयू उम्मीदवार की हार पर लवली आनंद ने कहा कि ये देखना पड़ेगा ऐसा कैसे हुआ। बहुत सारी बातें है उसपर मिल बैठकर समीक्षा करनी चाहिए। यह देखना होगा कि कहां चूक हुई है।

आगजनी में चार परिवारों के घर जले, लाखों की क्षति

ARARIYA : फारबिसगंज प्रखंड के मझुवा पंचायत के रानीगंज डुमरिया गांव के वार्ड संख्या एक में देर रात्री अचानक आग लगने से चार परिवार का घर जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाते-पाते चारों परिवार के घरों मे आग फैल गया,जिसके कारण घर में रखे नगदी साढ़े तीन लाख रुपए,आभूषण समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। काफी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग के द्वारा आग पर काबू पाया गया।आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पीड़ित प्रतिमा देवी, प्रमिला देवी, अमित मंडल, महेंश मंडल, दिनेश मंडल ने बताया कि हमलोग खाना खाकर सो गए थे तभी अचानक आग की लपेटे देखकर हमलोग जान बचाकर किसी तरह बाहर निकले। हो हल्ला करने पर ग्रामीणों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन सबकुछ जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलने पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप पटेल ने पीड़ित परिजनों के घर पहुंच कर ढांढस बंधाया।

मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के दो हजार डिफॉल्टर, बेगूसराय में 900 छात्रों पर केस

AGENCY PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेनेवाले हजारों छात्र अब मुश्किलों में घिर गये हैं। बिहार के सैकड़ों वैसे छात्रों पर केस दर्ज किया गया है जिन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेने के बाद पैसे नहीं चुकाए हैं। अकेले बेगूसराय जिले में ही मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभान्वित 925 छात्रों पर नीलामी केस दर्ज किया गया है। हालांकि छात्रों से ऋण वसूली के मामले में बेगूसराय बिहार में प्रथम एवं पटना दूसरे स्थान है। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम बेगूसराय के सहायक प्रबंधक अजय कुमार राय ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय योजना में शामिल आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत तीन या चार वर्षीय तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण

बिहार सरकार

Student Credit Card Scheme

दिया गया है। मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लाभान्वि त वर्ष 2016-2020 तक में दो हजार छात्र डिफाल्टर हो गए हैं। वैसे छात्र जिन्होंने शिक्षा पूरी करने के एक वर्ष बाद किस्त जमा नहीं किया है, उन्होंने बताया कि 198 वैसे छात्रों को राहत दी गयी है, जो तकनीकी शिक्षा पूरी करने के बाद बेरोजगार हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसका पथ पत्र जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में प्रत्येक छह माह पर जमा किया जाता है। कोर्स समाप्त होने के एक वर्ष बाद ईमेल पर नोटिस भेजा जाता है। ईमेल के द्वारा पहुंच बार नोटिस देने के बाद रजिस्टर डाक से अंतिम नोटिस दिया जाता है। रजिस्टर डाक से भेजे गए नोटिस के बाद जो छात्र नजरअंदाज करते हैं उनके ऊपर नीलामी बाद दायर किया जाता है। बताया जाता है कि जो छात्र नियमित पढ़ाई करते हैं, उन्हें किस्त की सुविधा मिलती है। दो लाख से कम ऋण है तो 5 वर्ष में 60 किस्त देना होता है। चार लाख के ऋण को 84 किस्तों में भुगतान करना पड़ता है। कोर्स पूर्ण होने से पहले पढ़ाई छोड़नेवाले छात्रों को किस्त की सुविधा से वंचित कर दिया जाता है, उन्हें एक मुश्त ऋण का भुगतान करना पड़ता है। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रबंधक बाबू सर्वजीत अकेला ने बताया कि वर्ष 2023 में 2514 छात्रों को लोन दिया गया वर्ष 2024 में 26 42 छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए लोन देने का प्रावधान है। इसमें 2200 छात्रों का ऋण स्वीकृत हो गया है।

जहरीली शराब से रात में गई आंख की रोशनी सुबह हो गई मौत

BEGUSARIA : बिहार के बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में दो लोगों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। कथित रूप से शराब पीने के बाद दोनों की मौत होने की बात कही जा रही है। इस मामले मे एक व्यक्ति के शव का मेडिकल बोर्ड बनाकर पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच मे जुटी है। पुलिस प्रसाशन ने अब तक शराब पीने से मौत होने की पुष्टि नहीं की है। मृतक की पहचान चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के मैदा शाहपुर के रहने वाले ग्रामीण चिकित्सक चुनचुन सिंह एवं उनके कंपाउंड हरे राम तांती के रूप में की गई है। मृतक चुनचुन सिंह का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। जबकि प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गठित टीम की देखरेख में हरे राम तांती का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी।

खुशखबरी : बदल डाली गांव की तस्वीर, दिया जाएगा 25 लाख का पुरस्कार

सिवान के तीन मुखिया को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित

AGENCY JAIPUR : बिहार के सिवान के तीन पंचायत के मुखिया को बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इन तीनों मुखिया को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसको लेकर तीनों पंचायत के लोगों में काफी खुशी है और मुखिया भी काफी गदगद हैं। सम्मानित होने वाले सिवान के मुखियाओं में लकड़ी नबीगंज प्रखंड के बसौली पंचायत के मुखिया भारतेंदु प्रसाद पांडे, दरौंदा प्रखंड के रुकुंदीपुर पंचायत की मुखिया बबिता और जलालपुर पंचायत की मुखिया बबिता देवी शामिल हैं। तीन मुखिया के कार्यों की सराहना की गई है और अपने क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए इनका राष्ट्रपति के हाथों सम्मान होना है।

राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित मुखिया।

रुकुंदीपुर मुखिया ने कराया अपेक्षित विकास

दरौंदा प्रखंद की रुकुंदीपुर की मुखिया बबिता का सम्मान होने की खबर के साथ मिलते ही मुखिया और पंचायत के लोग काफी उत्साहित हैं। बता दें कि दरौंदा प्रखंड के जलालपुर में पेयजल की काफी दिक्कत थीं और कृषि के लिए जल उपलब्ध नहीं था। जिन पर मुखिया बबिता देवी ने लगातार काम किया। मुखिया बबिता ने लगभग 2000 से ज्यादा घरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई। सिंचाई के लिए कृषि क्षेत्र में पानी की सुविधा उपलब्ध कराया। अब वक्त पर खेतों में सिंचाई और अच्छी फसल उगाने को लेकर किसानों में बहुत खुशी देखने को मिल रही है।

बसौली पंचायत के मुखिया का सम्मान

लकड़ी नवीगंज प्रखंड के बसौली पंचायत के मुखिया भारतेंदु प्रसाद पांडे ने सांसद आदर्श ग्राम योजना पेज 2 के तहत 23 / 24 से लेकर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर इस पंचायत में अनेकों कार्य किए गए हैं। नाली गली, चौड़ीकारण, हनुमान मंदिर काली मंदिर स्थान में फेवर ब्लॉक बिछाना, गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान मृत्यु दर शून्य होना आदि समेत कई काम कराए हैं।

वहीं समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड अंतर्गत मोतीपुर आदर्श ग्राम पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को भी सम्मानित किया जाना है। 2016 में इस पंचायत की मुखिया चुनी गई प्रेमा देवी ने अपने कामों के बलबूते इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाया। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा से सम्मानित इस पंचायत में तमाम बुनियादी सुविधाओं के साथ ही नई व हाईटेक व्यवस्था , मॉडल भवन , व्यवस्थित सड़कें मौजूद हैं। देश भर के पंचायत मानकों में मुजफ्फरपुर ज़िले के कटरा प्रखंड के जजुआर मध्य पंचायत को तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बेहतर कार्य को लेकर पंचायत के मुखिया सुमन नाथ ठाकुर को सम्मानित किया जाएगा। सम्मान के तौर पर 25 लाख की राशि भी दी जाएगी। आपको बता दें कि जजुआर बिहार के बड़ा गांव के नाम से जाना जाता है। जो सरकार की सभी योजनाओं में उम्दा प्रदर्शन कर रही है। सरकार की सभी योजनाओं को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। इसमें गरीबी मुक्त और आजीविका, उन्नत गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरित गांव आदि विषय सम्मिलित हैं।

विभिन्न मांगों को लेकर छात्र राजद ने जलाया कुलपति का पुतला

BHAGALPUR : विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को छात्र राजद कार्यकताओं ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन किया और कुलपति प्रो डॉ जवाहर लाल का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में कुलपति के आदेश पर वन नेशन वन इलेक्शन पर परिचर्चा कराई जा रही है, जिसका विरोध युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन राजनीतिक मुद्दा है। वहीं जनसंख्या वृद्धि पर भी चर्चा होनी चाहिए इसके साथ ही समाज से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जानी चाहिए लेकिन कुलपति के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है।

पटना मेट्रो के काम में आई तेजी

अगस्त 2025 से पांच स्टेशनों के बीच होगा ट्रेन का परिचालन

निर्माण कार्य का निरीक्षण करते मंत्री नितिन नवीन।

AGENCY PATNA : बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। राज्य सरकार और मेट्रो के अधिकारी मिशन मोड में इस काम को पूरा करने में जुटे हुए हैं। अगस्त 2025 तक पटना में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। शुरूआत में पटना के पांच स्टेशनों के बीच मेट्रो ट्रेन शुरू कर दी जाएगी। इसे प्रायोरिटी कॉरिडोर नाम दिया गया है, जो लगभग 6 किलोमीटर लंबा है। प्रायोरिटी कॉरिडोर में आईएसबीटी, जीरोमाइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए पटना मेट्रो के प्रबंध निदेशक सह नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने बुधवार को पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के प्रगति कार्यों का जायजा लिया।

हार से उपजी हताशा है ईवीएम पर सवाल

महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम को लेकर आसमान सिर पर उठाए विपक्ष को तब झटका लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकार्ता से पूछा, आखिर चुनाव हारने पर ही ईवीएम पर क्यों सवाल उठाए जाते हैं। याचिकाकर्ता के साथ ही विपक्ष के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। विपक्ष को एक और झटका तब भी लगा, जब इसी सोमवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में प्रशासन ने 75 ईवीएम का वीवीवैट यानी मतदान पर्चियों से मिलान किया और यह पाया कि मतों में कहीं कोई अंतर नहीं। इन ईवीएम का चयन सभी दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया, ताकि विपक्षी नेताओं के पास ऐसा कोई बहाना बनाने की गुंजाइश न रहे कि ईवीएम का चयन मनमाने तरीके से किया गया। इसके पहले ईवीएम के मसले पर महाराष्ट्र के विपक्षी दलों ने तब अपनी फजीहत खुद ही करा ली थी, जब उसके नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ लेने से इनकार करने के दूसरे ही दिन शपथ ले ली थी। यदि विपक्षी दलों को यह जताना था कि वे ईवीएम विरोध को लेकर इतने गंभीर हैं कि उनके विधायक शपथ लेना जरूरी नहीं समझ रहे तो फिर कम से कम हफ्ते-दस दिन तो अपने स्टैंड पर कायम रहते। वैसे इस फजीहत के बाद भी यह तय मानिए कि विपक्ष का रोना-धोना बंद होने वाला नहीं है। वह कुछ नए बहाने खोजकर लाएगा और यह रोना रोएगा कि उसे जानबूझकर हरा दिया गया। वह खबरों में बने रहने के लिए कुछ नाटक-नौटंकी भी करेगा। वास्तव में वह कर भी रहा है। इन दिनों महाराष्ट्र के विपक्षी नेता चुनाव आयोग को इस आशय की चिट्ठियां भेजने में लगे हुए हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल बंद किया जाए। हर कोई जानता है कि इन चिट्ठियों से कुछ नहीं होने वाला। इनका उद्देश्य केवल जनता को बहकाना है। महाराष्ट्र के विपक्षी नेता गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को यह कहने के लिए उकसा रहे हैं कि उनका ईवीएम पर भरोसा नहीं रह गया है। पिछले दिनों बची-खुची राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने एक गांव जाकर ईवीएम को निशाने पर लिया। उनके बयान को इंगित कर कुछ लोगों की ओर से यह माहौल बनाने की कोशिश की गई कि देखिए,अब जब शरद पवार ने भी ईवीएम पर संदेह जता दिया है तो फिर उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं कि आखिर क्यों। क्या इसलिए कि ऐसा शरद पवार कह रहे हैं। शरद पवार बड़े नेता हैं, लेकिन इसका यह मतलब यह तो नहीं हो सकता कि वह जो कुछ कहें, उसे पत्थर की लकीर मान लिया जाए। वह नेता हैं, न्यायाधीश नहीं। विपक्ष का ईवीएम पर रोना-धोना धोबी से न जीतने पर गधे के कान उमेठने वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। विपक्षी नेता यह तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में फिर से चुनाव कराए जाएं, लेकिन वे यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ झारखंड के भी चुनाव नतीजे उन्हें मंजूर नहीं और दोनों राज्यों में फिर से चुनाव कराए जाने चाहिए। शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ कांग्रेस को भी महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे रास नहीं आए और उसके नेता भी ईवीएम को कोस रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह एलान कर दिया है कि राहुल गांधी ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किया था, वैसे ही ईवीएम छोड़ो यात्रा भी करेंगे। यदि कांग्रेस सचमुच ऐसी किसी यात्रा को लेकर गंभीर है, तो यह जानने की उत्सुकता रहेगी कि क्या यह यात्रा उन इलाकों से भी निकलेगी, जहां से कांग्रेस विधानसभा या लोकसभा के चुनाव जीती है। कायदे से ऐसे इलाकों वाले कांग्रेस के विधायकों और सांसदों को इस यात्रा में शामिल होने के पहले त्यागपत्र दे देना चाहिए। क्या वे ऐसा करेंगे। नहीं करेंगे, क्योंकि आसार यही हैं कि न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। यदि राहुल गांधी ऐसी कोई यात्रा निकालते हैं तो वह अपनी और कांग्रेस की जगहंसाई ही कराएंगे। ईवीएम को अविश्वसनीय बताने के साथ उसके इस्तेमाल को रोकने के लिए उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न जाने कितनी बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन ऐसे कोई प्रमाण न तो चुनाव आयोग के समक्ष पेश किए जा सके और न ही अदालतों के समक्ष कि उससे छेड़छाड़ की जा सकती है। 2009 के आम चुनावों के बाद भाजपा नेताओं ने भी ईवीएम पर अविश्वास जताया था। भाजपा नेता जीएल नरसिम्हा राव ने ईवीएम के खिलाफ एक किताब भी लिखी थी। डेमोक्रेसी एट रिस्क..नामक इस किताब की प्रस्तावना लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। विपक्ष जब-तब इस किताब का उल्लेख करता है, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी ने तो यह भी कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। क्या विपक्ष ने माना। ईवीएम को लेकर विपक्ष अक्सर यह भी कहता है कि दूसरे तमाम देशों और यहां तक कि अमेरिका में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता और खुद एलन मस्क कह चुके हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। निःसंदेह उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन अमेरिकी ईवीएम को लेकर। एक तो भारत की ईवीएम अमेरिका की तरह नहीं है और दूसरे, क्या अमेरिका में जो कुछ होता है, वह सब हमें अपना लेना चाहिए। वहां राष्ट्रपति प्रणाली है। क्या विपक्ष यह कहेगा कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए। ईवीएम के मामले में इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि उसे भरोसेमंद बनाने के लिए समय-समय पर कई बदलाव किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर आगे भी किए जाने चाहिए, लेकिन किसी को भी हार की खीझ उस पर निकालने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

ऐतिहासिक हैं भारत के तीन नए आपराधिक कानून

ANALYSIS

डॉ. विपिन कुमार

कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी मोदी सरकार द्वारा लाए गए इन कानूनों का विरोध करते हैं और यह दलील देते हैं कि इससे देश में तानाशाह की प्रवृत्ति बढ़ेगी। लेकिन, मैं उनके इन दलीलों को पूरी तरह से हास्यास्पद मानता हूं। क्योंकि, यदि आप भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के इतिहास को देखें, तो पाएंगे कि पुराने कानून औपनिवेशिक न्यायशास्त्र की प्रतिकृति हैं, जिन्हें पूरे देश पर शासन करने के लिए बनाया गया था, न कि हमारे देश के नागरिकों की सेवा के लिए। इसी भाव शून्?यता के कारण ये कानून आमजनों के उत्पीड़न और शोषण का उपक्रम बन गए, जिनका उद्देश्य वास्तव में निदोर्षों के अधिकारों की रक्षा और दोषियों को दंडित करना होना चाहिए था। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाए गए नए कानून निश्चित रूप से उपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक हैं। सार्वजनिक सेवा और जनकल्याणकारी कानूनों से एक नए युग की शुरूआत हुई है। हमें याद रखना होगा कि न्याय में देरी केवल लोगों को हताश-निराश ही नहीं करती, बल्कि किसी न किसी स्तर पर देश के विकास की गति को भी बाधित करती है। इसके अतिरिक्त देश की छवि को भी खराब करने का काम करती है।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में तीन आपराधिक कानूनों को देश को समर्पित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नए कानूनों के माध्यम से त्वरित न्याय की उम्मीद जताई, जो पूरी तरह से सार्थक भी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम- जैसे तीन नए आपराधिक कानून हमारे समाज में गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए संगठित अपराध, आतंकवाद और ऐसे अन्य अपराधों पर भी कड़ा प्रहार करते हैं। इन प्रयासों से हमें अपनी कानूनी व्यवस्था को आजादी के अमृतकाल में अधिक प्रासंगिक और सहानुभूतिपूर्वक प्रेरित करने के लिए पुनर्भाषित करते हैं। इन कानूनों को मूर्त रूप देने में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी मोदी सरकार द्वारा लाए गए इन कानूनों का विरोध करते हैं और यह दलील देते हैं कि इससे देश में तानाशाह की प्रवृत्ति बढ़ेगी। लेकिन, मैं उनके इन दलीलों को पूरी तरह से हास्यास्पद मानता हूं। क्योंकि, यदि आप भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के इतिहास को देखें, तो पाएंगे कि पुराने कानून औपनिवेशिक न्यायशास्त्र की प्रतिकृति हैं, जिन्हें पूरे देश पर शासन करने के लिए बनाया गया था, न कि हमारे देश के नागरिकों की सेवा के लिए। इसी भाव शून्?यता के कारण ये कानून आमजनों के उत्पीड़न और शोषण का उपक्रम बन गए, जिनका उद्देश्य वास्तव में निदोर्षों के अधिकारों की रक्षा और दोषियों को दंडित करना होना चाहिए था। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाए गए नए कानून निश्चित रूप से उपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक हैं। सार्वजनिक सेवा और जनकल्याणकारी कानूनों से एक नए युग की शुरूआत हुई है। हमें याद रखना होगा कि न्याय में देरी केवल लोगों को हताश-निराश ही नहीं करती, बल्कि किसी न किसी स्तर पर देश के विकास की गति को भी बाधित करती है। इसके अतिरिक्त देश की छवि को भी खराब करने का काम करती है। जब समय पर न्याय नहीं मिलता तो कानून एवं

व्यवस्था का आदर न करने और उसके उल्लंघन के आदी लोगों का दुस्साहस बढ़ता है। तीनों आपराधिक कानूनों पर अमल से एक ओर जहां 60 दिन के अंदर आरोप तय किए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर सुनवाई पूरी होने के 45 दिन के अंदर फैसला सुनाना आवश्यक होगा। आंकड़े बताते हैं कि भारत के न्यायिक व्यवस्था में 3.5 करोड़ से भी अधिक लंबित मामले हैं और यहां विचाराधीन कैदियों की संख्या 77 फीसद है, जो दोषियों की संख्या से तीन गुना अधिक है। वहीं, भ्रष्टाचार, अत्यधिक काम का बोझ और पुलिस की जवाबदेही तीव्र और पारदर्शी न्याय व्यवस्था को कायम करने की दिशा में एक बड़ी बाधा है। ऐसे में मोदी विरोधी इस बात को समझें कि नियमों में बदलाव समय की मांग थी। सरकार के इन प्रयासों से निश्चित रूप से हमारे न्याय प्रणाली में अपेक्षित सुधारों को सुनिश्चित करते हुए न्यायालयों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। देश में न्यायिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा भी बारंबार आग्रह किया गया है। क्योंकि, आजादी के बाद न्यायालय की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए ऐसे सुधारों को लागू नहीं किया जा सका है। लेकिन, मोदी सरकार ने हमें 10 वर्षों के दौरान हमें एक नई उम्मीद दी है। कानून के जानकार इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है और भारतीय संदर्भ में यह बात पूरी तरह से चरितार्थ होती है। यह कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि लंबित मामले और विचाराधीन कैदियों की अत्यधिक संख्या हमारे समाज में अन्याय की भावना को जन्म देता है। हमने अखबारों की सुर्खियों में ऐसा कई बार पढ़ा है कि किसी मामले में न्यायालय जब तक अपना फैसला सुनाता है कि आरोपित की मृत्यु हो चुकी होती है। वहीं, कई बार ऐसी स्थिति भी होती है, जब कोई आरोपी अपने आरोपों के दंड से अधिक समय जेल में बिता देते हैं। फिर वर्षों तक जेल में रहने के बाद उन्हें न्यायालय से आरोप मुक्त कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति न्याय की दृष्टि से अन्याय को जन्म देती है। इस स्थिति में त्वरित सुधार की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानून समय की अनिवार्यता हैं और हमें इन प्रयासों का स्वागत करना चाहिए। हालांकि अभी बस केवल एक शुरूआत हुई है। हमें निकट भविष्य में अपने न्याय व्यवस्था की कार्य पद्धति के विविध पक्षों में सुधार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनमें नियुक्तियां, स्थानांतरण व अवसंरचनात्मक विकास जैसे प्रमुख घटक हैं। इसके अलावा भारतीय न्यायिक सेवा में भाषायी मुद्दों का भी एक विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे कि यदि कोई कन्नड़ बोलने वाला व्यक्ति ओडिशा में न्यायाधीश का पदभार संभाला है, तो इससे वहां न्यायाधीशों और जनता के माध्यम से संचार में रुकावट पैदा होती है। इसलिए प्रयास यह होना चाहिए कि ऐसी नियुक्तियों के दौरान हमारी भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाए। साथ ही हमें अपने न्याय व्यवस्था में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल भी बेहद कुशलतापूर्वक करना होगा। इससे न्यायालय और न्यायाधीशों के अलग-अलग प्रदर्शनों का मूल्यांकन करना बेहद आसान हो जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम इस दिशा में तेजी के साथ कार्य करेंगे और समाज में अधिकार और न्याय को स्थापित करने की दिशा में आने वाली हर एक बाधा को दूर करते हुए पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण पेश करेंगे।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

हर भारतवासी को उद्वेलित करता है भगत सिंह का अपमान

लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी ने बीते दिनों विदेश मंत्री से एक महत्वपूर्ण सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार लाहौर हाईकोर्ट में शहीद भगत सिंह के प्रति हुई अपमानजक टिप्पणियों से अवगत है या नहीं और यदि है तो उसने क्या कूटनीतिक कदम उठाए हैं। उनके इस प्रश्न को अतारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकृति मिली और विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 6 दिसंबर को लिखित जवाब दिया। यह अच्छी बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में भगत सिंह के अपमान का संसद ने संज्ञान लिया, लेकिन और भी अच्छा होता यदि इस मुद्दे को कहीं अधिक तवज्जो दी जाती। ऐसा इसलिए, क्योंकि भगत सिंह भारत के महानतम नायकों में से एक हैं और उनका अपमान तो छोड़िए, उनके विषय में कटु शब्द तक किसी को स्वीकार्य नहीं होंगे। इस मामले की जड़ें पाकिस्तान में सक्रिय भगत सिंह फाउंडेशन से जुड़ी हैं। फाउंडेशन करीब 20 वर्षों से इस प्रयास में लगा है कि लाहौर के एक प्रमुख चौराहे- शादमान चौक को भगत सिंह का नाम दिया जाए। फाउंडेशन के अनुसार, भगत सिंह समूचे उपमहाद्वीप के नायक हैं और उनकी स्मृतियों के प्रति पाकिस्तान में भी सम्मान प्रदर्शित किया जाना चाहिए। भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ लाहौर केंद्रीय कारागार में मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। 1961 में उस जेल को ढहाकर वहां आवासीय कॉलोनी बना दी गई। शादमान गोल चक्कर जेल परिसर वाले फांसीघाट इलाके में ही आता है। शहीदों के इस स्थान से जुड़ाव को देखते हुए ही फाउंडेशन चौराहे का नाम बदलने का आग्रह करता आ रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने 2012 में लाहौर हाईकोर्ट का रुख किया। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह नियमों के अंतर्गत कदम उठाए। उसके बाद से समाचार आते रहते हैं कि जिम्मेदार संस्थाएं इससे जुड़ी अनुकूल संभावनाएं तलाश रही हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से ऐसे समाचार गलत ही होते हैं। नवंबर की शुरूआत में यह मामला लाहौर हाईकोर्ट के सामने आया। स्थानीय नगर निगम ने अदालत को सूचित किया कि भगत सिंह फाउंडेशन की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस विचार को ही त्याग दिया गया है। इस विचार को नकारने में निगम ने पाकिस्तानी नौसेना के सेवानिवृत्त कमोडोर तारिक मजीद की राय को आधार बनाया। मजीद ने भगत सिंह के बारे में यह कहने का दुस्साहस किया कि वह क्रांतिकारी नहीं, बल्कि अपराधी थे, जिन्हें वर्तमान परिभाषाओं के हिसाब से आतंकी कहा जाता। उन्होंने एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या की थी और उसी अपराध में अपने दो साथियों के साथ उन्हें फांसी पर लटका दिया गया।

मजीद ने भगत सिंह को नास्तिक बताते हुए उन्हें इस्लाम विरोधी भी करार दिया। उन्होंने यहां तक सुझाव दिया कि भगत सिंह फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि यह पाकिस्तान की मूल विचारधारा के विरुद्ध है। लाहौर हाईकोर्ट ने अब इस मामले को 17 जनवरी तक लंबित कर दिया है। इस मामले में आगे जो भी हो, लेकिन इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि सिखों को लुभाने के प्रयास में जुटे पाकिस्तान में इस समुदाय के एक महान नायक की स्मृति एवं विरासत को इस प्रकार कलंकित किया जा रहा है। मनीष तिवारी के सवाल पर कीर्ति वर्धन सिंह के जवाब को देखें तो विदेश राज्य मंत्री ने यह जवाब दिया, भारत सरकार ने पाकिस्तान में भगत सिंह के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियों का संज्ञान लिया है और कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से इस घटना के प्रति पाकिस्तान सरकार के समक्ष कड़ा विरोध जताया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने पाकिस्तान में सांस्कृतिक विरासत पर बढ़ते हमलों, अल्पसंख्यक समुदाय की गरिमा पर आघात और उनके विरुद्ध बढ़ रही असहिष्णुता का मुद्दा भी उठाया है। सरकार और समूचा राष्ट्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह के अमूल्य योगदान को मान्यता देता है। उनकी पुण्यतिथि पर हर साल देश-विदेश में कार्यक्रम होते हैं। विदेश में सक्रिय भारत के कूटनीतिक मिशन भी भगत सिंह के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले कार्यक्रम करते हैं। सरकार के इस जवाब में वैसी प्रतिक्रिया प्रतिध्वनित नहीं होती, जैसी भगत सिंह के लिए आतंकी और अपराधी जैसे शब्दों के प्रयोग पर होनी चाहिए थी। सरकार की ओर से उन तिथियों का उल्लेख नहीं किया गया, जब कूटनीतिक माध्यमों के जरिए उसने पाकिस्तान से विरोध जताया। न ही यह उजागर किया कि क्या इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज कराई या नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में किसी को इस मामले में तलब किया। इससे भी महत्वपूर्ण इस स्पष्टता का अभाव है कि सरकार ने लाहौर हाईकोर्ट में भगत सिंह के विरुद्ध हुई टिप्पणियों को हटाने की मांग की है या नहीं। कूटनीतिक विरोध की सामग्री भी सार्वजनिक नहीं की गई। इस पर अफसोस ही हो सकता है कि सरकार ने इसे सामान्य मामलों की तरह ही लिया। भगत सिंह के विरुद्ध ऐसी टिप्पणियों का लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संज्ञान लिया जाना चाहिए था। लगता है विदेश मंत्रालय ने इस मामले को हल्के में ले लिया। यह विदेश मंत्री जयशंकर के उस दृष्टिकोण के उलट दिखता है कि देश अब नई राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत हो गया है। अच्छा होगा कि सरकार के नेतृत्व में देश की समूची राजनीतिक बिरादरी भगत सिंह के विरुद्ध टिप्पणियों की कड़ी निंदा करे। यदि यह संसद में किया जाए तो और भी बेहतर होगा। शादमान चौक का नाम बदलने या न बदलने का फैसला पाकिस्तान का है, लेकिन उन भगत सिंह के विषय में आतंकी एवं अपराधी सरीखी कोई अनर्गल टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, जिन्होंने 23 वर्ष की अल्पायु में ही राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।

Social Media Corner

सच के हक में...

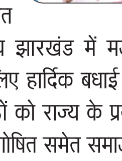

रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में शामिल हुआ। संघर्ष से उपजी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। यही कारण है कि हमने हमेशा हक-अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है। लड़कर जीत हासिल की है, कभी हार नहीं मानी है। विगत विधानसभा चुनाव में आप सभी कर्मठ नेताओं और जुझारू कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत तथा करोड़ो राज्यवासियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप झारखंड में मजबूत अबुआ सरकार का गठन हुआ। आप सभी को इसके लिए हार्दिक बधाई और जोहार। आने वाले समय में हमें झामुमो परिवार की जड़ों को राज्य के प्रत्येक कोने में पंहुचा मजबूत करने का काम करना है; वंचित, शोषित समेत समाज के सभी वर्ग को हक-अधिकार देने का काम करना है।

(सीएम हेमंत सोरेन का 'एक्स' पर पोस्ट)

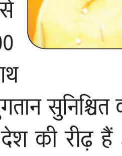

झामुमो-कांग्रेस गठबंधन ने किसानों से वादा किया था कि धान की खरीदी 3200 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर की जाएगी। लेकिन चुनावी वादों पर अमल न होने से किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि चुनावी वादों के अनुरूप किसानों से 3200 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान की खरीदी करें। साथ ही, किसानों के लिए पारदर्शी व्यवस्था और समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि किसान हमारे देश की रीढ़ हैं और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करना सभी के भविष्य के साथ अन्याय है।

(पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

अरावली को चट कर गया खनन माफिया

इस खबर से देश के हर संवेदनशील और जागरूक व्यक्ति को उद्वेलित होना चाहिए कि हरियाणा के नूंह के पास 22 अरब रुपये कीमत के पहाड़ को खनन माफिया चट कर गया। निस्संदेह, यह परेशान करने वाला घटनाक्रम नूंह जिले में राजस्थान सीमा पर स्थित पहाड़ से जुड़ा है, जो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम तंत्र की काहिली व सत्ताधीशों की गैरजिम्मेदारी से पनपा है। खनन विभाग की रिपोर्ट बताती है कि उपमंडल फिरोजपुर झिरका के कुछ इलाकों में खनन माफिया ने इस कृत्य को अंजाम दिया। कैसी विडंबना है कि गैरकानूनी तरीके से धन अर्जित करने की दबंगों की लिप्सा हमारे पर्यावरण व लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने से भी गुरेज नहीं करती। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम यह भी है कि अवैध खनन माफिया से टक्कर लेने वाले कई अधिकारियों को तबादले के रूप में खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। नागरिक संगठनों की उदासीनता भी उन खनन माफिया का हौसला बढ़ाती है, जो सत्ता के गलियारों में खासा रसूख रखते हैं। निश्चित रूप से हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र के संतुलन में निर्णायक भूमिका निभाने वाली इन पहाड़ियों को आज पुनर्जीवित करने की जरूरत है। पर्यावरण पुनर्स्थापना हेतु भूमिक्षरण और मरुस्थलीकरण से निबटने के लिए बाकायदा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में ग्यारह लाख मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए इस चौदह सौ किलोमीटर लंबे और पांच किलोमीटर चौड़े हरित गलियारे को बनाने का लक्ष्य है कि अरावली पहाड़ियों की पारिस्थितिकीय जीवन शक्ति को फिर से बहाल किया जा सके। एक समय था कि ये पहाड़ियां जंगल, वन्य जीवों, जलचरों और प्राकृतिक जल निकासी के जरिए एक समृद्ध पारिस्थतिकीय तंत्र बनाती थी। लेकिन, दुर्भाग्य से अब अरावली पर्वत श्रृंखला देश की सबसे खराब स्थितियों के लिए जानी जाती है। इस दिशा में सत्ताधीशों की उदासीनता और नियामक संस्थाओं की लापरवाही से हरियाणा में यह स्थिति खासी शोचनीय है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की तीस से अधिक पहाड़ियां पहले ही लुप्तप्राय हो चुकी हैं। खासकर हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों से लगते इलाकों में। निरंतर होते शहरों के विस्तार ने हरे-भरे परिदृश्यों को कंक्रीट के जंगलों में तब्दील कर दिया है। इसके चलते पूरे इलाके का पारिस्थितिकीय संतुलन बाधित हुआ है। सदियों में विकसित हुई वन संपदा व जीव-जंतुओं के अधिवास अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। निस्संदेह, इस कथित विकास की कीमत हमें लंबे समय तक चुकानी होगी। इसके अंतर्गत स्वदेशी वृक्षों की अनेक महत्वपूर्ण किस्में व दुर्लभ वन्य जीवों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर जा पहुंची हैं। साथ ही अनेक महत्वपूर्ण भूजल पुनर्भरण क्षेत्र सूख गए हैं। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब की हरित पहल से प्रेरित होकर ही ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को इस विनाशकारी अतिक्रमण को रोकने के लिए लाया गया था। स्वदेशी वन संपदा को सामुदायिक जुड़ाव के जरिये संरक्षित करने की योजना थी। इसके अंतर्गत 35000 हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना भी मकसद था। निस्संदेह, इस पर्यावरणीय संकट से निबटने के लिए पर्वत श्रृंखला के निकटवर्ती राज्यों में सहयोगात्मक प्रयास जरूरी हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक भी वनीकरण, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण जैसी पहलों के लिए वित्त पोषण करके अरावली परियोजना को संबल दे रहा है। लेकिन, यह भी हकीकत है कि इस परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर कती है कि हम अवैध खनन और अतिक्रमण रोकने के लिए संरक्षण कानूनों को कितनी सख्ती से लागू करते हैं, जिसमें भूमि संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनी सुरक्षा उपायों को संरक्षित करना महत्वपूर्ण होगा।

स्थल और उपासना

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ 12 दिसंबर से उन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी, जो पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की वैधता पर सवाल उठाती हैं। यह कानून देश में पूजा स्थलों की वही स्थिति बरकरार रखता है, जो देश की आजादी के दिन थी और इस स्थिति में बदलाव की मांग करने वाले मुकदमों पर रोक लगाता है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये याचिकाएं धर्मनिरपेक्षता के जिंदा रहने के लिए घातक चुनौती बन गई हैं। इनका नतीजा देश में सामुदायिक संबंधों और धर्मनिरपेक्ष सोच के भविष्य की दिशा तय करेगा। साल 1991 के अधिनियम में कुछ अपवाद थे- यह तत्कालीन बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद पर लागू नहीं होता था, जिसका अंत राम मंदिर के पक्ष में हुआ। न ही यह उन स्मारकों, स्थलों और अवशेषों पर लागू होता है जो प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत आते हैं। यह अंतिम रूप से निपटारा हो चुके किसी मुकदमे पर 1991 का अधिनियम लागू होने से पहले पक्षों द्वारा निपटा लिए गए किसी विवाद पर या रजामंदी से हुए किसी स्थल के बदलाव पर भी लागू नहीं होगा। कुछ हिंदू संगठनों और भक्तों द्वारा प्रेरित मुकदमेबाजी के जरिए मस्जिदों (जैसे वाराणसी में ज्ञानवापी, मथुरा में शाही ईदगाह और संभल में शाही जामा मस्जिद व अन्य) को निशाना बनाने की नए सिरे से कोशिश की पृष्ठभूमि में इस कानून को चुनौती दी गई है। साल 1991 के कानून को रद्द या कमजोर करने के किसी भी आदेश का इन अदालती कार्यवाहियों पर बुरा असर पड़ सकता है। याचिकाएं अतीत में आक्रमणकारियों द्वारा मंदिरों के विध्वंस का प्रमुखता से उल्लेख करती हैं और दावा करती हैं कि कई मस्जिदों को उनके ध्वंसावशेषों पर बनाया गया है। उनका तर्क है कि पूजा स्थल अधिनियम ऐसे विध्वंसों को वैध बनाता है और कानूनी कार्यवाहियों के जरिए अपने पूजा स्थलों को वापस पाने के हिंदुओं व अन्य समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन भी करता है।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

Why Punjab has fallen deeper into the abyss

AS I heard the news of the attempt to assassinate Sukhbir Singh Badal, my mind flashed back to the April of 1983 and the killing of AS Atwal (DIG), an outstanding police officer and a gem of a person. Atwal was martyred while on duty with the limited resources he had while facing an armed militancy. Sukhbir survived — barely. The individual heroics of a policeman saved the day, but how a known terrorist with Pakistani training and support was allowed to not only recce the area but also approach a Z plus protectee is a question that remains to be answered.They say that history repeats itself but in the case of Punjab, we seem to be approaching the cycle with alarming speed. The conditions being created are similar, but as, yet, we do not have a full-blown militancy.The Punjab countryside is awash with unemployed youth who indulge in petty crimes and feed the drug industry. A lot of them have organised themselves into armed gangs, available for kidnappings, killings and inter-gang warfare. Their tentacles reach into Canada, the USA, Australia and, of course, Pakistan. They even operate from within jails — how is this possible?The youth are unemployed as agriculture has been, for the past many decades, a failing proposition for most marginal farmers. Punjab was never given priority for industrialisation as it was considered a border state and was landlocked. Even today, with its huge diaspora, air connectivity to the rest of the world remains a distant dream, with paltry routes being assigned to its international airports. Employment in the defence and paramilitary forces is no longer of the scale it used to be. Also, most youth are unemployable in skilled professions because of a failed education system. In the 1960s and 70s, the region had four of the top medical institutions — Amritsar medical college, CMC, Ludhiana, Rajindra Hospital, Patiala, and the PGIMER, Chandigarh. Today, barring the PGI, the rest are poor reflections of their old days as poor funding and administration has eroded them. Punjab University commanded immense respect, boasting a successful alumnus in all fields of life; today, it's a shadow of its former self. The odd IIT or private institution that has come up is a case of too little. There seems to be no well-conceived plan to create suitable employment. Why are the youth running to foreign shores for basic education and jobs? Why are they not productively employed here?I recall the theory of 'Masterly Inaction', initially practised by John Lawrence (Viceroy of India) in the 1860s through his policy on dealing with Afghanistan after the death of its Emir, Dost Mohammad Khan, and the subsequent civil war. This policy helped the British consolidate their Indian empire. Its adaption on the home front is leading to the creation of a failed state. The concept of proactive administration, which identifies problems, finds solutions, engages in planning for its citizens, has changed to 'masterly inactivity', a conjuror's trick of creating an illusion of activity where there is none.Punjab is not at fault, Delhi also is missing in action. There is no acknowledgement of our problems. A proxy war was waged on the country through instigating, funding and promoting militancy in the state by Pakistan for two decades. What happened from 1970 to 1995, the days of horror and nights of massacres inflicted on us, is well known.

The Government of India resources were poured into fighting the militancy, but it was the blood of Punjabis that soaked its fields. Things were brought under control, but the political, administrative and economic fabric was destroyed. The situation required an initiative — a 'master plan'. It required political and administrative leadership of the highest order, but this was not to be. There has been no coordinated plan to pull Punjab out of this morass, no injection of financial or administrative support to help revive it. People forget the sheer scale of human tragedy during this time — over 3,000 police and paramilitary personnel were martyred. The Centre should have taken the lead and Punjab followed in its effort to revive.

The significance of variability in data-based estimates

The average is not the 'only' message. If individuals from all walks of life understand that, the data-based world will become more transparent and clear to people.

IONCE served in a debate competition as one of the three judges. The ranking made by me prevailed even after the final rankings of the candidates were prepared by aggregating the scores given by all judges. The other two judges were taken aback. However, as a statistician, I was aware of the cause. The other two judges' ratings were much less variable; they were typically in the range of, say, 60 to 65. However, the distribution of the scores given by me had a lot more variability because they ranged from 5 to 95Ideally, the scores should be added up after each judge's score has been divided by an appropriate measure of variability. Unfortunately, there was no such clause. This also holds true in many other real-world scenarios.

In fact, statistics recognises many measures of central tendency, or "average", such as the mean, which is the total divided by the number of observations, and the median, which is the middle-most value. We often state that country X has a larger per capita income than, say, country Y.

However, is the average income a reliable measure of the state of the economy if social inequality is ignored?In his 2013 book Capital in the Twenty-First Century, Thomas Pikettty used quantiles, such as the percentage of total wealth held by the poorest half of the population, the top 10%, the top 5%, the top 1%, or even the top 0.1% or 0.01%, because he believes that the Gini coefficient — a single number between 0 and 1 — is insufficient to explain the economic inequalities and their evolution. Four or five of these quantiles are seen to be adequate to understand the key components of economic inequality and its development, depending on the type of inequality and the time period that is being studied.Therefore, we basically require a sense of how wealth is distributed, which is just variability. Unfortunately, the majority of data-based estimates of different political and socioeconomic indicators are typically published without sufficiently addressing the estimates' variability.

Three researchers from the University of Southern Denmark have illustrated four classes of circumstances in which the conclusion reached based solely on the mean is qualitatively changed when variability is also taken into account. Their paper, "Variability Matters", was published in the International Journal of Environmental Research and Public Health in 2020.Variability is a significant issue when it comes to economic disparities, health and longevity disparities among social groups and population selection potential, which is based on the fitness distribution's tails. This is becoming increasingly clear to experts working on data. It has also been suggested that predicting and comprehending the Covid-19 pandemic required an understanding of the disease transmission variability.Again, Havelock Ellis, an English physician and author, first put up the theory of greater male variability in 1894 to explain the overabundance of males among the eminent and among the mentally ill. This theory has been used to attempt to explain why Harvard has so few female

mathematics professors, for instance.The statement, "A statistician confidently waded through a river that was on average 50 cm deep. He drowned," is commonly credited to Dutch author and television personality Godfried Bomans. To be fair, though, a statistician would never do that because she understands the importance of variability and that the river's depth might surpass her height in the midway.

The significance of understanding variability in medical prognosis is demonstrated by the extraordinary story of renowned evolutionary biologist Stephen Jay Gould. Gould was diagnosed with abdominal mesothelioma, an incurable cancer, in 1982. From the medical literature, he learnt that the median survival duration was eight months. "I will probably be dead in eight months," he thought initially.However, means and medians are abstractions of reality, as Gould was aware. Because Gould was an optimist and because he understood nature, statistics and the meaning of variance in life's processes, he consequently took a very different approach to the mesothelioma statistics. Well, half of the population will undoubtedly survive longer than eight months if the median is eight months. Due to his youth, disease identification at a relatively early stage, first-rate medical care he received, and a strong will to live, he didn't give up. "The distribution of variation had to be right-skewed… the upper (or right) half can extend out for years and years… my favourable profile made me a good candidate for that part of the curve," he thought. Gould's 1991 essay "The Median Isn't the Message" was included in his book Bully for Brontosaurus: Reflections on Natural History, which has been reprinted numerous times for a wide range of readers. Twenty years (not 20 months!) after being diagnosed, Gould passed away due to a different cancer.Perhaps, significant in this context is a quotation from William Winwood Reade that was referenced in Arthur Conan Doyle's novel The Sign of the Four. "While the individual man is an insoluble puzzle, in the aggregate he becomes a mathematical certainty," Sherlock Holmes said to Watson. "You can, for example, never foretell what any one man will do, but you can say with precision what an average number will be up to," said Holmes.Finally, let's consider a snapshot of election prediction. In the recent US presidential election, the final-minute survey indicated that Donald Trump would receive 47.2% of the national vote and Kamala Harris 48.4%. But in the end, Trump and Harris received 49.9% and 48.4% of the vote, respectively. Was the poll prediction, at least for the vote share percentages, overly weird statistically? Obviously not. The common poll predictions are usually subject to a plus-minus 3% margin of error if proper care is taken to design them. This means that if the same process is applied frequently, the true population average will, 95% of the time, fall within the sample estimate, plus or minus 3%, which is derived using the variability of the estimates, and sample sizes in opinion polls are ideally set accordingly. As per this, the aforementioned opinion poll suggests that Trump's expected vote share could reach 50.4%. At least, it didn't go beyond that limit!

All being said, the average is not the "only" message. If individuals from all walks of life understand that, the data-based world will become more transparent to the people.

Assad's fall

Fragile hope in Syria's new dawn

THE downfall of Bashar al-Assad marks the end of over half a century of authoritarian rule in Syria, ushering in a fragile era of hope and uncertainty. Assad's hasty departure, following a swift rebel offensive led by Hayat Tahrir al-Sham (HTS), symbolises both the collapse of despotism and the challenges of rebuilding a fractured nation. For over 13 years, Syria endured a brutal civil war that claimed over 5,00,000 lives and displaced millions. Assad's regime, once propped up by Russia and Iran, crumbled under the weight of its own corruption and violence. Yet, the victory of the HTS, an Islamist faction, offers no guarantee of stability. While its leader, Abu Mohammad al-Jolani, has shifted the group's narrative toward national liberation, critics question the HTS' capacity to govern inclusively.The immediate challenges are monumental. Syria's institutions lie in ruins and its economy shattered by war and sanctions.

Internally displaced citizens and refugees yearn for a return to normalcy, but fears of ethnic and sectarian divides linger. The promise of democracy is clouded by the ghosts of Libya and Iraq, where transitions led to chaos rather than cohesion.The US faces a critical moment in its West Asia strategy. Having supported Kurdish forces against the ISIS and maintained a military presence, Washington must now navigate the aftermath of Assad's fall. Its role could define whether Syria's future is one of peace or continued strife, balancing counterterrorism with humanitarian engagement. External forces further complicate Syria's path. Turkiye, the Gulf states and western powers have vested interests, while Israel and Iran remain wary of instability spilling across borders.

While Trump has said the Americans must keep off, the question is how the HTS was able to find the gunpowder to mount the final assault on Damascus, forcing even the Russians to withdraw. Who has this kind of military might?

Stakes are the highest for Israel

Assad was pillar of Iran-led 'axis of resistance' that posed a challenge for Jerusalem & US

THE US and its Turkish and Israeli allies are the prime movers in what has been characterised as the Syrian revolution that brought a stunning end to the 54-year rule of the Assad dynasty. They are the apparent beneficiaries of a process that started with a civil war, which began in 2011 and reached its climax on December 8 when the regime collapsed and the country's dictator, Bashar al-Assad, fled to Moscow with his wife and three children.

Assad was the main pillar of the Iran-led "axis of resistance" that posed a major challenge for both Jerusalem and Washington. He was also Russia's most trusted regional ally and his departure means Moscow is obliged to evacuate its last naval and military strongholds in West Asia.

Turkey, for its part, will finally have a sympathetic regime in charge in Damascus that can help Ankara confront the problems it faces with its Kurdish minorities living along the Syrian border. Even better for Turkey is the prospect of lakhs of Syrian refugees returning home and reducing the economic burden of hosting them that Ankara has been forced to bear for the past over a decade.The stakes are the highest for Israel where Assad's downfall has attracted mixed responses, ranging from jubilation to fears about what could emerge in the new Syria. "This is a historic day in the history of the Middle East," Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu declared during a visit to the Syria border. "The Assad regime is a central link in Iran's Axis of Evil — this regime has fallen." In a bit to take credit for what has happened in Syria, Netanyahu added, "This is a direct result of the blows we have inflicted on Iran and Hezbollah, the main supporters of the Assad regime. This has created a chain reaction throughout the Middle East of all those who want to be free from this oppressive and tyrannical regime."In this time of uncertainty, including a power vacuum in Damascus, Israel has taken the initiative by launching a series of pre-emptive military measures. These include deploying army bulldozers, painted in distinctive orange colours, to dig three-metre deep ditches along the Syria border to block militants from attacking the Jewish state that has the most to lose from what unfolds in Damascus.The nightmarish scenario for Israeli generals, echoed in Washington, is a repeat of last year's invasion from Gaza when Hamas gunmen used 4-by-4 Toyota pickups to crash through border fences and launch the deadliest attack against Jews since the World War II Holocaust. At least 1,200 Israelis were killed and thousands injured, while 240 were kidnapped and taken as hostages. Currently, 100 hostages still remain in custody.

Israelis, monitoring the progress of Syrian rebels, as they too drove to Damascus in similar four-by-four convoys and backed up by rocket-propelled grenades (RPGs), are fearful that what happened across the Gaza border last year could be repeated on the northern border with Syria. Digging the trenches — code-named Project New East — is one of the several measures approved by cabinet ministers who have been holding emergency meetings to assess the unfolding crisis in Syria.

In another unprecedented move, thousands of Israeli soldiers have created a 14-km deep buffer zone on the Syrian side of the border, known as Mount Hermon and famous on the Israeli side as a winter ski resort. Israeli media has published pictures of soldiers displaying their national flag with a caption declaring: "Syria's Mount Hermon has been occupied."Such is the fear of an escalating conflict along this border that the Israeli cabinet is contemplating ordering the army to expand its presence by capturing yet more Syrian territory. In the past few days, Israeli warplanes have launched endless strikes on Syrian military bunkers, missile bases and strategic military installations that are alleged to host clusters of chemical weapons, first used more than a decade ago to intimidate opponents of ousted President Bashar al-Assad, an ally of Russia and Iran, when they demanded the end of his authoritarian rule.At the time, Assad defied US President Barack Obama by crossing a so-called red line and deploying these chemical weapons with disregard for international law. Obama could have retaliated, but chose not to risk involving the US in the Syrian civil war.Delight in Assad's downfall is shared by many Syrian political prisoners rescued from his notorious jails. Horror stories of what they endured have sent shock waves across the region. These include the account of a weeping man who described how he and 54 others were due to be executed last Sunday, but were saved at the last minute when the regime in Damascus collapsed.

Another released victim is a middle-aged woman who was jailed as an unmarried teenager and has now emerged as the mother of two children. She has no idea about the identity of the children's father, or fathers. Some elderly prisoners, long presumed dead by their families, have resurfaced to tell their horror tales.None of these accounts come as a surprise to Syrian human rights campaigners, who explain how Assad and his late father, Hafez al-Assad, were among the Arab world's most ruthless dictators. Although the Assad family's human rights record has never been of interest to Israel, Tel Aviv has always been fearful of how Syria has played host to multiple terror groups headed by the likes of Nazi fugitive Alois Brunner, an associate of the late Adolph Eichmann, who died in 2001, Germany's Baader-Meinhof, Carlos the Jackal, and members of the Japanese Red Army.

THE PHOTON NEWS

08 www.thephotonnews.com

Thursday, 12 December 2024

Amazon set to enter quick commerce with pilot in Bengaluru

The company, however, did not divulge more information on other cities the pilot would be launched or the number of dark stores it would begin with.

NEW DELHI. Amazon is set to enter the quick commerce space with its 15-min delivery service ready to begin from this month on a pilot basis. The pilot would start from Bengaluru.The company, however, said as expected its quick commerce business may not be called Tez.Samir Kumar, country manager, Amazon India, told the media here on Tuesday that while Amazon focuses on implementing the strategy to offer the largest selection at fastest speeds and greatest value to customers in every single pin-code across the country, it will be starting a pilot to give the customers a choice to get their everyday essentials in 15 min or less,"We already have millions of customers across India including Prime Members who trust us and will look forward to this convenience. Stay tuned for more," said the Amazon country manager when asked about the much expected quick commerce space.The company, however, did not divulge more information on other cities the pilot would be launched or the number of dark stores it would begin with. Sources in the company said depending on the results of pilot in Benagluru, other cities would be selected.

Amazon is a late entrant in the quick commerce space, which is dominated by players like Zomato-backed Blinkit, Zepto, and Swiggy's instamart. The model works around a strong network of dark stores -- which are a retail distribution centre for online orders. Dark stores are essential for quick commerce players, especially to increase its market share.When questioned why Amazon took so long to enter the quick commerce business, country manager Samir Kumar said: "For us, we look at what our customers want. At times, we take our time to make decisions. But when we get into it, we want to make sure we build a fine product. Our goal is to make sure that the safety standards are right -- the folks or the associates who are going to be working on the road are safe."

The company already has a 2-hour delivery service Amazon Fresh under which it delivers fruits, vegetables, dairy and other grocery products.

Expansion will depend on results of pilot

The company, however, didn't divulge more information on other cities the pilot would be launched or the number of dark stores it would begin with. Sources in the company said depending on the results of pilot in Benagluru, other cities would be selected

RBI approves Burmans' open offer to acquire 26% stake in Religare

NEW DELHI. The Reserve Bank on Tuesday approved the open offer of Burman family, the promoters of FMCG major Dabur, to acquire an additional 26% stake in NBFC firm Religare Enterprises Ltd (REL).The RBI directed maintaining of the current board/management structure of REL. The central bank said it has granted its "approval for the proposed increase in shareholding of existing shareholders" -- four Burman family entities Puran Associates, VIC Enterprises, M B Finmart, and Milky Investment & Trading Company -- in Religare Enterprises Ltd (REL)."The acquirers are advised to consolidate the NBFCs in the resulting structure/ group (both Burman and Religare group) at the earliest and not later than March 31, 2026," the RBI said in a letter to Chairman of Religare Enterprises, a copy which was shared to the

exchanges."The request for change of management/appointment of four proposed directors -- Abhay Agarwal, Arjun Lamba, Ramanathan Gurumurthy, and Suresh Mahalingam does not have our approval at this stage," it said.The RBI has "advised" Religare to submit names of the proposed directors, along with the board resolution, after ensuring that they are "fit and proper". The Burman family through its entities had announced a Rs 2,116-crore open offer to REL shareholders in September last year to acquire up to 26% stake in the company. However, it was contested by REL independent directors, alleging fraud and other breaches by Burman entities and approached regulators, including markets regulator Sebi, the RBI and the IRDAI.

Reliance Industries biggest wealth creator, Adani Green fastest: Motilal Oswal study

NEW DELHI: Reliance Industries, Adani Green and Linde India – biggest, fastest, and most consistent wealth creator, respectively, between 2019 and 2024, as per Motilal Oswal's 29th Annual Wealth Creation Study which was released on Tuesday. It added that Adani Group's flagship company - Adani Enterprises - is the top all-around wealth Creator.

As per the study, dring 2019-24, top 100 wealth creators of India Inc created Rs 138 lakh crore. The pace of wealth creation is at 26% CAGR, higher than the BSE Sensex return of 14%. For the sixth time in succession, Mukesh Ambani's Reliance Industries (RIL) has emerged as the largest wealth creator over 2019-24. This takes RIL's Number 1 tally to 11 in the last 17 five-year study periods.Adani's renewable energy company - Adani Green - has emerged as the fastest wealth creator with a 2019-24 price CAGR of 118%. Rs10 lakh invested in 2019 in top 10 fastest wealth creators would be Rs 1.75

crore in 2024, a CAGR of 77% against 14% for Nifty 50, it said.The study stated the industrial gases and engineering company - Linde India is the most consistent wealth creator. "We define consistent wealth creators based on the number of years the stock has outperformed in each of the last 5 years.Where the number of years is the same, the stock price CAGR decides the rank. Based on this, over 2019-24, the relatively low-profile Linde India has emerged as the Most Consistent Wealth Creator," said the report. Linde has outperformed the Nifty Total Return Index in last 5 years and has the highest price CAGR of 68%.The analyses top 100 wealth-creating companies during the period 2019-24. Wealth created is calculated as the change in market cap of companies between 2019 and 2024 (March ending), duly adjusted for corporate actions such as mergers, de-mergers, fresh issuance of capital, buyback, dividends, etc.

Human Washing Machine Of The Future: It Just Takes 15 Minutes To Wash A Human; Japan Develops Prototype

The futuristic machine, which looks like the pod or cockpit of a fighter jet, will be showcased at the Osaka Kansai Expo in Japan, where 1,000 guests will have the opportunity to try it out.

New Delhi. Osaka-based showerhead company Science Co. has developed a 'human washing machine of the future', the 'Mirai Ningen Sentakuki', which takes 15 minutes to wash a human. The gadget uses AI to analyze the user's body before a custom wash-and-dry process.The futuristic machine, which looks like the pod or cockpit of a fighter jet, will be showcased at the Osaka Kansai Expo in Japan, where 1,000 guests will have the opportunity to try it out.According to local media, The Asahi Shimbun, the company chairman, Yasuaki Aoyama, said during an event, "We're about 70 per cent there. We plan to offer 1,000 general visitors an opportunity to use it during the expo."Science Co. has not confirmed how much the device may cost or when it might be available for

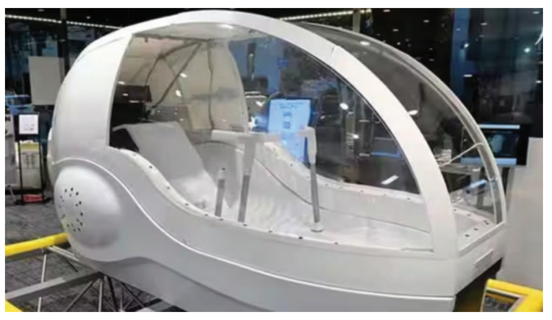

public purchase.

How does the machine work?

As soon as the user enters the machine, the clear plastic pod fills with warm water, releasing small air bubbles that create a powerful pressure wave that removes dirt from the skin. The user's chair electrodes collect biological information to ensure appropriate washing temperature.The human washing machine uses artificial intelligence to not only clean the body but also the mind. An AI-powered sensor interprets biological information and projects calming videos onto the inside of the plastic pod, ensuring a physically and mentally refreshed wash.The machine is equipped with a transparent cover to ensure comfort and prevent claustrophobia.

First machine was built 50 years ago

The 1970 Sanyo Electric Co.- now Panasonic Holdings Corp. invented a futuristic washing machine using hot water, micro-bubbles, and plastic massage balls, but it was never commercially released.

Comments of social media users

The news has received mixed responses from social media users. Reacting to the post, a user wrote, "One little glitch and you're euthanized."Another user wrote, "I can't waste 15 minutes every day. Up here in Canad,a we will get another carbon tax."One user said, "Leave it to Japan to turn hygiene into high-tech luxury.""I'll take one, only if you put wheels on it so I can drive it. Sorry, AI can drive it," said one user.Another user wrote, "These would be very welcome in retirement homes and health care facilities."

Fugitive businessman Mehul Choksi's assets worth Rs 2,566 crore to be auctioned

NEW DELHI. Properties worth Rs 2,566 crore of fugitive businessman Mehul Choksi would now be ready for auctioning after a special Mumbai court order. The properties were attached by the Enforcement Directorate (ED) in the PNB fraud case.

The ED has already started the process of handing over the properties to the liquidator and assets worth Rs 125 crore have been handed over to the liquidator of Gitanjali Gems, the company once owned by Choksi.

"The handed over properties include flats situated at Mumbai and two factories/godowns situated at SEEPZ Mumbai. Restitution of the rest of the properties is in progress," said the enforcement directorate, the agency that investigates matters related to money laundering.Gitanjali Gems went into corporate insolvency resolution process (CIRP) in 2018 and after three-and-a-half years, the National Company Law Tribunal (NCLT) ordered liquidation of the company. The company had a debt of Rs 39,000 crore, of which it owed Rs 25,000 crore to banks and financial institutions and Rs 13,000 crore to government.

One MobiKwik Systems IPO Fully Subscribed

New Delhi. The initial public offering (IPO) of fintech company One MobiKwik Systems got fully subscribed within an hour of opening of the issue on Wednesday.The initial share sale received bids for 2,16,17,852 shares, as against 1,18,71,696 on offer, translating into 1.82 times subscription, as per data available with NSE till 11:40 hours.Retail Individual Investors (RIIs) subscribed 7.69 times, while the Non-Institutional Investors (NIIs) portion received 1.55 times subscription.One MobiKwik Systems on Tuesday said it garnered Rs 257 crore from anchor investors.The Rs 572-crore IPO is available for public subscription during December 11 to 13.The company has fixed the price band of Rs 265-279 per share.The public issue is entirely a fresh issuance of equity shares worth up to Rs 572 crore with no offer-for-sale (OFS) component.

Proceeds from the fresh issue will be used for organic growth in its financial services business, for expanding its payment services and for research and development in AI, machine learning, and technology.Funds will also be used for capital expenditure on payment deices.

MobiKwik, the company's flagship application, provides consumers access to various payment options and financial products in digital credit, investments, and insurance.This is the second attempt by the Gurugram-based firm for the public issue following its first attempt in July 2021. Earlier, the company shelved its IPO plans and withdrew its draft papers due to unfavourable market conditions.It was founded by Bipin Preet Singh and Upasana Taku.

The company faces stiff competition from major players, including PhonePe, Paytm, Airtel Payments Bank and Freecharge.

The digital payments firm reported a consolidated total income of Rs 890.3 crore in FY24, compared to Rs 561.6 crore in FY23 and Rs 543.2 crore in FY22.

It incurred losses amounting to Rs 128.16 crore and Rs 83.8 crore in FY22 and FY23, respectively. However, for the financial year 2023-24, the company posted a profit of Rs 14.08 crore.

Industry should realign itself keeping political, strategic policies in mind: Nirmala Sitharaman

NEW DELHI. Finance Minister Nirmala Sitharaman on Wednesday said the industry will have to realign its policies keeping in mind political and strategic decisions of the country.Outlining the priorities of the economy for the next decade, Sitharaman also said attempts should be made to restore global calm and normalcy and noted that war or any form of disruption should be avoided.Sitharaman said the economy has to "clawback" more to regain its strength after the Covid pandemic and any skirmish or war will impact the supply chains and food value chains."The world is facing challenges which are reflected in the economy," the Minister said at the CII Global Economic Policy Forum here.Talking about ways to tackle supply chain disruptions, Sitharaman said currently there is a need to blend economic priorities with politics and strategic needs."When we talk about restoring supply chains to frictionless supply chains, let's not forget it's not just economics, it's more than that… We have to build in our own decision making not just in economic sense but also in a political and strategic sense.""Supply chains will have to be restored but you would have to reset it, realign it, you will have to make sure that it is spread so much that no geopolitical or strategic risks will threaten our wellbeing," Sitharaman said.She said lessons learnt in the last decade should tell us that the country will have to now realign, and industry will have to realign itself not just on economic principles.

There is a need to blend large, small and medium industries to achieve "scale and spread" and job creation, Sitharaman said."Industry will have to look at ways to adapt with newer challenges," she said, adding scale cannot be the only criteria.

500 stocks will be under T+0 settlement from January 31: Sebi

While the Sebi move is aimed at speeding up the settlement cycle, which currently stands at T+1, the same-day settlement cycle will continue to be optional.

NEW DELHI. The Securities and Exchange Board of India (Sebi) on Tuesday said top 500 stocks listed on the exchanges will be eligible for the same-day settlement cycle (T+0) in a phased manner. These stocks will be available for settlement from January 31, 2025.While the Sebi move is aimed at speeding up the settlement cycle, which currently stands at T+1, the same-day settlement cycle will continue to be optional.Currently, only 25 stocks are available for the T+0 settlement. The beta version of the settlement cycle was launched in March this year, but the response has been tepid, with negligible volumes.Brokers will be permitted to charge a differential brokerage for the facility. Qualified stock brokers, or those classified as large brokers given their client size and volume managed, have been directed to put in place processes and systems for smooth implementation.In December last year, the regulator had proposed to introduce a facility for clearing and settlement of funds and securities on T+0 on an optional basis. It had also proposed to introduce an optional instant settlement at a later stage.Under the T+0 trade cycle, the settlement of trades will happen on the same day after the closure of the market. If investors sell a share, they will get the money credited to their account the same day, and the buyer will also get the shares in their demat account on the very day of the transaction.The Sebi announced a block deal window from 8.45 am to 9 am for the T+0 cycle, in addition to the existing block deal windows for the T+1 settlement.A shortened settlement cycle will bring cost and time efficiency, transparency in charges to investors and strengthen risk management at clearing corporations and the overall securities market ecosystem.The T+0 trade cycle is expected to provide flexibility in terms of faster pay-out of the funds against the securities to the sellers and faster pay-out of securities against the funds to the buyers. It will allow better control over funds and securities by the investors.For the securities market ecosystem, a shorter settlement cycle will further free up capital in the securities market, thereby enhancing the overall market efficiency. It will enhance the overall risk management of clearing corporations (CCs) as the trades are backed by upfront funds and securities.

PNB Fraud: Mehul Choksi's Assets Worth Over 2,500 Crore To Be Auctioned

The federal agency said in a statement that it initiated the 'restitution of assets' to the rightful owners in this case following an order passed by a special Prevention of Money Laundering Act (PMLA) court based in Mumbai.

New Delhi. The Enforcement Directorate Tuesday said it has begun restituting assets worth more than ? 2,500 crore as part of a money laundering investigation against absconding businessman Mehul Choksi in connection with the alleged ? 13,000 crore PNB loan fraud case.

The federal agency said in a statement that it initiated the 'restitution of assets' to the rightful owners in this case following an order passed by a special Prevention of Money Laundering Act (PMLA) court based in Mumbai."In pursuance to the order, the process of handing over of assets has been initiated and properties worth more than ? 125 crore have been handed over to the Liquidator of Gitanjali Gems Ltd (a company of Choksi).

'Everything changed that day'

Manoj (19)Background: Family moved from UP's Jhinjhana to Delhi in 2008; father stayed back in village, working as a farm labourer. Belong to the SC community.Case: Died cleaning a sewer in Rohini's Sector 3 in 2012

Case status: Trial pendingCompensation: Family says they received only Rs 2 lakh of the Rs 10 lakh compensation amount"I moved to Delhi so I could give a good life to my children… Everything changed the day I lost my son… since my son passed away, my health has been poor," Manoj's mother Ram Kali (60), who lives in a JJ cluster in Rohini, said.

"The handed over properties include six flats in Kheni Tower at Santacruz in east Mumbai and two factories/godowns situated at Santacruz Electronic Export Processing Zone (SEEPZ) in the capital city of Maharashtra," it saidThe ED has attached or seized assets worth ? 2,565.90 crore in this PMLA case against Choksi and the court has allowed "monetisation" of all these properties.The agency said it took "proactive steps" to initiate the restitution process and the probe agency, along with the affected banks, "agreed to take a common stand" and moved the court.The court, on September 10, ordered that the ED would "facilitate" the banks, liquidators in different Gitanjali Group companies to carry out valuation and auction of the attached or seized properties. It also directed that after auction of the said properties, the sale proceeds would be deposited in the Punjab National Bank (PNB) and ICICI Bank (affected lenders) as fixed deposits.

Choksi has been staying in Antigua since 2018 after leaving India.Choksi, his nephew, fugitive diamond trader Nirav Modi and their family members and employees, bank officials and others were booked by the ED and the Central Bureau of Investigation (CBI) in 2018 for perpetrating the alleged loan fraud at the Brady House branch of the PNB in Mumbai.

It was alleged that Choksi, his firm Gitanjali Gems, and others "committed the offence of cheating against PNB in connivance with certain bank officials by fraudulently getting the LoUs (letters of undertaking) issued and got the FLCs (foreign letter of credit) enhanced without following prescribed procedure".

The agency has filed three chargesheets against Choksi till now.Nirav Modi, declared a fugitive economic offender, is lodged in a London jail after he was held by the authorities there in 2019 on the basis of a legal request made by the ED and the CBI in this case. He is contesting extradition to India.

Delhi gears up for winter: Authorities, NGOs ramp up shelters for homeless

NEW DELHI. As peak winter approaches, authorities and NGOs in the capital are gearing up to provide shelter to thousands of destitute.The Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB), the nodal agency for improving the quality of the life of slum dwellers, recently announced that it has installed 235 pagoda tents across the city to provide refuge to homeless individuals during the harsh winter nights, as part of the Delhi government's 2024-25 winter action plan. Launched on November 15, the plan includes the setup of 250 tents, with the remaining 15 reserved for emergencies.However, in the past, DUSIB shelters have proven to be inadequate in providing housing to all of the city's homeless. The last official survey by the agency was conducted in 2014 and estimated a total of 16,670 homeless individuals. NGOs say that the real figure is far higher.

According to the Centre for Holistic Development (CHD), 180 homeless people died as a result of the cold last winter. The organisation also claimed that at least 192 homeless people succumbed to the heatwave in June this year. The National Human Rights Commission (NHRC) had even issued a notice to the Delhi government on the basis of the report.

In November, the Delhi High Court instructed the Chief Secretary and other authorities to swiftly act on a plea seeking a detailed survey of the homeless population in Delhi. The court also called for an assessment of the effectiveness of existing shelter home services, ensuring compliance with legal standards.Similarly, the apex court sought details from the DUSIB on the facilities available for housing the homeless in the city, considering the approaching winter months.

"We are concerned. We are on the eve of what is going to be a very chilly winter," a top court bench, led by Justice B R Gavai and Justice V Viswanathan had observed.DUSIB currently operates 197 shelters with a capacity for 7,092 individuals. Appearing for one of the petitioners, advocate Prashant Bhushan said the total capacity of shelter homes in Delhi was around 17,000 people and the DUSIB has demolished nine such facilities.

In an interview with Nitesh Kumar, Program Coordinator of the Society for Promotion of Youth and Masses (SPYM), Prabhat Shukla discusses the process and challenges in countering homelessness. Excerpts.

How many such shelters does your organisation run in Delhi?

In winter, we increase the number of homeless shelters in operation. We currently have about 75 such shelters in the capital with a daily footfall of 200. In addition, we operate five de-addiction shelters since a majority of the homeless population are drug addicts. We also run recovery shelters that cater to the sick homeless.

How are these shelters operated?

The footfall increases in winter. DUSIB has hired siven agencies that operate homeless shelters in 15 clusters. We set up homes wherever we feel the requirement for shelter. Each cluster also has a rescue team and van which transports willing people to nearby shelters.

AI To The Rescue: How Cops Busted 2.7 Crore Jewllery Theft In Rajasthan

New Delhi. A criminal gang that orchestrated a ? 2.70 crore theft at a jeweller's shop in Rajasthan's Churu was caught after Artificial Intelligence was used to generate pictures of the thieves.

Churu Superintendent of Police Jai Yadav said that the victim Chhaganlal Soni's jewellery shop in Uttarada market was robbed of cash, gold and silver on November 30. The masked thieves climbed on to the shop's roof from an empty plot behind the shop and broke the staircase door and entered inside.While CCTV footage of the theft and the shop's vicinity was

retrieved, ascertaining the identities of the thieves was difficult as they wore masks on their faces and gloves to avoid fingerprints. Further, the car used by the gang also had a fake number plate.

Police searched about 1,000 CCTV cameras in Ratangarh, Rajaldesar, Parsneu, Bidasar, Jaswantgarh bypass and Ladnun. They also created photos of car numbers and masked photos using Artificial Intelligence and then sequenced with over 200 pictures.Creating photos of the thieves helped the police in arresting three accused, namely Bhagirath Bawari, Ajay Singh Bawari and Yadaram Bawari, all residents of Uttar Pradesh. Two accused are yet to be caught.Yadav said that the gang had also stolen 4 kg gold in West Bengal earlier.

DMRC developing over 40 km of underground corridors in Phase 4 expansion

NEW DELHI. The DMRC is developing over 40 km of new underground corridors as part of its Phase 4 expansion, which constitutes about 50% of the total lines being developed across five different corridors, according to a senior DMRC official.

It is constructing 27 underground stations in Phase 4. The DMRC has already completed a small underground section from Janakpuri West to Krishna Park of about 2 km. This is an extension of the Magenta Line, the officer said.This is a major engineering feat since the underground corridors are passing through a variety of strata such as crowded residential and commercial areas in Sadar Bazar, Ajmal Khan Park, etc., he said.

Generally, DMRC constructs the underground metro stations using conventional cut-and-cover technology while the tunnels are built with the help of tunnel boring machines (TBM), the officer said.

However, a small section on the Aerocity-Tughlakabad corridor near Tughlakabad was built using the NATM technology (New Austrian Tunnelling Method). This method of tunnelling has also been used earlier by the DMRC with great success, the officer said. TBMs are especially useful for underground tunnelling work in congested urban areas. The DMRC has been using TBMs for its tunnelling work since Phase 1.

"While the Aerocity-Tughalakabad corridor will have about 19 km of underground corridor, the Janakpuri West-RK Ashram Marg corridor will have about 9 km of underground sections. The Inderlok-Indraprastha corridor will have over 11 km of underground lines. The Majlis Park - Maujpur and the Lajpat Nagar-Saket G Block sections will not have any underground stations," the official shared.

3 Days On, 5-Year-Old Still Stuck In Rajasthan Borewell, Piling Rig Deployed

A race against time ensued in Rajasthan's Dausa as authorities pressed a piling rig machine into action to dig a 150-feet-deep tunnel near a borewell where a five-year-old boy is trapped since December 9.Aryan fell into the open borewell on Monday evening while playing at a farm in Kalikhad village, while rescue operations were launched around 4 pm. Rescuers were deployed several earthmovers and tractors to dig a parallel hole, while also using rope and other equipment to attempt pulling out the child.

New Delhi. A race against time ensued in Rajasthan's Dausa as authorities pressed a piling rig machine into action to dig a 150-feet-deep tunnel near a borewell where a five-year-old boy is trapped since December 9.Aryan fell into the open borewell on Monday evening while playing at a farm in Kalikhad village, while rescue operations were launched around 4 pm. Rescuers were deployed several earthmovers and tractors to dig a parallel hole, while also using rope and other equipment to attempt pulling out the child. Oxygen is being supplied to the child through a pipe, whose condition is said to be stable, as per news agency ANI. On Tuesday night, an Xcmg 180 piling rig was deployed

at the rescue site.42 hours into the operation to rescue Aryan, a tunnel has been dug up till a depth of 70 feet amid temperature falling to a minimum 8 degrees Celsius. Earlier, the umbrella technique, also used during the Uttarkashi tunnel rescue operations in November 2023, did not succeed in retrieving the child.

National Disaster Response Force (NDRF), State Disaster Response Force (SDRF), and Civil Defence teams have also reached the spot," Dausa District Magistrate said.Meanwhile, Rajasthan minister and BJP leader Kirodi Lal Meena reached the site of operations where Aryan's condition is being monitored through a camera. "These incidents happen across the country. There is direction from the government but no law. A law should be made regarding covering borewells," he said.

In September, a two-year-old girl was rescued from a 35-foot open borewell in the Bandikui area of Dausa after 18 hours of rescue operations by NDRF and SDRF. The girl had been stuck at a depth of 28 feet and a similar approach was initiated to rescue her.

LG: Launch drive against illegal Bangladeshi immigrants

NEW DELHI. The L-G secretariat has written to the Chief Secretary and Police Commissioner asking for initiating "strict action" against illegal Bangladeshi immigrants residing in the national capital. The L-G secretariat has asked them to launch a special drive for two months to identify the immigrants and take strict action in a time-bound manner.A delegation of Ulemas and Muslim leaders from Dargah Hazrat Nizamuddin and Basti Hazrat Nizamuddin on Saturday expressed concern about the attacks on Hindu and other minority

communities in Bangladesh."Ulemas and Muslim residents have requested that illegal Bangladeshi infiltrators should neither be given houses on rent nor employment by any establishment. They have requested that their children should not be given admission in any government or private school. The Muslim leaders have also demanded removal of illegal infiltrators from roads, footpaths, parks and other government lands," the letter read.

"The L-G has desired that a two-month long special drive be launched for taking stringent and time-bound action and weekly report be sent to the secretariat regularly," it added.

Amid Atul Subhash Suicide Shocker, Supreme Court's Big Remark On Dowry Cases

New Delhi. Flagging a "growing tendency to misuse" laws protecting women from cruelty by their in-laws, the Supreme Court has said courts must exercise caution while deciding dowry harassment cases to prevent unnecessary harassment of innocent people.

The remarks are significant amid a nationwide debate on the misuse of dowry prohibition laws in the aftermath of a 34-year-old man's suicide in Bengaluru. Before he died by suicide, Atul Subhash recorded an 80-minute video in which he accused his estranged wife Nikita Singhania and her family of slapping multiple cases on him and his family to extort money from them. Atul Subhash also criticised the justice system in his 24-page suicide note.The Supreme Court's tough remarks came as it set aside a Telangana High Court order that had refused to strike down a dowry harassment case against a man, his parents and other family members. The court said an examination of the FIR shows that the wife's allegations were "vague and omnibus". It also said that some of the accused have no connection to the matter and "have been dragged into the web of crime without any rhyme or reason".

"A mere reference to the names of family members in a criminal case arising out of a matrimonial dispute, without specific allegations indicating their active involvement should be nipped in the bud," the court said. "It is a well-recognised fact, borne out of judicial experience, that there is often a tendency to implicate all the members of the husband's family when domestic disputes arise out of a matrimonial discord," it added.Noting that such sweeping accusations unsupported by concrete evidence cannot form the basis for prosecution, the bench of Justice BV Nagarathna and Justice N Kotiswar Singh said in its order, "Courts must exercise caution in such cases to prevent misuse of

legal provisions and the legal process and avoid unnecessary harassment of innocent family members."

The court said Section 498A of the Indian Penal Code, which punishes cruelty against a woman by her husband or his relatives, was incorporated into a law to ensure swift intervention by the State. With IPC replaced by Bharatiya Nyaya Sanhita, Section 80 now deals with dowry death and Section 85 with cruelty against a woman by her husband or his relatives.

The court noted that in recent years, there has been a notable rise in matrimonial disputes across the country, accompanied by growing discord and tension within the institution of marriage. "...consequently, there has been a growing tendency to misuse provisions like Section 498A of the IPC as a tool for unleashing personal vendetta against the husband and his family by a wife.Making vague and generalised allegations during matrimonial conflicts, if not scrutinized, will lead to the misuse of legal processes and an encouragement for use of arm twisting tactics by a wife and/or her family. Sometimes, recourse is taken to invoke Section 498A of the IPC against the husband and his family in order to seek compliance with the unreasonable demands of a wife," the order said.The court clarified that it was not stating that any woman who has suffered cruelty should remain silent.

NEWS BOX

Argentina's Milei touts US trade deal, says 'happy times' ahead

BUENOS AIRES. Argentine President Javier Milei promised Tuesday that inflation will soon be "little more than a bad memory" and vowed to pursue a free trade deal with the United States next year.

"Happy times are coming in Argentina," Milei said in a televised speech, in which he celebrated progress on monthly inflation which has dropped under his cost-slashing agenda, even as poverty has risen.

Milei said his government will seek a free trade agreement with the United States next year and added he will use his rotating presidency of the Mercosur economic bloc to boost te autonomy of its members to make deals.The self-proclaimed "anarcho-capitalist" also promised a tax reform that would reduce national taxation by 90 percent, and vowed to eliminate Argentina's strict currency controls so that people can "use the currency they want in their daily transactions."On Tuesday morning, Milei promised to cut taxes on exports from 2025 during a meeting with leaders of the Argentine Rural Society, the entity that brings together the large landowners of one of the main food producers in the world.

Since taking office in December, Milei's government has applied a drastic austerity program with the aim of eliminating the budget deficit and taming chronic inflation.It has slashed subsidies for transport, fuel and energy, even as thousands of public servants lost their jobs.While monthly inflation dropped to a three-year low in October, the annual figure of 236.7 percent in August remains one of the highest in the world.Poverty rose to 53 percent of the population in the first half of 2024 -- up 11.2 percentage points under Milei.

Want all parties to resolve disagreements peacefully: US on India-Bangladesh ties

WASHINGTON. The United States has said that it wants India and Bangladesh to resolve their differences peacefully.State Department spokesperson Matthew Miler said this at his daily news conference on Tuesday.

"We want to see all parties resolve their disagreements peacefully," Miler said, responding to a question on the recent visit of India's foreign secretary to Bangladesh.During his visit early this week, Foreign Secretary Vikram Misri conveyed New Delhi's "concerns" over the safety and security of minorities in Bangladesh."I have underlined India's desire to work closely with the interim government of Bangladesh. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities," Misri told reporters in Dhaka at the end of his visit.

Humanitarian aid to North Gaza mostly blocked for last two months: UN

UNITED NATIONS. Humanitarian aid to North Gaza, where Israel launched a ground offensive on Oct. 6, has largely been blocked for the past 66 days, the United Nations said Tuesday. That has left between 65,000 and 75,000 Palestinians without access to food, water, electricity or health care, according to the world body.In the north, Israel has continued its siege on Beit Lahiya, Beit Hanoun and Jabaliya with Palestinians living there largely denied aid, the U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, known as OCHA, said. Recently, it said, about 5,500 people were forcibly displaced from three schools in Beit Lahiya to Gaza City.Adding to the food crisis, only four U.N.-supported bakeries are currently operating throughout the Gaza Strip, all of them in Gaza City, OCHA said.Sigrid Kaag, the senior U.N. humanitarian and reconstruction coordinator for Gaza, told reporters after briefing the U.N. Security Council behind closed doors Tuesday afternoon that civilians trying to survive in Gaza face an "utterly devastating situation."She pointed to the breakdown in law and order and looting that has exacerbated a very dire situation and left the U.N. and many aid

organizations unable to deliver food and other humanitarian essentials to hundreds of thousands of Palestinians in need.Kaag said she and other U.N. officials keep repeatedly asking Israel for access for convoys to North Gaza and elsewhere, to allow in commercial goods, to reopen the Rafah crossing from Egypt in the south, and to approve dual-use items.Israel's U.N. Mission said it had no comment on Kaag's remarks.The U.N. has established the logistics for an operation across Gaza, she said, but there is no substitute for political will that humanitarians don't possess."Member states possess it," Kaag said. And this is what she urged Security Council members of and keeps urging the broader international community to press for — the political will to address Gaza's worsening humanitarian crisis.

Wildfire in Malibu destroys homes, sends thousands fleeing

MALIBU. A ferocious fire tore through Malibu on Tuesday, destroying at least seven homes in one of California's most desirable areas, and forcing thousands to evacuate.Multimillion-dollar properties, some owned by Hollywood celebrities, were in the path of the blaze, which exploded late Monday, fanned by powerful winds and tinder-dry brush.Firefighters were unable to get a foothold in the steep canyons that surround the tony enclave near Los Angeles, where towering flames were devouring hillsides, blanketing the air in choking smoke."We were completely surrounded," resident Alec Gellis told broadcaster KTLA."It was like 11 pm. We hear people screaming. I walk outside -- the sky is bright red."Within 45 minutes, it's coming down the hillside and then within an hour after that, we're fully surrounded, houses burning down on one side. Ridge is burning on the other side, mountains all around us.

"It got pretty scary at one point."

Door-to-door response

Law enforcement officers have ordered thousands of people to leave their homes, with many more told to be ready to flee if conditions worsen."There are approximately 20,000 affected citizens under evacuation orders and evacuation warnings," said Captain Jennifer Seeto of Los Angeles County Sheriff."Fire can be extremely unpredictable, and we highly encourage residents in the fire areas to be prepared. Have a plan and heed our evacuation warnings and orders."Deputies had gone door-to-door urging people to get out as the flames began to spread on Monday night.Malibu Mayor Doug Stewart said the fire had been "traumatic," but vowed that the city and its people would not be defeated."That's the way it is here in Malibu. It burns, it comes back, and we're resilient and strong."Actor Dick Van Dyke, who celebrates his 99th birthday on Friday, posted on Facebook that he and his wife had fled their Malibu home."Arlene and I have safely evacuated with our animals except for (a cat that) escaped as we were leaving. We're praying he'll be OK and that our community... will survive these

terrible fires," he wrote.The city, which sits a short drive from Hollywood's major studios, has been home to some of the biggest names in show business, with present and former residents including Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston and Cher.AirdropsBy Tuesday evening, the so-called Franklin Fire had swelled to more than 2,800 acres (1,150 hectares) and was still raging out of control, fanned by powerful seasonal winds that have led to forecasters hoisting a "red flag warning."Los Angeles County fire chief Anthony Marrone said 1,500 firefighters were continuing to battle the flames, with the help of aircraft that were dumping thousands of gallons (litres) of water and retardant from the air.Aerial reconnaissance showed an unconfirmed number of homes damaged and destroyed, he told reporters."The entire fire area remains under threat," he added.Tens of thousandsof people across southern California had their electricity cut off. Utilities frequently de-energize lines ahead of windy days to reduce the fire risk from downed power lines.California Governor Gavin Newsom said the state had already secured a Fire Management Assistance Grant from the Federal Emergency Management Agency to assist with the response."Fire officials and first responders are working relentlessly to protect lives and property from the Franklin Fire," Newsom said in a statement.Wildfires are a feature of life in California and other parts of the US West, and are often exacerbated at this time of year by Santa Ana winds, which blow dry desert air from the interior.

World's Unluckiest Travellers: The Harrowing Stories Of The Winners

World. A travel insurance company has revealed the winners of the World's Unluckiest Traveller awards for 2024, featuring a collection of frightening and bizarre travel misadventures. This contest of stories of travel nightmares received nearly 500 entries from across North America. After weeks of voting, a winner has emerged.Julie S was named the World's Unluckiest Traveller and won $10,000. Her story, "From Bodybag to Skydiving," recounts a trip to Phoenix with her friend Sam. After a night of mishaps, Sam had to be transported in a body bag due to space constraints but recovered and insisted on skydiving.The runner-up, Jennifer G, shared her story "MexiNO!" about her kidney failure diagnosis and decision to travel before starting dialysis. Her vacation in Mexico,

meant to escape Wisconsin winter, turned disastrous with no beach, a closed pool, and a mouldy, bedbug-infested room without water. She spent the night in the bathtub and won $5,000.In third place, "Don't Look Up While Walking" shares a cautionary tale of visiting Maho Beach in Saint Martin to see planes flying low over the neighbouring Princess Juliana Airport. The third-place winner received $3,000. Fourth place went to "A Trip That Took Many Years Off My Life," about a mother and her pre-teen son visiting southern Italy for the first time, where the child ended up in the hospital with a bacterial infection requiring seven days of ultrasounds. The fourth-place winner received a set of Victorinox luggage.According to the web portal of the company, Anna F received the fourth highest votes (1,082 votes) and won the fourth-place prize, a new set of Victorinox luggage (valued at $1,900). Our thanks to Victorinox for donating this amazing prize. And, Sweepstakes Winner Melanie A was a randomly selected voter and won the sweepstakes prize, a GoPro action camera and kit (valued at $450).

South Korea's former defence chief attempted to kill self after being arrested in martial law case

SEOUL. South Korea's previous defense minister was stopped from attempting suicide while in detention over last week's martial law, officials said, as police were reported to be raiding President Yoon Suk Yeol's office Wednesday in their intensifying investigation.

The main liberal opposition Democratic Party also plans to submit a new motion to impeach Yoon for his Dec. 3 declaration that imposed martial law.Yoon's ill-conceived power grab has paralyzed South Korean politics, frozen its foreign policy, and rattled financial markets, greatly reducing his chances of completing his five-year term and casting a turbulent shadow over one of Asia's most robust democracies.

Shin Yong Hae, commissioner general of of the Korea Correctional Service, told lawmakers Wednesday that Kim tried to kill himself at a detention center in Seoul. He said that Kim's suicide attempt failed after center officials stopped him and that he is in a stable condition now.At the same parliament committee

meeting, Justice Minister Park Sung Jae confirmed Kim's failed suicide attempt.Kim was arrested earlier Wednesday after a Seoul court approved a warrant for him on allegations of playing a key role in a rebellion and committing abuse of power. Kim became the first person formally arrested over the Dec. 3 martial law decree.Later in the day, National Police Agency Commissioner General Cho Ji Ho and Kim Bong-sik, head of the metropolitan police agency of the capital, Seoul, were detained over their actions during martial law. They are being investigated for their roles in deploying police forces to the National Assembly to block lawmakers from voting to lift Yoon's martial law decree.South Korean police also searched Yoon's office Wednesday over his martial law decree, Yonhap news agency reported. Other South Korean media also carried similar reports. but Yoon's office and police have not immediately confirmed the search.

The country's main law enforcement institutions are focusing on finding whether Yoon and others involved in imposing martial law committed the crime of rebellion.Yoon survived an impeachment attempt last Saturday when the ruling party boycotted the vote, but the Democratic Party is aiming to put the new motion to a vote on Saturday.

Bangladesh acknowledges attacks on minorities; says 88 cases filed, 70 arrested so far

World. Bangladesh has confirmed 88 cases of communal violence targeting minorities, primarily Hindus, since the departure of former Prime Minister Sheikh Hasina in August. Interim government head Muhammad Yunus' press secretary, Shafiqul Alam, revealed the figures on Tuesday, adding that 70 individuals have been arrested in connection with the attacks, as reported by news agency PTI.

The announcement follows a visit by Indian Foreign Secretary Vikram Misri, who raised concerns about the safety and welfare of minorities in Bangladesh during meetings with the country's leadership. Misri expressed India's apprehensions over the increasing number of attacks, urging for enhanced protection of vulnerable communities.He added that India seeks a positive and mutually beneficial relationship with Bangladesh, emphasising the desire for a constructive and people-centric partnership. He expressed India's willingness to work closely with the current interim government in Bangladesh to achieve these goals.

Cases and arrests

Alam told reporters that 88 cases had been registered between August 5 and October 22. The incidents reportedly occurred across various regions, including Sunamganj in the northeast and Gazipur in central Bangladesh.

"The number of cases and arrests is likely to increase as new incidents of violence have been reported in Sunamganj, Gazipur, and other areas," Alam stated,

according to PTI.Authorities believe that not all attacks were faith-based. Alam suggested that some victims were members or affiliates of Sheikh Hasina's former ruling party, the Awami League, and may have been targeted due to political affiliations or personal disputes."Some attacks targeted individuals who were former members of the ruling party or were the result of personal disputes. Nevertheless, since violence occurred, the police are taking appropriate action," he said.

Pattern of attacks

While the Bangladeshi government has maintained that many incidents were not driven by religious intolerance, the pattern of violence against minorities has raised alarm. Hindus, who comprise a small percentage of Bangladesh's population, have historically faced sporadic communal violence, often coinciding with political transitions.Alam also disclosed that details of incidents occurring after October 22 will be shared in a subsequent report, hinting at the possibility of additional cases coming to light.

Regional and international concerns

The confirmation of these incidents has intensified scrutiny from India. India has previously voiced concerns over the treatment of minorities in Bangladesh, particularly during periods of political instability.

The Bangladeshi government has reassured both domestic and international stakeholders of its commitment to protecting minorities and maintaining law and order. Authorities have vowed to investigate each incident and bring perpetrators to justice.

Man accused of killing UnitedHealthcare's CEO shouts on way into courthouse, fights extradition

ALTOONA. The man charged with murder in the killing of the CEO of UnitedHealthcare made it clear he wasn't going to make things easy on authorities, shouting unintelligibly and writhing in the grip of sheriff's deputies as he was led into court and then objecting to being brought to New York to face trial.The displays of resistance Tuesday weren't expected to significantly delay legal proceedings for Luigi Nicholas Mangione, who was charged in last week's Manhattan killing of Brian Thompson, the leader of the United States' largest medical insurance company. Little new information has come out about possible motivation, though writings found in Mangione's possession hinted at a vague hatred of corporate greed.In his first public words since he was arrested at a McDonald's in Pennsylvania after a five-day search, the 26-year-old Ivy League graduate from a prominent Maryland real estate family emerged from a patrol car shouting about an "insult to the intelligence of the American people" while deputies pushed him inside a courthouse.A law enforcement bulletin obtained by The Associated Press said that at the time of his arrest, Mangione was carrying a handwritten document expressing anger with what he called "parasitic" health insurance companies and a disdain for corporate greed and power.He wrote that the U.S. has the most expensive health care system in the world and that profits of major corporations continue to rise while "our life expectancy" does not, according to the bulletin.Mangione remained jailed in Pennsylvania, where he was initially charged with possession of an unlicensed firearm, forgery and providing false identification to police.Manhattan prosecutors were beginning to take steps to bring Mangione to New York, but at a brief hearing Tuesday, defense lawyer Thomas Dickey said his client will not waive extradition and instead wants a hearing on the issue. Mangione was denied bail after

prosecutors said he was too dangerous to be released.He mostly stared straight ahead at the hearing, occasionally looking at papers, rocking in his chair or looking back at the gallery."You can't rush to judgment in this case or any case," Dickey said afterward. "He's presumed innocent. Let's not forget that."Mangione was arrested in Altoona, Pennsylvania, about 230 miles (about 370 kilometers) west of New York City, after a McDonald's customer recognized him and notified an employee, authorities said.

New York police officials have said Mangione was carrying a gun like the one used to kill Thompson and the same fake ID the suspected shooter had used to check into a New York hostel, along with a passport and other fraudulent IDs.A law enforcement official who wasn't authorized to discuss the investigation publicly and spoke with The Associated Press on condition of anonymity said a three-page, handwritten document found with Mangione included a line in which he claimed to have acted alone.

"To the Feds, I'll keep this short, because I do respect what you do for our country. To save you a lengthy investigation, I state plainly that I wasn't working with anyone," the document said, according to the official.

Thompson, 50, was killed Dec. 4 as he walked alone to a Manhattan hotel for an investor conference. From surveillance video, New York investigators determined the shooter quickly fled the city, likely by bus.

Kylian Mbappe injured Ancelotti hopes no serious issue with Real Madrid star

Real Madrid boss Carlo Ancelotti is hoping that Kylian Mbappe's injury he sustained in the UEFA Champions League clash against Atalanta on Tuesday, December 10. Mbappe was in fine form during the match before the injury forced him off the field.

New Delhi. Carlo Ancelotti expressed hope that Kylian Mbappe's injury is not serious after the forward played a pivotal role in Real Madrid's thrilling 3-2 Champions League win against Atalanta on Tuesday. Mbappe, under scrutiny for a slow start to life at Real following his free transfer from Paris Saint-Germain, delivered a standout performance before being forced off in the first half.The French star opened the scoring in the 10th minute with a sharp finish and caused constant problems for Atalanta's defence with his electrifying runs. However, his night was cut short in the 35th minute when he went down and signaled for a substitution, making way for Rodrygo.

Vinicius Jr, returning to action after a two-week absence due to a muscle injury, had a subdued performance overall but seized his opportunity in the 56th minute. The Brazilian slotted home a rebound to restore Real's lead after Charles De Ketelaere had levelled for Atalanta with a penalty just before halftime.Jude Bellingham extended the advantage three minutes later with a composed finish following a swift counterattack, putting the reigning champions in a commanding position. Despite Ademola Lookman pulling one back in the 65th minute to set up a nervy finale, Real Madrid held firm.Thibaut Courtois was instrumental in preserving the victory, making a series of crucial saves as Atalanta piled on the pressure late in the game. The win moves Real Madrid to nine points in the group standings, keeping them in the hunt for a top-eight finish and automatic progression to the Round of 16.Ancelotti said that Mbappe suffered a lower pelvis discomfort and wasn't able to sprint."Mbappe has suffered an overload, an ischial (lower pelvis) discomfort," Ancelotti told Movistar Plus.

"It doesn't seem serious, but we'll see tomorrow after the exams. He couldn't sprint, it was bothering him a bit and we decided to make the substitution."

Very important win

Ancelotti said that it was a very important win for his side as the race heats up for the top 8 spot. While the Madrid boss admitted that an automatic qualification spot will be difficult, he is looking forward to the next 2 games to see how many points they can pick up."It's a very important victory, not everyone wins here," Ancelotti said."We suffered and fought hard, there is no Champions League without suffering. They were pushing, but we started well in the second half. We are very happy. It was a win that is very good for us, not just for the points, but to build confidence."It's still difficult to finish in the top eight, but we have two games to pick up points. Let's see what happens."

NEWS BOX

Josh Hazlewood in, Scott Boland out for Gabba Test Brett Lee delivers verdict

New Delhi. Brett Lee has said that if Josh Hazlewood is fit for the Gabba Test against India then he should slot back into the Australia lineup instead of Scott Boland. Hazlewood had missed the Adelaide Test win due to a side strain as Boland came in to replace him. During the match, the pacer, who was playing his first Test in almost 18 months, picked up 5 wickets across both innings. Boland's efforts proved to be crucial as Australia won the match by 10 wickets to level the series. The Australian medical staff will now examine Hazlewood and see how he will perform during the main training session on Thursday, December 12, before making a call. Lee said that it would be tough to drop Boland, but if Hazlewood is fit then he would come back into the side.

"Look it's a tough one but you'd have to go back on form and what Josh Hazlewood has done," Lee said on Fox Cricket. "For me

personally, Josh Hazlewood slips straight back in. If he's fully fit he gets the new ball or at least is definitely back in the team."

Boland the new MacGill?

Lee would draw parallels between Boland and Stuart MacGill's career. MacGill was the backup to the great Shane Warne during his career and Lee felt that Boland is a bit unfortunate he is part of an era that has Pat Cummins, Mitchell Starc and Hazlewood in it."It's unfortunate for Scott Boland because when he's had his opportunity he's nailed it," Lee said."I look at Scott Boland and I probably think he's a bit like MacGill playing in the Warne era. MacGill took 200 Test wickets bowling when Shane Warne was either injured or out for other reasons. So he was a quality, quality bowler."

"Boland could be in any team around the world. Any playing nation. But unfortunately, when you've got Starc, Cummins and Hazlewood, they're still doing the business and they're in his way at the moment. It's nothing against Boland because he's bowled the house down."

Rohit Sharma should sacrifice his position for India's future: Cheteshwar Pujara

IND vs AUS, 3rd Test: Rohit Sharma should continue to bat in the middle-order feels Cheteshwar Pujara. Pujara wants KL Rahul and Yashasvi Jaiswal to continue in the top order keeping India's future in mind.

New Delhi. India captain Rohit Sharma should bat in the middle order in the Brisbane Test match, said Cheteshwar Pujara. Speaking ahead of the 3rd Test, set to start on December 14, Pujara argued that Rohit should sacrifice his position thinking about the future of Indian cricket.Sharma, who had skipped the first Test match of the Border-Gavaskar Trophy 2024/25 had a terrible outing in the pink ball Test match at Adelaide, scoring a total of 9 runs across two innings. Rohit got consistently troubled on his off and middle stumps and lost his wicket to Scott Boland and Pat Cummins.Speaking on ESPNcricinfo, Pujara asked Rohit to work on his technique and argued that a bigger front-foot stride might help him in Australia. Pujara also advocated that Rohit should sacrifice his opener's spot for KL Rahul and Yashasvi Jaiswal, thinking about the future of the Indian team."He has not scored a lot of runs against New Zealand and he did not start well in Australia, so there is a bit of pressure on him to perform. But someone like him who knows his game will just have to be more positive, and work a bit more on his footwork. If he has a slightly bigger stride, it will help him," Cheteshwar Pujara said in a video by ESPNcricinfo in the build-up to the Brisbane Test match.

Border-Gavaskar Trophy: Full Coverage

"The stump line has been troubling him a lot. He has been getting out bowled and LBW, which is a bit of concern for him. That's the line he will have to work on in the nets, because in the balls outside off stump, he is looking more comfortable. I think he should continue to bat at No.6. We are looking at India's future, KL Rahul and Yashasvi Jaiswal. They batted really well in the 1st Test match, Shubman also is likely to bat at No.3. We should think about the long term and that's why I think that Rohit should continue to bat at No.6," he further added.KL Rahul and Yashasvi Jaiswal were the stars of India's first Test match of the series, hitting 200 runs between them. That allowed India to dominate Australia in Perth and secure a massive 295-run win. In the second Test match however, India were drubbed by Australia, as they lost the match by 10 wickets, due to twin batting failures.The third Test match of the series will be played at the iconic Gabba. The game will start at 5:50 AM IST on 14 December.

AUS vs IND: Can Rishabh Pant repeat 2021 Gabba heroics as India eye comeback

New Delhi. India wicketkeeper-batter Rishabh Pant will return to the very place which made him the star that he's today, as India travel to Brisbane for the third Test of the ongoing Border-Gavaskar Trophy. Rohit Sharma's men have been left shaken by a ten-wicket loss in Adelaide as their horror show against the pink ball continued. Pant has also looked far from his best in the series so far, having scored just 87 runs from two matches.The second Test in Adelaide saw Pant play some audacious shots in the second innings as he came down the track against the seamers despite India losing wickets from the other end. However, Australia are yet to see the vintage Pant back who sealed his spot in the Indian Test team on the back two heroic knocks on the last tour.Sydney was the first place which witnessed a new emerging star in Indian cricket in 2021 as Pant tore apart Nathan Lyon smashing him to all corners of the historic venue. Courtesy of his blistering 97 (118), India came mighty close to chasing down the massive target of 407 but eventually had to settle for a draw.However, Pant accomplished in the very next Test in Brisbane what he couldn't in Sydney, as his unbeaten 89* helped India register their highest run chase in SENA (South Africa, England, New Zealand and Australia)

countries of 328. The victory held even greater significance as it ended Australia's 32-year-long unbeaten streak at the Gabba and also helped India win their second successive series down under.The series rose Pant's stocks in world cricket like no other, as his name became synonymous with India's greatest Test series victory in overseas conditions. His career also skyrocketed post the Gabba heroics as he began being touted as the best wicketkeeper batter in the world. Since the 2020-21 tour of Australia, Pant has scored 1966 runs from 27 matches at an average of 44.68 and a strike rate of 77.61 since the last Australia tour.Rishabh Pant hungry for more after Test comebackPant recently made a sensational comeback to Test cricket after 21 months with a century against Bangladesh in Chennai followed by knocks of 99, 60 and 64 against New Zealand.

SA vs PAK: Linde, Miller star as South Africa down Pakistan in 1st T20I

New Delhi. George Linde's sensational all-round performance powered South Africa to an 11-run victory over Pakistan in the first T20I at Kingsmead, Durban. Returning to the international stage after three years, Linde delivered a stunning 24-ball 48 with the bat and followed it up with figures of 4-21. His heroics secured him the Player-of-the-Match award, despite narrowly missing a hat-trick in the penultimate over after a successful review denied him the feat.

Pakistan's chase faltered despite Mohammad Rizwan's late surge. The captain, who initially struggled with a sluggish 36 off 44 balls, redeemed himself by finishing with 74 off 62. His valiant effort, however, fell short as Pakistan could not recover from a slow middle phase and an inexperienced middle order.

SA vs PAK 1st T20I Highlights

South Africa fielded a largely second-string side but found inspiration in David Miller's

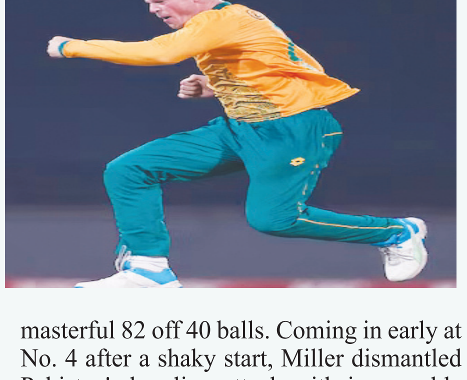

masterful 82 off 40 balls. Coming in early at No. 4 after a shaky start, Miller dismantled Pakistan's bowling attack with impeccable timing and brute power. His assault on spinners Sufiyan Muqeem and Abrar Ahmed was particularly destructive, including three consecutive sixes off Abrar in the 10th over. Miller's dominance propelled South Africa to 163, despite a late collapse triggered by Pakistan's bowlers.Pakistan's chase began promisingly with Saim Ayub providing a brisk start, but the loss of Babar Azam for a duck and a tight middle-over spell by South Africa turned the tide. Linde and his fellow bowlers stifled Pakistan's scoring while picking up regular wickets, leaving them needing an improbable 19 runs off the final over. Despite a dramatic 17th over that went for 24 runs, South Africa held their nerve, with 18-year-old Kwena Maphaka redeeming himself in the last over by dismissing Rizwan to seal the win.

WI vs BAN: Jayden Seales, Brandon King help hosts clinch series with clinical win

WI vs BAN: Hosts West Indies beat Bangladesh in the second ODI of the series to take an unassailable lead of 2-0. Jayden Seales won the player of the match award with a sensational four-wicket haul.

New Delhi. The West Indies won a One-Day international series against Bangladesh for the first time in 10 years. Playing the 2nd ODI of the series on Tuesday, 10 December, the hosts put in a clinical performance, first restricting Bangladesh to 227 and then chasing it down in just 37 overs with 7 wickets in hand.The dominating victory helped Windies clinch the series with a game to spare as they look to rebuild their ODI side after missing out on the ODI World Cup 2023 spot.It's great to see the bowlers bounce back the way they did," captain Shai Hope said. "Gotta tick boxes and keep improving. We were clinical. We've been struggling to win series at home (so) hope to finish 3-0 now."On the same pitch where the West Indies won by five wickets on Sunday, the par score was 300. But fast bowler Jayden Seales undercut Bangladesh with three wickets in the first powerplay. Seales returned to bag Mahmudullah for 62 in the 45th over and finish with a match-deciding 4-22 in nine overs.The chase was almost a formality. Brandon King and Evin Lewis opened with a 109-run partnership in 21 overs. King led with 82 and Lewis and Keacy Carty were out just short of half-centuries.Bangladesh was 115-7 in the 26th over when Tanzim Hasan Sakib joined Mahmudullah and they rescued the innings. While they were batting with increasing ambition, Bangladesh could dream of 270-280.Mahmudullah reached fifty off 84 balls, and Tanzim was closing on his when he was out caught and bowled by off-spinner Roston Chase. Tanzim had 45 off 62 and the partnership reached 92 runs from 106 balls. Mahmudullah was out in the next over for 62 off 92.In the chase, Lewis was slower to get in a groove than King and was dropped on 28. King and Lewis were both hit on the body in the 40s while attempting pulls at Nahid Rana.

UEFA Champions League: Real Madrid snap losing run, Liverpool remain unbeaten

Real Madrid halted their losing streak with a thrilling 3-2 victory over Atalanta, while Liverpool continued their winning run by defeating Girona. Bayern Munich also secured a commanding win over Shakhtar Donetsk.

New Delhi. Real Madrid ended their two-game losing streak in the Champions League with a hard-fought 3-2 victory against Serie A leaders Atalanta, while Liverpool maintained their winning run in the competition by downing Girona on Tuesday, December 10. Bayern Munich, PSG, Bayern Leverkusen, Brest and Aston Villa also secured wins on Tuesday.

Kylian Mbappe opened the scoring for Los Blancos in the 10th minute with a precise finish but was forced off shortly after due to injury. Charles De Ketelaere levelled the match with a penalty just before halftime, awarded after Aurelien Tchouameni tripped Sead Kolasinac. In the second half, Real Madrid regained control as Vinicius Jr capitalised on a rebound to put the holders ahead in the 56th minute. Moments later, Jude Bellingham extended the lead with a clinical counterattack. Atalanta pulled one back through Ademola Lookman in the 65th minute, but Thibaut Courtois delivered a masterclass in goal to secure Madrid's three points.Real Madrid now sit 18th in the 36-team table with nine points, while Atalanta remain ninth on 11 points, both vying for a spot in the top eight for direct qualification to the last 16.Liverpool Maintain Perfect Record with Girona VictoryLiverpool continued their flawless Champions League

campaign, grinding out a 1-0 win at Girona. Mohamed Salah converted a penalty in the 63rd minute after Luis Diaz was fouled, sealing Liverpool's sixth win in as many matches.Girona put up a resilient fight, particularly in the first half, forcing several saves from Liverpool's goalkeeper Alisson. The hosts, however, couldn't capitalise on their counterattacking opportunities, leaving them rooted in 30th place with just three points. Liverpool remain atop the standings with 18 points, five clear of second-placed Inter Milan.

Bayern Munich Thrash Shakhtar Donetsk

Bayern Munich secured their first away win of the Champions League season with a commanding 5-1 triumph over Shakhtar Donetsk. Shakhtar struck early through Kevin in the fifth minute, but Konrad Laimer equalised six minutes later. Thomas Mueller's goal on the stroke of halftime gave Bayern the lead.Michael Olise shone in the second half, converting a penalty in the 70th minute before adding another in stoppage time. Jamal Musiala also chipped in with a late goal, completing a dominant performance for the German giants. The win propels Bayern into eighth place with 12 points, while Shakhtar languish in 27th with just four.

Shraddha Kapoor

Spills The Beans On Her Appearance In Varun Dhawan's Bhediya 2

Shraddha Kapoor, known for her humble attitude and strong acting skills is currently attending the ongoing Red Sea International Film Festival 2024 in Saudi Arabia. Amidst this, she engaged in a candid conversation where she revealed some exciting details about her upcoming projects.In an interview with Pinkvilla, Shraddha Kapoor opened up about her upcoming projects. The actress was asked if she would be a part of Varun Dhawan's Bhediya 2. For context, in a pre-credit scene of her last film, Stree 2, Bhaskar (played by Dhawan) asks another character in the movie, Jana (played by Abhishek Banerjee) to set him up with Stree (played by Shraddha). Although Jana declines, Bhaskar continues to plead with him. This made the audience curious whether Shraddha would be part of Bhediya 2.

Shraddha said, "Only time will tell if any more cameos of mine come up in any of the other Maddock films. I don't know yet." The actress also mentioned that she will soon announce her upcoming projects. She said, "Very soon, I will share the films that I will be doing, which I will be shooting for next year."

In the same conversation, Shraddha was also asked about her opinion of Kiran Rao's directorial Laapataa Ladies being India's entry for the Oscars 2025. Talking about the same, the actress, heaped praises on the film and admitted that she loved it. She said, "It's so amazing to see that good films are getting their due and appreciation." The social drama also stars Nitanshi Goel, Pratibha Ranta, Ravi Kishan, and Sparsh Shrivastav, among others, in key roles.

She further expressed, "I feel any film that gets its due and recognition is a great feeling, and it only sets a standard. It only inspires more people to be true to the craft," adding, "People will know that acha thik hai, my focus should be on doing good work or making good films, and that's it. If I do that, people will be watching."Meanwhile, Shraddha's last film Stree 2 became the highest-grossing film of all time after collecting nearly Rs 580 crore at the box office.

Kareena on Laal Singh Chadha

Rupa has done more for me than what Singham can do

Actor Kareena Kapoor Khan, who played Rupa in Laal Singh Chadha, spoke about her character in the film while comparing it to her role in Singham Again. The actor also mentioned how Aamir Khan was "shattered" after their 2022 film tanked at the box office. Kareena was a part of a roundtable discussion for The Hollywood Reporter India, also joined by Vicky Kaushal, Shabana Azmi, Rajkummar Rao, Pratik Gandhi, Kani Kusruti, and Anna Ben.

Kareena Kapoor called Laal Singh Chadha "a beautiful and honest film". "You have such stalwarts like Aamir who believed in that film. He was shattered. He met me somewhere and said, 'Picture nahi chali hamari na, tu baat toh karegi na mujhse?' (Our movie didn't work. You will still talk to me, right?).' I said, 'We are actors, I am the most proud that you gave me Rupa [her character],'" she said.

> Kareena Kapoor Khan reflected on the emotional aftermath of Laal Singh Chadha's box office failure. The actor further highlighted her character, Rupa, sharing that it has done more for her than Singham Again has.

Emphasising how proud she is of the character she played in the film, Kareena said, "I feel what Rupa has done more for me than what a Singham [Again] can do."

Shabana Azmi, who participated in the roundtable, asked Kareena the reason behind her statement. The Chameli actor said, "The character that Advait [Chandan] wrote was so beautiful, and I loved playing it. There is so much to think of. We didn't make that movie thinking that it would make Rs 500 crore. It was just made with all heart. Everybody gave their best."

Laal Singh Chadha was released amid a lot of backlash. Though the film garnered critical appreciation, it failed to perform at the box office by earning a lifetime collection of Rs 61.36 crore in India and Rs 133.50 crore worldwide.

Zeenat Aman reveals how Khaike Paan became a surprise hit after it was rejected

Veteran actor Zeenat Aman recently shared a delightful anecdote about one of the most iconic songs in Bollywood history, Khaike Paan Banaraswala, from the film Don. The song, which has remained etched in the hearts of fans for decades, was not originally meant to be part of the film Banarasi Babu, as Zeenat reveals in her Instagram post.

According to Zeenat's post, the song was initially created for Dev Anand's Banarasi Babu, but it was rejected for being "too frivolous." However, Director Chandra Barot, who had completed shooting his action-thriller Don, starring Amitabh Bachchan in a double role, realised that the film needed a lighter moment to balance the intense plot. As a result, the cast and crew returned to Mehboob Studio for an additional shoot to film the song, which went on to become a surprising hit.

Zeenat recounted how the number was brought to life with Kishore Kumar's infectious vocals, a playful beat, and an energetic performance by Amitabh Bachchan, which set the stage for one of the most memorable tracks in Indian cinema. "I remember most acutely the quantity of paan that Mr Bachchan consumed and the sheer energy he brought to set," Zeenat wrote, recalling the fun-filled days of shooting.

She also noted the physical challenge of shooting the sequence. "He was one of just two male leads at the time who was considerably taller than my 5 feet 8 inches," she mentioned, adding that it was a rare instance where the director had her dancing in "proper" high heels for the song.

Khaike Paan Banaraswala quickly became a national sensation, with media reports suggesting that moviegoers were returning to cinemas time and again just to enjoy this one song. The track's playful lyrics, catchy rhythm, and vibrant performances made it a household anthem. Zeenat also reflected on how the song was later reenacted by Shah Rukh Khan and Priyanka Chopra in the 2006 remake of Don, directed by Farhan Akhtar. She appreciated how their version of the number was equally upbeat and catchy, echoing the magic that made the original so special.

SRK impressed by Baby John distributor's cut, predicts it could be as big as Jawan

Shah Rukh Khan, impressed by Baby John's distributor's cut, predicted it could match the success of Jawan, highlighting its potential as a box office hit.

Shah Rukh Khan, who delivered a massive blockbuster with Jawan in 2023, has reportedly watched the distributor's cut of Varun Dhawan's Baby John. According to insiders, SRK was highly impressed by what he saw, drawing comparisons between the potential success of Baby John and Jawan.

Shah Rukh Khan, known for his sharp eye for cinematic excellence, believes Baby John has all the ingredients to become a box office sensation. Filmmaker Atlee, who worked with SRK in Jawan, made him watch the director's cut of Baby John. For the unversed, he helmed the Tamil version of the film, Theri, starring Thalapathy Vijay.

After praising the trailer, Shah Rukh Khan was mighty impressed with Baby John. "SRK watched the distributor's cut of Baby John and was very impressed. He believes the film will be as big as Jawan. SRK even called Kalees [director] and praised him for his work in the film," a source close to the production told India Today Digital. An insider revealed that the film also boasts a powerful performance by Varun, whose portrayal of the titular character is expected to leave a lasting impact.

Baby John stars Varun Dhawan, alongside Keerthy Suresh, Wamiqa Gabbi, and Jackie Shroff. The film is expected to be a gripping narrative with a blend of action, drama, and emotion. It releases on December 25.